चिंतन

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जरूरी

देश में भ्रष्टाचार की जड़ें अभी भी गहरी हैं। आजादी के बाद से ही नौकरशाही व राजनीतिक सत्ता में भ्रष्टाचार पल्लवित-पोषित होता है। वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के संकल्प के साथ सत्ता में आई, 76वें स्वतंत्र दिवस (2022) पर भी लाल किले की प्राचीर से पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित एक्शन का आह्वान किया। इस आह्वान से साफ था कि उनके आठ वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर अपेक्षा के अनुरूप लगाम नहीं लग सकी। वर्ष 2023 में आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों मंन से 93वें स्थान पर था। अब वर्ष 2024 के सितंबर में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ की गईं और इसके बाद दिल्ली के स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें मिलीं। 2023 में सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कुल 74,203 शिकायतें मिलीं, ये वो हैं, जो रिपोर्टेड हैं, करप्शन के अनेक मामले प्रकाश में ही नहीं आते। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकारी सख्ती व कानूनी सख्ती के बावजूद भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सका है। यह सरकार की नीतियों व शासन-प्रशासन की सफलता पर प्रश्नचिन्ह है। कोयला मंत्रालय में भ्रष्टाचार की 4,420, श्रम मंत्रालय में 3,217, पेट्रोलियम मंत्रालय में 2,749 तथा गृह मंत्रालय (दिल्ली पुलिस को छोड़कर) में 2,309 शिकायतें मिलीं। रक्षा मंत्रालय में 1,861 शिकायतें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 1,828 शिकायतें, दूरसंचार में 1,457 शिकायतें और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ 1,205 शिकायतें प्राप्त हुईं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में 960, ऊर्जा मंत्रालय में 930, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण में 929 और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में 889 शिकायतें थीं। आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग सभी मंत्रालयों में भ्रष्टाचार के मामले हैं। देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुए, कठोर कानून बने, गवर्नेंस के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाए गए, पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहे हैं। देश के सरकारी सिस्टम में संस्थागत (नीतिगत) और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर कदाचार हैं। निजी स्तर पर भी कंपनियों, उत्पादों से लेकर विनिर्माण तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के लिए राजनीति व नौकरशाही की मिलीभगत, सरकार में नीतिगत व सिस्टमैटिक पारदर्शिता की कमी, लालफीताशाही के चलते प्रशासनिक देरी, और अप्रभावी कानूनी ढांचे, राजनीतिक हस्तक्षेप, वेतन विसंगतियां, पदासीन लोगों में जिम्मेदारी का अभाव, राष्ट्र प्रथम की भावना व सार्वजनिक नैतिकता का अभाव जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार का असर नागरिक के जीवन में सार्वजनिक सेवाओं, अर्थव्यवस्था से लेकर न्याय पाने और व्यक्तिगत आर्थिकता तक हर स्तर पर पड़ता है। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसे नियामकीय ढांचे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सका है, तो सरकार को और जवाबदेह व पारदर्शी गवर्नेंस मॉडल पर विचार करना चाहिए। राजनीतिक, प्रशासनिक, पुलिस व न्यायिक सुधार के साथ सरकार व सार्वजनिक जीवन में नैतिक, लीगल व सिस्टमैटिक मानक तय किए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जरूरी है।

संघ बैठक का संदेश : राष्ट्र प्रथम

विमर्श
अवधेश कुमार

> आप संघ के समर्थक हों या विरोधी, स्वीकार करना पड़ेगा कि यह कार्य व्यापक स्तर पर कोई कर रहा है तो संघ और उसके विचार प्रेरित संगठन ही। महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध यौन दुराचार पर सभी प्रतिनिधियों द्वारा त्वरित और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता पर आम सहमति थी और कहा गया कि कानूनी तंत्र और सरकार को प्रोएक्टिव, सजग और सक्रिय रहने के साथ आवश्यकता होने पर कानूनी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि समन्वय बैठक से इस दिशा में निश्चित कार्यक्रम एवं सरकारों के लिए सुझाव आए होंगे जिन पर अमल होगा। प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि हमारे काम का एक ही मूल सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथम।

केरल के पलक्कड़ में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक से निकले संदेश कई अर्थों में महत्वपूर्ण हैं। संघ की अखिल भारतीय बैठकों पर देश और भारत में रुचि रखने वाले विदेश की भी दृष्टि रहती है। इस समय भारत के अंदर और पड़ोस में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनके संदर्भ में बहुत बड़ी संख्या में सक्रिय और आम लोग भी जानने को उत्सुक हैं कि इन पर संघ का मंतव्य क्या है और वह क्या कर रहा है। चूंकि यह संघ से जुड़े मोटा-मोटी सभी संगठनों की वार्षिक बैठक थी तो यहां के स्वर और निर्णय का महत्व है। विरोधियों और राजनीतिक दृष्टि से सोचने वालों को छोड़ दीजिए तो संघ पर निष्पक्ष अध्ययन करने वाले मानते हैं कि जो भी निर्णय या भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती है वह सभी संबंधित संगठनों के लिए होता है और सभी उसी तरह काम करते हैं जैसे परिवार के सदस्य। पिछले कुछ महीने में भाजपा और संघ के संबंधों पर कई ऐसे संकेत और वक्तव्य आए जिनसे लगता था कि परस्पर संवाद, सहयोग या समन्वय की कमी है। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का वह बयान अभी तक चर्चा में है कि भाजपा उस दौर से काफी आगे बढ़ चुकी है जब उसे संघ की आवश्यकता थी और अब वह अपना कार्य स्वयं संभालने में सक्षम है।

लोकसभा चुनाव परिणाम भाजपा और उनके समर्थकों के उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने के कारण भी अनेक अटकलें और टिप्पणियां सामने आ रही थी। राजनीति और सत्ता की ताकत सबसे बड़ी दिखती है इसलिए सामान्य मानस प्रत्येक विषय को इसी के इर्द-गिर्द देखता है। हालांकि सच यही है कि संघ से जुड़े या उसकी प्रेरणा से काम करने वाले अन्य संगठनों की तरह राजनीति में भाजपा भी एक है। सत्ता के पास सर्वाधिक निर्णयकारी शक्तियां है इसलिए उसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि वहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। बैठक में जानकारी देने वाले प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के वक्तव्यों में अपनी ओर से भाजपा पर कुछ न कहना बताता है कि भाजपा पर विशेष फोकस नहीं था। प्रश्न है कि समन्वय बैठक में हुए विमर्शों , भाषणों या वक्तव्यों तथा निर्णयों को किस रूप में देखा जाए? सुनील आंबेकर ने बताया कि हमारे काम का एक ही मूल सिद्धांत है, राष्ट्र प्रथम। संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष 2026 की ओर बढ़ रहा है और इस दृष्टि से कुछ कार्यक्रम तय किए इनमें पांच संकल्प प्रमुख हैं, जिनके आधार पर संघ राष्ट्रव्यापी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने की घोषणा कर चुका है। केरल में बैठक है तो वायनाड भूस्खलन और त्रासदी का विवरण एवं स्वयंसेवकों का समाज के साथ मिलकर किए गए राहत व पुनर्वास कार्यों का चित्र और आगे की योजनाएं भी सामने रखी गईं। इसी तरह महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार, बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा, वक्फ विधेयक,समान नागरिक संहिता आदि।

पूरे देश को हिलाने वाला पश्चिम बंगाल का घटनाक्रम गहन चर्चा में न आये, ऐसा हो नहीं सकता। संघ अनेक

वर्षों से सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने, उन्हें स्वावलंबी बनाने तथा उनकी भागीदारी बढ़ाते हुए सामाजिक एकता और परिवर्तन पर काम कर रहा है। परिवार को सशक्त करते हुए भारत के सामाजिक आधार को मजबूत करना है तो महिलाओं के अंदर चेतना, आत्मविश्वास तथा उन्हें अधिकाधिक आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना होगा। इस दृष्टि से संघ सामाजिक परिवर्तन लक्ष्य को आगे बढ़ा रहा है। अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की चर्चा और जनजाति महारानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को व्यापक रूप से मनाने का निर्णय हुआ जिसकी पहल वनवासी कल्याण आश्रम करेगा। जरा सोचिए, दिन-रात दलितों, आदिवासियों की बात करने वाले संगठनों, राजनीतिक दलों और नेताओं ने कभी अहिल्याबाई या रानी दुर्गावती के बारे में चर्चा भी की?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों ने पिछले वर्षों में जनजातियों के बीच के राजाओं, महापुरुषों, महारानियों तथा वीरांगनाओं या समाज में योगदान देने वाली महिलाओं-पुरुषों को जिस तरह महिमामंडित कर उनको आगे लाया है, वह पहले नहीं देखा गया। गहराई से देखेंगे तो यह लंबे समय संघ की विचारधारा से मिली प्रेरणा और काम करने वाले संगठनों के समन्वय की ही परिणति है। जिस तरह इस समय भारत को जाति और समुदाय के नाम पर खंडित करने का राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उनमें केवल उनका प्रतिवाद करने की जगह समाज में सकारात्मक काम करने की आवश्यकता है।

आप संघ के समर्थक हों या विरोधी, स्वीकार करना पड़ेगा कि यह कार्य व्यापक स्तर पर कोई कर रहा है तो संघ और उसके विचार प्रेरित संगठन ही। महिलाओं और बच्चियों के विरुद्ध यौन दुराचार पर सभी प्रतिनिधियों द्वारा त्वरित और समयबद्ध न्याय की आवश्यकता पर आम सहमति थी और कहा गया कि कानूनी तंत्र और सरकार को प्रोएक्टिव, सजग और सक्रिय रहने के साथ आवश्यकता होने पर कानूनी ढांचे को मजबूत करना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि समन्वय बैठक से इस दिशा में निश्चित कार्यक्रम एवं सरकारों के लिए सुझाव आए होंगे जिन पर अमल होगा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन पर संघ का मत अलग है। संघ के अनुसार विषय सरकार का है पर यह बहुत लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हालांकि यह भी कहा गया कि विषय सभी लोकतांत्रिक सरकार को कानून के अनुसार शासन करने और जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए जनता के प्रति जवाब दिए होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार क्या इस तरह का व्यवहार करने वाली है?

जाति जनगणना के मुद्दे को राजनीतिक दलों ने जिस उग्रता से सामने रखा है उससे समाज में भ्रम और तनाव दोनों बढ़ा है। प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के वक्तव्य का मुख्य स्वर यही था कि संघ समाज के पिछड़ों, वंचितों आदि को मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण सहित हर प्रकार के उपायों का समर्थन करता है। अर्थ हुआ कि संघ को जनगणना के साथ जाति गणना में कोई समस्या नहीं है। हां,सचेत होकर गणना कराने के साथ पूरी सतर्कता से इसका उपयोग करना होगा। संघ के अनेक समर्थकों और जानकारों के बीच इस पर स्पष्ट दो राय हैं। अधिकतर प्रतिक्रिया यही है कि जाति गणना के खतरों, पूर्व गणना के आंकड़ों की विसंगतियों ,भारत की जातीय जटिलता और समाज की एकता का ध्यान रखते हुए इसके प्रति देश को सचेत करना चाहिए था। अब संघ ने फिर अपना मत स्पष्ट कर दिया है तो ज्यादातर लोग उसके अनुसार आगे प्रभावों व नकारात्मक उपयोग और दुरुपयोग का पूर्व आकलन करते इससे समाज के रक्षा करने के पूर्व उपाय पर काम करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

दो टूक
कृष्णमोहन झा

जातिगत जनगणना के मुद्दे पर संघ का संतुलित दृष्टिकोण

कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल पिछले कुछ महीनों से जातिगत जनगणना का मुद्दा उछाल कर देशभर में अपने पक्ष में हवा बनाने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ राजग की मुखिया भाजपा ने अभी तक अपना कोई स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया है परन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गत दिनों केरल के पलक्कड़ शहर में संपन्न अपनी अखिल भारतीय समन्वय बैठक में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनका निहित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। संघ का मानना है कि हिंदू समाज में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है लेकिन इस मुद्दे का चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल पिछड़े समाज का कल्याण होना चाहिए।

बैठक में संघ का स्पष्ट मत था कि जातीय विभाजन को रोकने का एक मात्र उपाय हिंदुत्व है। गौरतलब है कि देश के विभिन्न स्थानों पर संघ की समय-समय पर होने वाली बैठकों में अखिल भारतीय समन्वय बैठक को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। केरल के पलक्कड़ में संपन्न हुई यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी क्योंकि कुछ समय पूर्व वायनाड में भूस्खलन से जान-माल का भारी नुक़सान हुआ था। बैठक के प्रारंभ में वायनाड हादसे में असमय ही मौत की शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। बैठक में संघ के स्वयंसेवकों ने वायनाड में चल रहे राहत कार्यों में अपनी सहभागिता की जानकारी साझा की। संघ की इस महत्वपूर्ण बैठक के पहले दिन सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सहित संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधियों ने भी बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

लोकसभा चुनावों के बाद तीन महीने बाद संपन्न संघ की इस तीन दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय महत्व के जिन विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ, उनकी सारगर्भित जानकारी बैठक की समाप्ति के पश्चात संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रभारी सुनील आंबेकर ने एक पत्रकार वार्ता में प्रदान की। सुनील आंबेकर ने बताया कि बैठक में कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या की घटना की निंदा करते हुए उसकी जांच और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकारी मशीनरी, तंत्र की सक्रियता पर बल दिया गया। संघ की बैठक में कोलकाता कांड जैसी घटनाओं को रोकने के पांच तरह के उपाय किए जाने पर बल दिया गया। इनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर त्वरित न्याय, सामाजिक जागरूकता, बचपन से बच्चों में उत्तम संस्कार, शिक्षा व्यवस्था और आत्म रक्षा का प्रशिक्षण शामिल है।

बैठक में इस विषय से जुड़े विचार-विमर्श में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परोसी जाने वाली सामग्री की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए ताकि वे अश्लीलता न परोस सकें। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कोलकाता कांड जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने में संघ द्वारा सुझाए गए उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संघ की समन्वय बैठक में बांग्ला देश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से बांग्ला देश सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया गया। बैठक में बांग्ला देश की ताजा स्थिति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी पेश की गई। संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रभारी ने बताया कि बैठक में पंच परिवर्तन संकल्प के रूप में नागरिक कर्तव्य, कुटुम्ब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय स्वत्व देशव्यापी परिवर्तन अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। संघ की प्रति वर्ष होने वाली बैठकों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली समन्वय समिति की यह बैठक इस बार चूंकि लोकसभा चुनावों के बाद आयोजित की गई थी इसलिए जब पत्रकारों ने सुनील आंबेकर से संघ और भाजपा के बीच विगत दिनों उभरे कथित मतभेद के बारे में प्रश्न किया तो उन्होंने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए कहा कि हम इसे परिवार के अंदर ही सुलझा लेंगे। बैठक में संघ के शताब्दी आयोजनों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गलत सोच का चश्मा जल्दी उतार देना चाहिए

संकलित
दर्शन

जब सोच निषेधात्मक या गलत होती है, तब वह सुख को भी दुख में परिवर्तित कर देती है। गलत सोच का चश्मा जितनी जल्दी हो, उतार देना चाहिए। बुरे विचार जितना दूसरों का नुकसान करते हैं, उतना ही स्वयं का भी करते हैं। कारण अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरा दिमाग ठंग से नहीं सोच पाता। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। कहा गया है कि आपके विचार वहां तक ले जाते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं। पर कमजोर विचारों में दूर तक ले जाने की ताकत नहीं होती। हम जो हैं वह सब विचारों का फल है। जो हम सोचते हैं, वही बन जाते हैं। मनुष्य अपने कार्यों से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने विचारों से स्वयं को। गलत सोच एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को धनवान और प्रतिष्ठित होते देख आदमी में नकारात्मक चिंतन जागता है। अपनी ईमानदारी उसे मूर्खतापूर्ण लगती है। वह पुनर्चिंतन करता है-क्या मिला मुझे आदर्शों पर चलकर? यह नकारात्मक चिंतन उसे भी गलत सोच के दलदल में उतार देता है। समाज में भ्रष्ट और बेईमान लोगों की उत्पत्ति इसी तरह के गलत विचारों के संक्रमण से हुई। इस तरह का गलत सोच हमारी दुनिया को छोटा कर देता है। भीतर और बाहरी दोनों ही दुनिया सिमट जाती हैं। तब हमारी छोटी-सी सफलता अहंकार बढ़ाने लगती है। थोड़ा-सा दुख अवसाद का कारण बन जाता है। कुल मिलाकर सोच ही गड़बड़ हो जाता है। अपने ही बोले हुए को सुनते रहना ज्यादा सीखने नहीं देता। हमारा चिंतन गुणी को ओर केंद्रित रहना चाहिए।

जरूरतमंदों की मदद ही सबसे बड़ी सेवा

संकलित
प्रेरणा

एक वैद्य गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आनन्दपुर गया। वहां गुरुजी से मिलने पर उन्होंने कहा कि जाओ और जरूरतमंदों को सेवा करो। वापस आकर वह रोगियों की सेवा में जुट गया। शीघ्र ही वह पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। एक बार गुरु गोविंद सिंह स्वयं उसके घर पर आए। वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वे कुछ देर ही ठहरेंगे। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला- वैद्य जी, मेरी पत्नी की तबियत बहुत खराब है। जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। वैद्य जी असमंजस में पड़ गए। एक ओर गुरु थे, जो पहली बार उनके घर आए थे। दूसरी ओर एक जरूरतमंद रोगी था। अंततः वैद्यजी ने कर्म को प्रधानता दी और इलाज के लिए चले गए। लगभग दो घंटे के इलाज और देखभाल के बाद रोगी की हालत में सुधार हुआ। तब वे वहां से चले, उदास मन से उन्होंने सोचा कि गुरुजी के पास समय नहीं था। अब तक तो वे चले गए होंगे फिर भी वैद्यजी भागते हुए वापस घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। गुरुजी बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैद्यजी उनके चरणों पर गिर पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा- तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सबसे बड़ी सेवा जरूरतमंदों की मदद करना है।

अंतर्मन

आज की पाती

हथकरघा को और बढ़ावा मिले

वर्ष 1905 में जब अंग्रेजी शासक लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की कोशिश की, तो उसी समय कोलकाता के टाउनहॉल में हजारे देश के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन का श्रीगणेश किया था। हथकरघा हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान भी है। इनमें हमारे देश के इतिहास की झलक देखने को मिलती है। केंद्र सरकार देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया था, ताकि देश में हथकरघा उत्पादों और इसके जरिए रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। देश में हथकरघा को और बढ़ावा देने की जरूरत है।

- मयंक जोशी, राजनांदगांव

ट्रेंड

प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी

हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारियों में से एक, श्री प्रकाश सिंह जी से मिलना वास्तव में अद्भुत था। भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के प्रति उनका जुनून उल्लेखनीय है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

देश में भय का राज

नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देशभक्त तो भय का राज स्थापित कर रहे हैं। मौत की सड़क में घिरे हुए नफरती तंत्र वालुन को चुनौती देते हुए सुलेखा हिंसा पैदा कर रहे हैं। नाजुक सरकार से इनकी खुली छूट मिली है, इसीलिए उनकी इतना साहस पैदा हुआ है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

विजेताओं को बधाई

वाल वैरिल पैरालिंपिक में हमारा दिन शानदार पैरालिंपिक था। उन सभी विजेताओं को बधाई जिन्होंने भारतीय ध्वज को ऊंचा फहराया, जिसने वह पैरालिंपिक में भारत के लिए अब तक का सबसे यादगार दिन बन गया।

-सचिन, पूर्व क्रिकेटर

पसंदीदा दोस्त चाहिए

मेरी तरह वो देखभाल ले लड़ने इतना कुछ सिखाया है कि अब मैं ऐसे दोस्त चाहती हूं जो जिंदगी न हों और मुझे अंदर से ठोक कर सके.. बिल्कुल मेरे पसंदीदा स्नैकबेयर उत्पादों की तरह।

-सेलिना जेटली, अभिनेत्री

करंट अफेयर

श्रीलंका में दाह संस्कार के अधिकार की गारंटी मिली

श्रीलंका में एक ऐसे विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गयी है जो हर व्यक्ति को यह फैसला करने का अधिकार प्रदान करेगा कि उसके शव को दफनाया जाए या जलाया जाए। मंगलवार को मंत्रिमंडल के एक नोट से यह जानकारी सामने आयी। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जबरन दाह संस्कार से देश के नौ प्रतिशत मुस्लिम अल्पसंख्यकों में काफी नाराजगी फैल गयी थी। 'दफन एवं दाह संस्कार अधिकार विधेयक' के माध्यम से अल्पसंख्यकों की नाराजगी दूर करने की चेष्टा की गयी है। नोट में कहा गया है, 'यह निर्णय लेने का अधिकार मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को होगा कि उसके शव को दफनाया जाए या उसका दाह संस्कार किया जाए।' सोमवार को इस विधेयक को मंजूरी दी गयी थी। उसके बाद न्याय मंत्री एम यू एम अली सबरी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, मंत्रिपरिषद ने 'दफन और दाह संस्कार अधिकार विधेयक' को पारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को मंजूरी दे दी, यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसका मैंने दृढ़ता से समर्थन किया था।' कोविड-19 महामारी के दौरान, 2020 और 2021 में, तत्कालीन सरकार द्वारा नियुक्त की गयी एक विशेषज्ञ समिति ने फैसला किया था कि अगर वायरस से मरने वाले मरीजों के शवों को दफनाने की अनुमति दी जाती है।

ऑफ बीट

सोने के बड़े टुकड़े कैसे तैयार होते हैं?

सोने के प्रति मानव जाति का आकर्षण हजारों साल पुराना है। प्राचीन यूनानी और रोमन दस्तावेज में सोने के खनन का जिक्र किया गया है। सोना पाने की चाह ने आधुनिक दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासतौर पर 19वीं शताब्दी में। यह ठोस, पीली धातु ज्यादातर चट्टानी खनिज क्वार्ट्ज की 'शिराओं' में पाई जाती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि तापमान, दबाव और रसायन विज्ञान में परिवर्तन के कारण दोनों (सोना और क्वार्ट्ज) भूमिगत गर्म तरल पदार्थों से एक साथ संघनित हो जाते हैं। भूविज्ञानी इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन सोने के बड़े टुकड़े कैसे तैयार होते हैं, यह अब भी रहस्य का सबब बना हुआ है। सोना प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तरल पदार्थों में प्रति दस लाख में छोवल एक भाग की दर से घुलता है, तो यह दसियों या यहां तक कि सैकड़ों किलोग्राम वजन वाले टुकड़ों में कैसे समा जाता है 'नेचर जियोसाइंस' पत्रिका में मंगलवार को प्रकाशित हमारे अनुसंधान के मुताबिक, उक्त सवाल का जवाब संभवतः क्वार्ट्ज के असम्भव विद्युत गुणों में, और भूतंप के दौरान उस पर पड़ने वाले दबाव में छिपा हुआ है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

60 प्रतिवर्ष इंसानों में होने वाले संक्रमण पशु जनित हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार। वहीं करीब 80 प्रतिशत पशु हर साल मांस की जरूरत के लिए मार दिए जाते हैं।

अरविंद कुमार मिश्रा
लोक नीति विश्लेषक

आजकल

खानपान से भी जुड़ा है पर्यावरण का पहलू

देश में हर साल सितंबर माह का प्रथम सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के प्रति जागरूक करना है। आज की बिगड़ी जीवनचर्या और गलत खानपान के कारण लोगों में तरह-तरह की बीमारियां पनप रही हैं। इसमें वीगन फूड (मांसाहारी खाद्यान्न के शाकाहारी विकल्प) हमारी मदद कर सकते हैं। वनस्पतियों से बने शाकाहारी चिकन, मटन और कबाब, सोया और जई से बना दूध, वनस्पतियों से तैयार दही, पनीर और घी, वनस्पति चीज, बर्गर एवं बटर जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हमें स्वाद और पोषण की नई दुनिया में ले जा रहे हैं। जरूरत है इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की

पोषक आहार लोगों को सेहतमंद बनाए रखते हुए स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण भी करता है। प्रतीकात्मक

देश में इस समय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। हर साल सितंबर माह का प्रथम सप्ताह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार और सही पोषण के प्रति जागरूक करना है। देश में पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वर्ष 1982 में मनाया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य विषय 'सभी के लिए पौष्टिक आहार' है। इसमें दैनिय नहीं कि स्वस्थ एवं संतुलित आहार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को पोषण प्रदान करता है और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्याप्त पोषण का सेवन करने वाले व्यक्ति अधिक कार्य करते हैं जबकि खराब पोषण प्रतिरक्षा में कमी, बीमारी के जोखिम को बढ़ाने, शारीरिक एवं मानसिक विकास को क्षीण करने तथा कार्यक्षमता में कमी पैदा करने का कार्य करता है। पोषण का उत्पादकता, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के सथ जलवायु में नकारात्मक बदलाव बढ़े हैं। इसका असर खाद्यान्न उत्पादन और उसके उपभोग के तरीकों पर पड़ा है। आज की बिगड़ी जीवनचर्या और गलत खानपान के कारण लोगों में तरह-तरह की बीमारियां पनप रही हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही खाद्य पदार्थ हजारों साल से हमारे पोषण और आजीविका का आधार हैं। बढ़ती आबादी के साथ पशु आधारित खाद्यान्न पर निर्भरता बढ़ती गई। इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर गैरजरूरी दबाव पड़ा। अब यह जैव विविधता के असंतुलन के रूप में हमारे सामने है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक गैरशाकाहारी खाद्यान्न की बढ़ती खपत से घास के मैदान, ओजोन परत, वन, मिट्टी और समुद्री जल को बेतहाशा नुकसान पहुंचा है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 14.5 प्रतिशत हिस्सेदारी पशु आधारित खाद्यान्न उत्पादन की है। दुनिया के कुल चारगाह का 15 प्रतिशत मवेशियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इससे जैव विविधता के सामने नया संकट पैदा हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि इंसानों में होने वाले 60 प्रतिशत संक्रमण पशु जनित हैं। 80 अरब पशु हर साल मांस की जरूरत के लिए मार दिए जाते हैं। मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ा अंतर होने से पशु आधारित खाद्यान्न की गुणवत्ता निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जलवायु संकट के बीच पशुओं से मिलने वाले खाद्यान्न जैसे मांस, अंडे के शाकाहारी विकल्पों की मांग बढ़ी है।

शाकाहारी भोजन के नए संस्करण वीगन फूड (मांसाहारी खाद्यान्न के शाकाहारी विकल्प) की तकत को उपभोक्ता, बाजार और सरकारें समझ रही हैं। वनस्पतियों से बने शाकाहारी चिकन, मटन एवं कबाब, सोय और जई से बना दूध, वनस्पतियों से तैयार दही, पनीर एवं घी, वनस्पति चीज, बर्गर एवं बटर जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हमें स्वाद की नई दुनिया में ले जा रहे हैं। वीगन फूड एक तरह का शाकाहारी भोजन ही है। आबादी का एक बड़ा अनुपात मांस-मछली का सेवन नहीं करता, लेकिन अंडे एवं डेरी उत्पाद अर्थात पशुओं से प्राप्त दुग्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करता है। वीगन फूड में मांस-मछली के सथ दुग्ध उत्पादों का विकल्प भी मिलता है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक वनस्पतियों पर आधारित खाद्य पदार्थों की मांग 20 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है। मांसाहार के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे वीगन फूड का बाजार अकेले भारत में 2030 तक 6,824 करोड़ रुपये का होगा।

कुपोषण से जंग में सहायक : देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित पोषण के कई कार्यक्रमों के बावजूद कुपोषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले पांच साल में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग का स्तर 38 से 36 प्रतिशत तक मामूली रूप से कम हुआ है। स्टंटिंग तब मामूली रूप से कम होती है जब किसी बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 में अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मोटापे की व्यपकता में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत और पुरुषों में 19 प्रतिशत से 23 प्रतिशत हो गया। 15 से 49 आयु वर्ग की 58 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं। देश की 75 प्रतिशत आबादी प्रोटीन की कमी से जूझ रही है। समग्र पोषण से जुड़ी ऐसी चुनौतियों के समाधान में पशु आधारित खाद्यान्न के वनस्पति आधारित विकल्पों को टिकाऊ बनाना होगा। पादप आधारित खाद्यान्न व्यक्ति की रोजमर्रा की पोषण आवश्यकता को पूरा करता है। इसमें पाए जाने वाले आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी12, विटामिन डी, ओमेगा-3, फैटी एसिड और आयोडीन सुपोषण के आधार हैं। पौधों में संग्रहित विभिन्न यौगिक फाइबर, एंटी आक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायक हैं। सोयाबीन से तैयार होने वाले शाकाहारी चिकन की ही बात करें तो यह प्रोटीन से भरपूर होता है। सोयाबीन में 33 प्रतिशत प्रोटीन, 21 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसमें वसा की मात्रा भी कम होती है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित देशों में शाकाहारी खाद्य उत्पादों की लोकप्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसकी वजह शाकाहारी खाद्य उत्पादों के उच्च पोषक तत्व हैं। दुनिया भर में वनस्पतियों से तैयार फूड से स्मार्ट प्रोटीन हासिल कर कुपोषण की जंग को आसान किया जा रहा है।

भारतीय आहार पद्धति को देखें तो 70 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। इसका दबाव पशु आधारित खाद्य प्रणाली पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन से बचने के लिए पशु आधारित उत्पादों के पादप आधारित विकल्पों को बढ़ावा होगा। वीगन फूड को लेकर भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक अनुकूलता हमारे पक्ष में है। हम मोटे अनाज, काबुली चना, मसूर की दाल, मटर, चावल और सोयाबीन के शीर्ष पांच उत्पादकों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से आदिवासियों द्वारा श्रेअन से ऐसे डिब्बा बंद और फैक्लिफ्ड खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, जो जंक फूड के बेहतरीन विकल्प हैं। इनमें जौ के सूप, नुडल्स, मिलेट बार जैसे उत्पाद प्रमुख हैं। वनस्पति आधारित जई, सोया और बादाम दूध देरी के पैकेल्फ उत्पाद के रूप में उभर रहे हैं। वहीं इसकी खपत बढ़ने का प्रत्यक्ष लाभ किसानों को होता है। नेशनल न्यूट्रिशन मानिटरिंग ब्यूरो द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति देश में विटामिन ए और डी की न्यूनता पर चिंता जाहिर कर चुकी है।

ग्रामीण शीत भंडारण क्षमता का लाभ : पशुओं से मिलने वाले खाद्यान्न के शाकाहारी विकल्पों की लोकप्रियता बाजार में उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन उत्पादों की मांसाहारी खाद्य पदार्थों की तुलना में लागत सक्षम बनाया जाना चाहिए। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से निजी निवेशक अत्यधिक नियामकीय हस्तक्षेप के भय से मुक्त होंगे। इसका लाभ वनस्पति आधारित खाद्यान्न के प्रसंस्कृत उत्पादों की वृद्धि के रूप में होगा। इससे किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार होगा, जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी मिलेगी। पौधे आधारित खाद्यान्न के सामने सबसे बड़ी चुनौती भंडारण की भी है। इस दिशा में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए हर ब्लाक स्तर पर दो हजार टन क्षमता के भंडारण गोदाम बनाए जा रहे हैं। देश की भंडारण क्षमता अभी 1,450 लाख टन है, जो बढ़कर 700 लाख टन हो जाएगी।

शून्य कार्बन उत्सर्जन में सहायक : संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक विश्व की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी। इस दौरान खाद्यान्न की मांग लगभग 59 प्रतिशत बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक आठ प्रतिशत लोग भूख के संकट से जूझ रहे होंगे। जलवायु में हो रहे नकारात्मक बदलाव विकासशील देशों की खाद्य श्रृंखला पर सबसे अधिक असर डाल रहे हैं। आज जलवायु संकट ने मनुष्य के साथ ही संपूर्ण प्रकृति के समक्ष आपातकालिन स्थिति निर्मित कर दी है। तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव खाद्यान्न प्रणाली पर पड़ा है। ऐसे में खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता के लिए पशु आधारित खाद्यान्न के वनस्पति विकल्प सहायक होंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर से 50 प्रतिशत अधिक खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत होगी।

सेहत खराब कर रहे जंक फूड

आज जंक फूड शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों और युवाओं में स्वास्थ्य जनित समस्याएं पैदा कर रहे हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, कोनैफ्लार, रागी, मैदा, मीठी मकई के दाने, कुट्टू, चना दाल से बने उत्पाद पशुओं द्वारा खाद्यान्न का विकल्प हैं। सोया, जई, बादाम से तैयार दुग्ध और डेरी उत्पाद खाद्य श्रृंखला में असरदार उपस्थिति बना रहे हैं। आवश्यकता है पौधों से तैयार होने वाले वीगन फूड के सर्टिफिकेशन को लेकर जागरूकता लाने की। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) 2021 में वीगन फूड के लिए अलग लोगो (निशान) जारी कर चुका है। वीगन फूड के हर पैकेट में इस लोगों को प्रिंट करना अनिवार्य है। यह अंग्रेजी का बी अक्षर (बीच में पत्ती की आकृति) होता है जिसे हरे रंग में चित्रित किया गया है। वीगन फूड की प्रसंस्करण और फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम से जोड़कर कृषोपण की जंग आसन बनाया जा सकता है। एफएसएसएआइ द्वारा संचालित फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम में चावल और दूध में बाहर से पौषक तत्व मिलाए जाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां महज कुछ दूरी पर भाषा और खानपान के तरीके बदल जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि खानपान की आदतों क्षेत्र विशेष की जलवायु के अनुकूल हों। यदि ऐसा करने में हम सफल हुए तो स्वाद के नए विकल्प वीगन फूड हमारे जायके और सेहत के साथ धरती को भी सुंदर बनाएंगे।

-अरविंद कुमार मिश्रा

खरी-खरी

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर मंथन

धर्मेंद्र जोशी

तमाम प्रयासों के बाद भी देश की सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार दृष्टिगत नहीं हुआ, तो अधिकारी वर्ग खासा चिंतित हो उठा। जिनके खुद के बच्चे तो महंगे प्राइवेट स्कूलों में तालीम ले रहे हैं वे राजधानी के वातानुकूलित कमरों में बैठकर गांव-देहात की पाठशाला की दुर्दशा पर दुबलाने लगे। आनन-फानन में रात के बारह बजे आदेश जारी किया गया। सुबह होते ही मातहतों को आमद की ताकीद की गई।

चाय-नश्ता के साथ चर्चा का दौर शुरू हुआ, जो लंच तक किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। शिक्षा व्यवस्था में अलख जगाने का दम भरने वाले खुद सुस्ताने लगे। एक गंभीर अधिकारी ने मौके की नजाकत समझते हुए सभी को आराम करने को कहकर चार बजे तक के लिए बैठक स्थगित कर दी। जैसे ही घड़ी का कांटा चार पर आय, सभी तंद्रा से जागे और मिशन 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' के लिए अपनी आरामदायक कुर्सी पर आकर बैठ गए।

बड़े अधिकारी ने चिंता जताते हुए कहा कि हमारे सरकारी स्कूलों की हालत अत्यंत दयनीय है। इसे सुधारने के लिए आप अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। इतना सुनते ही कई हाथ झट से खड़े हो गए। सबसे पहले एक नवागत अधिकारी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोलीं- मुझे लगता है कि इस आधुनिक समय में शिक्षा में नवाचार की महती आवश्यकता है। इसके लिए क्यों न अधिकारियों को विदेश यात्रा पर भेजा जाए, जिससे अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति को हमारे स्कूलों में भी लागू किया जा सके। यह सुनकर पहली पंक्ति बैठे अफसर ने संपल्लीक हवाई यात्रा का लगे हाथ सुझाव दिया। तभी अंतिम पंक्ति में बैठे वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें शिक्षा की जमीनी स्तर पर पहुंच कर मजबूत करना है। ऐसे में कृपया हवा-हवाई बातें न करें। क्यों न सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का बड़ा अभियान चलाया जाए। एक तेजतर्रार अधिकारी बीच में ही खड़े हो बोले-मेरी राय है कि सभी स्कूलों के लिए नवीन भवन निर्माण की योजना बनाई जानी चाहिए।

अभी भी अधिकारीजनों का मंथन जारी है।

पोस्ट

पेंशन की बात तो दूर रही, हिमाचल प्रदेश में वेतन तक की मुश्किल हो गई है। मुफ्तखोरी वाली आर्थिक नीतियों का अभी सिर्फ यह ट्रेलर है। पूरी पिक्चर कैसी होगी, इसी से अंदाजा लगा लीजिए।
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhi

फिल्म इमरजेंसी की रिलीज में कई बाधाएं आ रही हैं, मगर सच का एक स्वभाव है कि इसकी धूल को जितना कालीन के नीचे दबाने की कोशिश करोगे, उतनी उड़कर आपकी आंखों में आकर चुभेगी।
जगदीश भाटिया@jagdish

विमान अपहरण कांड पर बनी आइसी-814 की जितनी चर्चा हो रही है, उस पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आइएसआइ को अपने पीआर-प्रचार के लिए अनुभव सिन्हा से बेहतर फिल्मकार नहीं मिल सकता था।
हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की करहुत देखिए। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत नेताओं की तस्वीरों पर जूते मार रहे हैं। यह सुसंस्कृत महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है।
संजय निरुपम@sanjayniirupam

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को देखे बिना उसका विरोध सही है?

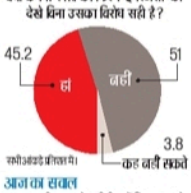

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या आइसी-814 देव सीरीज में फिल्मकार ने विमान अपहरण कांड को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ममता जी ने आज तो उगला खूब गुबार,
दो मानेहर चीज के भोदी जिम्मेदार।
मोदी जिम्मेदार वही दे दे इस्तीफा,
दोषी जन को आप बांटती जाय रजीफा।
इनके स्वर के साथ बांटती जाय रजीफा।
इनके स्वर के साथ करे जो हां जी, हां जी,
उससे रहे प्रसन्न हमेशा ही ममता जी।
- ओमप्रकाश तिवारी

विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

सख्त भू कानून का इंतजार

उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य है, जिसके 71 प्रतिशत से अधिक भूभाग पर वन क्षेत्र है। भूगोल अधिकांशतया पर्वतीय है तो परिस्थितियों को विषम होना ही है। इन तमाम कारकों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण परियोजनाओं, औद्योगिक विकास और अवस्थापना सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती। यही वजह है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सख्त और शासक भू कानून लागू किए जाने की मांग राज्य गठन के बाद से ही उठती रही है। इन दिनों भू कानून को लेकर आम जनमानस फिर उद्वेलित है। हाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सैकड़ों की संख्या में लोग सख्त भू कानून की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। यद्यपि, वर्तमान पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, लेकिन इसकी संस्तुतियों को अब तक धरातल पर नहीं उतारा जा सका है।

भूमि का विषय उत्तराखंड में जनभावनाओं से जुड़ा रहा है, लेकिन संरक्षित वन क्षेत्र के कारण यहां विकास कार्य व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। राज्य, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र से पलायन का एक बड़ा कारण यह भी कहा जा सकता है। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि राज्य गठन के बाद अनियोजित तरीके से भूमि की खरीद ने जोर पकड़ा। इसका असर जनसांख्यिकीय बदलाव के रूप में देखने को मिल रहा है। एक तो भूमि की कम उपलब्धता और उस पर राज्य से बाहर के व्यक्तियों द्वारा भूमि की व्यापक पैमाने पर खरीद-फरोख्त, इससे राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा। पिछले कुछ चुनावों में सख्त भू कानून को मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश भी राजनीतिक दलों द्वारा की गई।

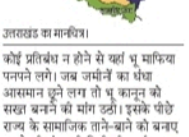

उत्तराखंड का मानचित्र।

नौ नवंबर, 2000 को जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, उस समय उत्तर प्रदेश के समय का ही भू कानून यहां लागू किया गया। भूमि खरीदने और बेचने पर कोई प्रतिबंध न होने से यहां भू माफिया पनपने लगे। जब जमीनों का धंधा आसमान छूने लगा तो भू कानून को सख्त बनाने की मांग उठी। इसके पीछे राज्य के सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखने की मंशा भी छिपी थी। वर्ष 2002 में राज्य की पहली निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी सरकार ने भू कानून को सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाए। इसी कड़ी में वर्ष 2003 में बाहरी व्यक्ति को आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्गमीटर भूमि खरीद की ही अनुमति देने का प्रतिबंध लागू किया गया। कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लगाया गया, तो 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार जिलाधिकारियों को सौंपा गया। उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़े विषयों में भूमि खरीद के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। तब भू कानून में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली जाएगी, उसे दो साल में पूरा करना होगा। यद्यपि, बाद में यह छोल दी गई कि परियोजना तय समय में पूरी न होने की स्थिति में उचित कारण बताकर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

इस सबके बावजूद राज्य में जमीनों की तेजी से खरीद-फरोख्त का क्रम बना रहा। दरअसल, तिवारी सरकार के कार्यकाल में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज मिला तो तमाम प्रतिष्ठानों के लिए कृषि भूमि की खरीद की गई। तब नए उद्योग भी राज्य में स्थापित हुए। भूमि की खरीद-फरोख्त ज्यादा तो हुई, लेकिन इसका उपयोग आवासीय एवं अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाने लगा। ऐसे में भू कानून में फिर से बदलाव की मांग उठने लगी। वर्ष 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की खंडूड़ी सरकार ने भू कानून को कुछ और सख्त किया। इसमें भूमि की खरीद पर क्रेता एवं विक्रेता, दोनों का सत्यापन अनिवार्य किया गया। सथ ही बाहरी व्यक्तियों के लिए 500 वर्गमीटर भूमि खरीद की अनुमति को घटाकर 250 वर्गमीटर कर दिया गया। यद्यपि, उद्योग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान जैसे कार्यों के लिए भूमि की जरूरत का ध्यान रखा गया। उस समय यह मांग भी उठी थी कि पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर राज्य में भू कानून बनाया जाए। हिमाचल में कृषि भूमि कोई तभी खरीद सकता है, जब वह किसान हो और लंबे समय से वहीं रह रहा हो। यही नहीं, हिमाचल में राज्य का गैर कृषक व्यक्ति भी भूमि नहीं खरीद सकता। यह बात अलग है कि सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

वर्ष 2017 में भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में कई संशोधन किए गए। कृषि, उद्योग, बागवानी, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीद के पूर्ववर्ती 12.5 एकड़ के दायरे को बढ़ाकर 30 एकड़ तक कर दिया गया। विशेष मामलों में इससे ज्यादा भूमि खरीद की व्यवस्था भी कर दी गई। यानी, एक तरह से सीलिंग लगभग समाप्त सी हो गई। ऐसे में इसका विरोध होना स्वभाविक था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी सख्त भू कानून की मांग ने जोर पकड़ा। तब सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून पर विचार एवं संस्तुतियां देने के लिए समिति गठित की। यह समिति अपनी संस्तुतियों समेत रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। इसमें भूमि खरीद से पहले क्रेता-विक्रेता दोनों का सत्यापन कराने, खरीद का उचित कारण बताने, 12.5 एकड़ की सीलिंग खत्म कर नई व्यवस्था को कड़ा बनाने, जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी जाए, उसका उपयोग तय समय में सुनिश्चित कराने जैसी संस्तुतियां की गई हैं।

धामी सरकार इनका कानूनी दृष्टि से परीक्षण करा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति इन संस्तुतियों का परीक्षण कर रही है, लेकिन लंबी अवधि गुजरने के बाद भी इस दिशा में ठोस पहल नहीं हो पाई है। यही कारण है कि भू कानून का मुद्दा राज्य में फिर से गर्माने लगा है। विपक्ष भी इसे खूब हवा दे रहा है। यद्यपि, सरकार ने साफ किया है कि वह राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लाएगी।

भारत-अमेरिका संबंध

बढ़ती रणनीतिक साझेदारी

डा. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान

पिछले दिनों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की चार दिवसीय यात्रा पर थे। उनकी यात्रा का मकसद भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना था। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रित किया। यदि अमेरिकी रक्षा कंपनियां भारत आती हैं तो दोनों देश मिलकर जिन रक्षा उत्पादों का निर्माण करेंगे वे आधुनिक किस्म के होंगे। इस प्रयास में सफलता मिलने पर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को काफी आगे बढ़ा सकेगा। इसके अलावा भारत रक्षा निर्यात में भी तेजी से आगे बढ़ेगा।

राजनाथ सिंह ने यात्रा के दौरान वाशिंगटन में दो महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। पहला, सुरक्षा आपूर्ति समझौता और दूसरा, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता। सुरक्षा आपूर्ति समझौते के जरिये अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए पारस्परिक समर्थन प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। इसके तहत दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करने के लिए एक-दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त कर सकेंगे। अमेरिका अब तक यह समझौता 17 देशों के साथ कर चुका है। भारत 18वां देश है। वहीं संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जो समझौता हुआ है, उसके तहत दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस समझौते के तहत भारत हिंद-प्रशांत कमांड, फ्लोरिडा में एक विशेष आपरेशन कमांड एवं बहरीन में अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय संयुक्त समुद्री सेना में तीन कर्नल स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करेगा। वैसे इस समझौते की औपचारिकता से पहले ही ऐसे अधिकारियों की तैनाती की जा चुकी है।

हाल में अमेरिका ने एंटी-सबमरीन वारफेयर सोनोबाय और उससे संबंधित उपकरण भी भारत को बेचने की अनुमति दी है। इस पनडुब्बीरोधी सामग्री से समुद्र में भारत को ताकत बढ़ेगी और चीन की साजिश पर लगाम लगने में मदद मिलेगी। सोनोबाय के मिलने से भारत की एमएच-60 आर हेलीकाप्टरों से पनडुब्बीरोधी युद्ध संचालन की क्षमता बढ़ेगी। इसे वर्ष मार्च में भारत ने छह एमएच-60 आर हेलीकाप्टरों का पहला स्क्वाड्रन तैयार किया है। भारत ने नौसैनिक हेलीकाप्टर बेड़े को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2020 में अमेरिका से 24 लाकहीड मार्टिन-सिकोरस्की एमएच-60 आर बहुउद्देश्यीय हेलीकाप्टरों की खरीद का आर्डर दिया था। सोनोबाय तकनीक की अच्छाई यह है कि शत्रु की नजर में नहीं आती है और लक्ष्य को शीघ्र पता कर लेती है। लक्ष्य चाहे जितनी अधिक ऊंचाई पर हो या चाहे जितना नीचे हो, दोनों ही स्थितियों में लक्ष्य को खोजेगा इसके लिए आसन होता है। सोनोबाय की लंबाई तीन फुट और माटाई पांच फुट है। इसको नौसेना के युद्धपोत व हेलीकाप्टर से समुद्र में छोड़ा जाता है। यह रेडियो ट्रांसमीटर तथा हाइड्रोफोन की मदद से लक्ष्य की शीघ्रता से ढूढ लेता है। सोनोबाय एक प्रकार के सेन्सर उपकरण होते हैं, जो समुद्र में पानी के अंदर शत्रु की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। पानी में नीचे पहुंचने के बाद ये ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पनडुब्बियों की स्थिति को पता कर लेते हैं। इनका उपयोग नौसैनिक अभियानों में शत्रु की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाएगा। निश्चित है कि इससे नौसेना की ताकत काफी अधिक बढ़ जाएगी। सोनोबाय से समुद्र में देश की पनडुब्बियों की सुरक्षा भी मजबूत हो जाएगी।

सेना के आधुनिकीकरण में अमेरिका का सहयोग लेता भारत। फाइल

इसके अलावा भारत ने अमेरिका से असाल्ट राइफलें खरीदने का भी निर्णय लिया है। इसी के तहत भारत ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी सिग सायर को 73,000 सिग-716 असाल्ट राइफलों का आर्डर दिया है। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। भारत पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच यह कदम उठाया है। सिग-716 असाल्ट राइफल की मारक क्षमता 500 मीटर है। इसकी बैरल की लंबाई लगभग 16 इंच है। इसकी एक मैगजीन में 20 गोलियां लोड होंगी। यह प्रत्येक मिनट में 685 राउंड फायर करती है। 73,000 सिग-716 असाल्ट राइफलों के मिलने के बाद भारत के पास इनकी संख्या 1,45,400 हो जाएगी। इन राइफलों को चीन एवं पाकिस्तान की लगती सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इस तैनाती से सीमाओं पर भारतीय सेना और मजबूत हो जाएगी।

****

दैनिक जागरण

संतुलित दृष्टिकोण के बिना जीवन में स्थायित्व संभव नहीं

एक और कठोर कानून

ममता सरकार की पहल पर बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के प्रविधान वाला जो विधेयक पारित किया, उससे यौन अपराधी हतोत्साहित होंगे, यह कहना कठिन है। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह राजनीतिक संदेश देना अधिक है कि ममता सरकार दुष्कर्म के अपराधों के प्रति संवेदनशील है। ममता सरकार को यह संदेश देने की जरूरत इसीलिए पड़ी, क्योंकि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में एक प्रशिक्षु महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने यही जताया कि बंगाल पुलिस और सरकार ने इस प्रकरण में गैर जिम्मेदारी और संवेदनहीनता का परिचय दिया। बंगाल विधानसभा की ओर से आनन-फानन पारित किए गए विधेयक में कहा गया है कि यदि दुष्कर्म के किसी मामले में पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वह कोमा में चली जाती है तो अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। पहले यह कहा गया था कि ऐसे मामलों में सजा सुनाए जाने के 10 दिन के अंदर दोषी को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन पारित किए गए विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि यह इसीलिए नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं था। तय न्याय प्रक्रिया का पालन किए बिना फांसी की सजा पर अमल संभव नहीं। किसी को फांसी की सजा तभी दी जा सकती है, जब उच्चतर न्यायपालिका इसकी अनुमति दे दे। इसी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश को दहलाने वाले निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा देने में आठ वर्ष लग गए थे।

कई राज्यों में कठोर कानूनों के चलते दुष्कर्म और हत्या के मामलों में निचली अदालतों की ओर से अपराधियों को फांसी की सजा तो रह-रहकर सुना दी जाती है, लेकिन उस पर अमल मुश्किल से ही हो पाता है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 20 वर्षों में दुष्कर्म और हत्या के मामलों में केवल पांच अपराधियों को फांसी की सजा दी जा सकी है। भले ही ममता बनर्जी यह कह रही हों कि अपराजिता महिला-बाल सुरक्षा विधेयक भारतीय न्याय संहिता से अधिक कठोर है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक के कानून बन जाने पर वह माहौल कायम हो सकेगा, जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें और आरजी कर मेडिकल कालेज जैसी घटनाएं न हो सकें? इसके प्रति इसलिए आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि आरजी कर मेडिकल कालेज की घटना पर देशव्यापी रोष-आक्रोश के बाद भी प्रतिदिन दुष्कर्म के समाचार आ रहे हैं। ये समाचार यही बताते हैं कि संबंधित कानूनों को दुरुस्त करने और पुलिस को अपना रवैया सुधारने के साथ ही समाज को भी चेतने की जरूरत है। आखिर समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी कब निभाएगा और इस दिशा में राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि राजनीति ही समाज को सबसे अधिक प्रभावित करती है।

शिक्षा विभाग की चिंता

उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा तमाम कोशिशों के बाद भी पटरी पर नहीं आ पा रही है। एक तरफ विभाग का आधा-अधूरा प्रशासनिक ढांचा तो दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुस्ती इसे और बढ़ा रही है। ऐसे में शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं की राह में कई तरह की बाधाएं खड़ी होती दिख रही हैं। राज्य गठन के बाद से ही शिक्षा विभाग इस समस्या से जूझ रहा है। शुरुआती कुछ वर्ष छोड़ दें तो प्रशासनिक स्तर पर ज्यादातर कामचलाऊ व्यवस्था रही। अब फिर से वही हालात बन गए हैं। विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक और एससीईआरटी के अलग-अलग निदेशक हैं, लेकिन बर्तमान में पूर्णकालिक एक ही हैं। विडंबना यह कि इन पदों को भरने के लिए विभाग के पास पात्र अधिकारी हैं ही नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण विभागीय योजनाओं को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। कुछ इसी तरह के हालात स्कूलों के भी हैं। अधिकांश इंटरमीडिएट एवं इंटर कालेज प्रभारी प्रधानाचार्यों के भरोसे हैं। यानी तस्वीर शिक्षकों की है। प्राथमिक से लेकर इंटर तक के स्कूलों में काफी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। कुछ समय पहले शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पठन-पाठन की व्यवस्था को पटरी पर लाने का फार्मूला निकाला था, मगर यह पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुआ। विषय विशेषज्ञ के तौर पर सरकार ने इंटर कालेजों में इनकी नियुक्ति की थी, मगर अतिथि शिक्षक इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में विभाग को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। इस बीच, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का यह बयान उम्मीद जगाता दिख रहा है कि जल्द प्रदेश में 851 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। इन्हें राज्य के पर्वतीय और दूर दराज वाले इलाकों में नियुक्ति दी जाएगी। यदि सरकार ऐसा कर लेती है तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के लिए बड़ी राहत होगी।

कट्टरपंथियों के शिकंजे में बांग्लादेश

तसलीमा नसरीन

ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मध्ययुग में चला गया है, जहां गैर-इस्लामिक लोगों और आधुनिकता के लिए कोई जगह नहीं

बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर मुझे आरोप में लग कि वह छात्रों द्वारा जायज मांग के हक में शुरू की गई एक मुहिम है। इसीलिए उसका समर्थन भी किया। हालांकि उन छात्रों ने किसी को यह भांपने तक नहीं दिया कि इस आंदोलन का नक्शा इस्लामी कट्टरपंथियों और अलगाववादियों ने तैयार किया है। अब इन छात्रों ने पूरे देश में आतंक का माहौल बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में हुए कथित छात्रों ने करीब 1,169 अध्यापकों को अपमानित कर उन्हें नौकरी छोड़ने पर विवश किया। इनमें से अधिकांश अध्यापक हिंदू हैं। उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त रहे हिंदुओं सहित समूचे अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? जिहादी लड़ाके और सजायाफ्ता अपराधी जेलों से रिहा किए जा रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी और जिहादी समूह हिजबुत तहरीर से प्रतिबंध हट गया है। आइएस का झंडा लेकर हिजबुत तहरीर के लड़ाकों ने ढाका में रैली की। अलकायदा के द्विज्ञानिर्देशों पर गठित अलक़ासुल्ला ब्रांग्ला टीम के जिहादी नेता मोहम्मद जशीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया गया है।

इस समय बांग्लादेश की सड़कों पर राजनीतिक दलों से ज्यादा जिहादी इस्लामिक समूह हैं। ये लोग खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं। इससे पहले कि बांग्लादेश पूरी तरह जिहादियों के चंगुल में फंस जाए, कुछ उपाय करने होंगे। इसमें सबसे पहले तो जल्द से जल्द निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव में अवामी लीग सहित सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। चुनी हुई सरकार मजबूत के साथ काम करे की जाने वाली राजनीति खत्म करे। इस प्रक्रिया में जमात-ए-इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता न दी जाए, क्योंकि वह मूल रूप से मजहबी संगठन है। इसी तरह हिजबुत तहरीर, आइएस और दूसरे आतंकी समूहों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिंसक भीड़ द्वारा किए जा रहे कथित न्याय के सिलसिले पर विराम लगे। प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रखनी होगी। संविधान के मजहबी आधार को हटाकर पंथनिरपेक्षता को लागू करना होगा। शिक्षकों एवं छात्रों को कक्षाओं में तथा सैनिकों को बैरकों में लौट जाना होगा। मजहबी आधार पर बने नागरिक कानून खत्म करने होंगे तथा समानता की बुनियाद वाले दीवानी कानून लागू करने होंगे। आजादी के म्यूजियम, राष्ट्रपिता के म्यूजियम तथा मुक्तियोद्धाओं के जिन म्यूजियमों को तोड़ दिया गया, उनका पुनर्निर्माण करना होगा। मदरसों को

अवधेश राजपूत

स्कूलों में तब्दील करना होगा। पाठ्यक्रम में पंथनिरपेक्ष मूल्य एवं आधुनिक शिक्षा अपनानी होगी। सरकार को अपने खर्च सार्वजनिक करने होंगे। सूचना का अधिकार कानून पारित कर पारदर्शिता बढ़ानी होगी।

शेख हसीना सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को लेकर तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हाल-फिलहाल जो हो रहा है, वह भी कतई सही नहीं। शेख हसीना से सत्ता छीनने वालों का भी लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं। चारों तरफ बर्बरता का नंगा नाच चल रहा है। मुहम्मद यूनुस या दूसरे जिम्मेदार लोग भी सार्थक हस्तक्षेप करते नहीं दिखते। उलटे उग्र युवाओं के विध्वंसात्मक और अमानवीय क्रियाकलापों को विभिन्न तरीकों से प्रश्रय दिया जा रहा है। चुनाव को लेकर भी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी नेता तारिक जिया को बांग्लादेश लौटने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सत्ता पर नियंत्रण फिलहाल जमात-ए-इस्लामी के पास है और वह नहीं चाहती कि बीएनपी के नेता लौटें। तारिक जिया के बांग्लादेश लौटने पर जमात का महत्व घट जाएगा। इसलिए जमात चाहती है कि बगैर चुनाव के इसलामी कट्टरपंथियों के साथ देश की सत्ता जितने समय तक उसके पास रहती है, वह उतना ही अच्छा होगा। इसी तरह वे लोग बांग्लादेश में पूरी तरह इस्लाम का शासन लागू कर पाएंगे। दूसरी ओर, शासन की कमान संभाल रहे मुहम्मद यूनुस रहस्यमय व्यक्ति हैं। यूनुस मूल रूप से एनजीओ वाले हैं। सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति से सत्ता संभलेगी? यह तो समय ही बताएगा कि वह कठपुतली हैं या निर्णय लेने के लिए पूरी तरह आजाद? उनका अभी तक का रवैया अच्छे संकेत नहीं देता। उन्होंने 1971 के मुक्तियुद्ध को खारिज कर 2024 के छात्र आंदोलन को मुक्तियुद्ध का नाम दिया है। मुक्तियुद्ध के स्मृति चिह्नों को ध्वस्त कर देने पर सरकार की तरफ से विरोध की आवाज तक नहीं निकली। जब आंदोलनकारी स्मारकों पर हथौड़े बरस रहे थे, तब यूनुस ने कहा था कि मुक्तियोद्धा विजय के उल्लास में डूबे हैं। विध्वंसात्मक कार्रवाइयों का इस निर्लज्ज तरीके से बचाव करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। बांग्लादेश में जितने भी अलगाववादी और कट्टर मुस्लिम हैं, वे वहाबी इस्लाम में यकीन करते हैं। वहाबी इस्लाम सूफीवाद का विरोधी है। इसीलिए, कट्टरपंथी अब सूफियों की कब्र या मजारों को निशाना बना रहे हैं।

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का रवैया प्रचंड भारत-विरोधी है। वहां भारत-विरोधी कई रैलियां हो चुकी हैं। शेख हसीना को शरण देने से लेकर बांग्लादेश में आई बाढ़ का ठीकरा भारत पर फोड़ा जा रहा है। लगता नहीं कि यह सरकार भारत से बेहतर रिश्तों की इच्छुक है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी मात्र आठ प्रतिशत है। हिंदुओं का सफाया किए बगैर ये कट्टरपंथी मानेंगे नहीं। फिर शिया और अहमदिया मुसलमानों की भी खत्म कर देंगे। नास्तिकों, तर्कवादियों और उदारवादियों के लिए भी बांग्लादेश में कोई जगह नहीं होगी। फिर ये लोग आपस में ही लड़कर मरेंगे। उसके बाद भी इन्हें सद्बुद्धि नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मध्ययुग में चला गया है, जहां गैर-इस्लामिक लोगों और आधुनिकता के लिए कोई जगह नहीं। कुछ समय पहले बांग्लादेश की तरक्की की चर्चा हो रही थी और बांग्लादेश को उस स्थिति तक पहुंचाने में शेख हसीना का योगदान कोई कम नहीं। जिहादियों को बेशक उन्होंने जेल में डाला, मगर मजहबी तुष्टीकरण के लिए भी कई काम किए। जैसे मदरसे की डिग्री को मान्यता देने और इस्लामिक संस्कृति का विस्तार। उन्होंने जिनको शह दी, वही उन्हें मात देने वाले साबित हुए।

(बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका प्रख्यात साहित्यकार हैं)

response@jagran.com

सिर उठाते समानांतर सेंसर बोर्ड

राजीव सचान

कहीं कंगना की फिल्म का विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा है ताकि खालिस्तानी आतंकियों की करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे?

कंगना रनौत फिर से चर्चा और विवाद में हैं। इस बार इसका कारण है उनकी फिल्म इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी पर केंद्रित है। इस फिल्म को लेकर उपजे विवाद के कारण छह सितंबर को उसकी रिलीज टल गई है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुछ और समय मांग लिया है। इस पर कंगना ने अपने निराश व्यक्त की है। उनकी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी है और एक जबलपुर उच्च न्यायालय में। आने वाले दिनों में ऐसी कुछ और याचिकाएं दायर हों तो हैरानी नहीं।

किसी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में कुछ गलत नहीं। ऐसा कई फिल्मों के मामले में हो चुका है। इसमें भी कुछ गलत नहीं कि किसी फिल्म से नाराज लोग उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें या फिर इंटरनेट मीडिया पर उसे न देखने की मुहिम चलाएं, जैसे कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा के मामले में देखने को मिला था और हाल में रिलीज वेब सीरीज आइसी-814 को लेकर हो रहा है। ऐसा भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी होता है। इन दिनों मलयालम भाषा की चर्चित फिल्म आडुजीवितम-द गोट लाइफ का खाड़ी के देशों और विशेष रूप से सऊदी अरब में विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि इसमें केरल के मोहम्मद नजीब की रौंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती का चित्रण किया गया है, जिन्हें सऊदी अरब में गुलाम की तरह रखा गया था। सऊदी अरब के कई लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म उनके देश की गलत छवि दिखाती है। वे ऐसा फिल्म देखने के बाद कह रहे हैं। इसके बाद भी खाड़ी के देशों ने इस फिल्म को प्रतिबंधित नहीं किया है। भारत में लोग फिल्म इमरजेंसी को देखे बगैर उसे प्रतिबंधित करने ही नहीं, बल्कि कंगना से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। यह मांग करने वालों में जय संविधान का राग अलापने वाले भी शामिल हैं। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि किसी की फिल्म बनने के 'अपराध' में गिरफ्तार करने की मांग की जाए और वह भी तब, जब फिल्म रिलीज न हुई हो। कंगना की फिल्म का विरोध कई

कंगना रनौत का पोस्टर जलाते लोग। फाइल

सिख संगठन कर रहे हैं। इनमें सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी भी है। पंजाब और कुछ राज्यों में इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं।

सिख संगठनों का कहना है कि फिल्म में सिखों का गलत चित्रण किया गया है, लेकिन आखिर कैसे? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है, क्योंकि वह रिलीज ही नहीं हुई है। जो देख रहा है, वह है इस फिल्म का ट्रेलर। 2 मिनट 53 सेकेंड के इस ट्रेलर में चंद सेकेंड के लिए भिंडरांवाले को यह कहते हुए दिखाया गया है, 'तुम्हारी पार्टी (कांग्रेस) को वोट चाहिए और मुझे चाहिए खालिस्तान।' सिख संगठनों का कहना है कि भिंडरांवाले ने ऐसा कभी नहीं कहा। यह सच हो सकता है, क्योंकि जब कभी भिंडरांवाले से पूछा जाता था कि क्या आप खालिस्तान चाहते हैं तो उसका जवाब होता था, 'मैं नहीं मांग रहा, लेकिन बीबी (इंदिरा गांधी) देगी तो ले लूंगा।' इसका यह मतलब नहीं कि भिंडरांवाले का खालिस्तान से कोई लेना-देना नहीं था। यदि भिंडरांवाले का खालिस्तान से कुछ लेना-देना नहीं था तो उनिया भर के खालिस्तान समर्थक उसका पोस्टर लहराकर उसका गुणगान क्यों करते हैं? क्या ये वही खालिस्तानी नहीं, जो कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका आदि में भिंडरांवाले का पोस्टर लेकर राष्ट्रीय ध्वज जलाते-फाड़ते-रौंदते रहते हैं?

फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर में कुछ सेकेंड का एक और दृश्य है, जिसमें सिख भेष वाले बेंदूकधारी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। यदि किसी को इस पर भी आपत्ति है तो यह हास्यास्पद है। दुनिया जानती है कि खालिस्तानी आतंकियों ने पंजाब में हजारों लोगों को मारा। कहीं कंगना की फिल्म का विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा है ताकि खालिस्तानी आतंकियों की करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे? यह ध्यान रहे कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की तो खूब चर्चा होती है और उचित ही होती है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के हाथों पंजाब में जो हजारों हिंदू-सिख मारे गए, उनकी चर्चा कभी नहीं होती। सिख संगठनों का तर्क है कि कंगना की फिल्म भाईचारा बिगाड़ेगी। गजब यह है कि ऐसा वे भी कह रहे हैं, जो भिंडरांवाले समेत अन्य खालिस्तानी आतंकियों का महिमामंडन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर खालिस्तानी आतंकियों का गुणगान करते समय इन संगठनों को भाईचारे की चिंता क्यों नहीं होती?

फिल्म इमरजेंसी के विरोध ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के बेतुके विरोध की याद दिला दी है। इस फिल्म को देखे बगैर करणी सेना ने उसके खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। जैसी धमकियां आज कंगना को मिल रही हैं, वैसी ही दीपिका पादुकोण को दी जा रही थीं। सड़कों पर हिंसा और हंगामा किया जा रहा था। आखिरकार फिल्म तब रिलीज हो सकी, जब उसका नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया। फिल्म रिलीज होने पर पता चला कि उसमें वैसा कुछ था ही नहीं, जिसे लेकर हंगामा किया जा रहा था। कोई किसी फिल्म से असहमत हो सकता है, लेकिन यह बेतुका है कि उसकी विषयवस्तु से परिचित हुए और उसे देखे बिना उसका विरोध किया जाए। इससे भी खराब बात है फिल्म की रिलीज रोकने के लिए धमकियों का सहारा लेना और सेंसर बोर्ड एवं सरकार को चेताना। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी संगठन समानांतर सेंसर बोर्ड न बनने पाए।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मनिरीक्षण

जीवन में सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण से आशय है-स्वयं के भीतर झांककर देखना एवं अंतर्मन के प्रत्येक कोने का भलीभांति अवलोकन करते हुए प्रत्येक प्रकार के नकारात्मक अवयव को पहचानना। वस्तुतः समय के साथ प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। यह परिवर्तन परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। जहां अनुकूल परिस्थितियां हमारे अंतर्मन को परिष्कृत करने का कार्य करती हैं, वहीं प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे आंतरिक जगत को विकृत करने में योगदान करती हैं। अंतर्मन की यह विकृति अनेक विपरीत मनोदशाओं को जन्म देती है, जो कहीं न कहीं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक बनती हैं। यही कारण है कि हमें समय-समय पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है।

आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भीतर घर कर चुकी बुराइयों एवं त्रुटियों को पहचान सकते हैं एवं उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर आत्मनिरीक्षण करने से हमारी कमियां दूर होने लगती हैं। यह ध्यान रहे कि आत्मनिरीक्षण कभी सापेक्षता के भाव के साथ नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें पूर्णतः निरपेक्ष होना पड़ेगा। निरपेक्षता यानी अपनी कमियों की पहचान में शिथिलता न बरतना। सख्ती एवं अनुशासन के साथ गलतियों को स्वीकार करना एवं भविष्य में उन्हें न दोहराने के लिए कृतसंकल्प होना ही आत्मनिरीक्षण का सही तरीका है।

आत्मनिरीक्षण एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में ही हम स्वयं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लोगों की भीड़ में हमारा मन कभी भी आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत से अनावश्यक बाह्य तत्व हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने व्यक्तित्व की सतत रूप से परिष्कृत करते हुए उन्नति की चरमावस्था तक पहुंच सकते हैं।

प्रेरणा अवस्थी

माइक्रोप्लास्टिक का सर्वव्यापी संकट

सुधीर कुमार

प्लास्टिक प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट ही नहीं है, बल्कि यह खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारी सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है

'माइक्रोप्लास्टिक्स इन सल्ट एंड शुगर' नामक एक हालिया अध्ययन के अनुसार, देश में नमक और चीनी के लगभग सभी ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पाई गई है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भी माइक्रोप्लास्टिक का संक्रमण हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, नमक के नमूनों में प्रति किलोग्राम माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा 6.71 से 89.15 टुकड़े, जबकि चीनी के नमूनों में यह मात्रा 11.85 से 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम तक पाई गई है।

माइक्रोप्लास्टिक का सर्वव्यापक होना बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है। आज प्लास्टिक लगभग हर जगह व्याप्त है। कारखानों से बाजार और फिर बाजार से जो प्लास्टिक हमारे घरों तक आता है, वह उपयोग के बाद पर्यावरण में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहकर भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, 1950 में दुनियाभर में फैले प्लास्टिक के कण मानव और जीवों के श्वसन तंत्र के जरिये उनके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक (आकार पांच मिलीमीटर से कम) और नैनोप्लास्टिक (एक माइक्रोन से छोटे) के रूप में प्लास्टिक के छोटे कणों का संकेंद्रण गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। प्लास्टिक के असंख्य टुकड़े पृथ्वी का औसत ताप बढ़ाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या अधिक विकराल हो रही है।

माइक्रोप्लास्टिक का यह संकट न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से चिंताजनक है, बल्कि इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दे भी उभर सकते हैं। इस संकट के समाधान के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और सुरक्षित विकल्पों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना होगा और अन्य कारगर विकल्पों की ओर रुख करना होगा। साथ ही, खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक की मौजूदगी पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अपनी भूल सुधारे पाकिस्तान

'बलूचिस्तान संकट से सहमा पाकिस्तान' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में विवेक काटजू ने पाकिस्तान की स्थिति का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया है। बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे को छेड़ने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बचता। दुनिया देख रही है कि भारत के नियंत्रण में आने वाला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गुलाम जम्मू-कश्मीर की क्या स्थिति है। दोनों इलाकों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद तो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की प्रगति को नए पंख लगे हैं। ऐसे में, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि वह कश्मीर के मुद्दे को भुलाकर बलूचिस्तान पर ध्यान दे। विभाजन के दौरान उसने बलूचिस्तान के शासकों के साथ विश्वासघात किया, लेकिन अब वहां की जनता के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाकर उस भूल सुधार की दिशा में बढ़ना चाहिए। यदि पाकिस्तान ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक न लेते हुए बलूचिस्तान में दमन एवं उत्पीड़न जारी रखा तो फिर इतिहास खुद को वैसे ही दोहरा सकता है जैसे पूर्वी पाकिस्तान की पहचान को पीछे छोड़कर नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। उसका एक और विभाजन उसकी मुश्किलें और बढ़ाने का ही काम करेगा।

केशव तिवारी, आजमगढ़

अपने कार्यकर्ताओं को अवसर दे भाजपा

''भानुमति का कुनबा बनती भाजपा'' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राज कुमार सिंह ने बहुत सटीक बात कही है। आज राजनीति में भाजपा जिस प्रकार के समझौते कर रही है वह भविष्य में उसके लिए ही हानिकारक साबित होंगे। दूसरे राजनीतिक दलों के नेता अपने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा उनका आगे बढ़कर स्वागत करती है। केवल स्वागत ही नहीं उन्हें टिकट देकर चुनाव में अपना प्रत्याशी भी बनाती है। ऐसे जो लोग वर्षों से भाजपा में विषम परिस्थितियों में भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं, वे अपने को ठगा महसूस करते हैं। एक दिन कुंठाग्रस्त व उदासीन हो जाते हैं। राजनीति में यह माना जाता है कि जीतने वाले को ही प्रत्याशी बनाया जाता है। दो-चार सीटों में विपक्षी प्रत्याशी को देखते हुए जैसे को तैसा मानते हुए समझौता करना पार्टी की मजबूरी मानी जा सकती है, परंतु अधिकांश बाहर से आए नेताओं को प्रत्याशी बना देना भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे धीरे-धीरे पार्टी व संगठन में कार्यकर्ताओं के मन खराब होते जाएंगे और वे अधूरे मन से या फिर केवल ठिकाना के काम करेंगे। इससे अंदर ही अंदर पार्टी या संगठन में टूट शुरू हो सकती। पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी घोषित करना चाहिए, उनको ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अन्यथा भविष्य को लेकर जो आशंकाएं लेखक ने प्रस्तुत की हैं, वे भाजपा के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होंगी। अभी वक्त है भाजपा नेतृत्व उपयुक्त कदम उठाकर इसे सुधार ले।

डा. हेमेंद्र राजपूत, नई दिल्ली

भारत को बांटने की साजिश

कुछ लोग भारत में क्षेत्र, संप्रदाय, ओबीसी एवं एससी-एसटी जैसे मुद्दे पर फूट डालने की कोशिश में हैं। वे भारत के बहुसंख्यक समुदाय के मुख्य प्रेरणा स्रोत सनातन धर्म पर लगातार चोट कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली है। इस लोकसभा चुनाव में यह नीति कुछ हद तक सफल भी रही। इससे उत्साहित होकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता इस नीति को और जोर-शोर से आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। देश को आंतरिक और बाह्य स्तर पर कई खतरे हैं। 1947 में हुए देश विभाजन का दंश आज भी महसूस किया जा सकता है। समाज को जाति और अन्य वर्गों में बांटना विनाशकारी सिद्ध होगा। आज देश को ऐसे राजनेता, धार्मिक गुरु एवं समाज सुधारक की जरूरत है जो समाज को किसी भी तुच्छ आधार पर बंटने न दे। देश में जो भ्रम की राजनीति फैलाई जा रही है उसे निरस्त कर सके।

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

सम्पादकीय

भारत में खाद्य तेल की बढ़ती खपत और आयात निर्भरता

भारत खाद्य तेलों के अहम उत्पादकों में से एक है। दुनिया के कुल तिलहन रकबे का करीब 15-20 फीसदी भारत में है। जबकि वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी 6-7 फीसदी और खपत में हमारा योगदान 9-10 फीसदी है। इसके बावजूद देश की खाद्य तेल खपत का करीब 57 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। ऐसे में जाहिर है हम वैश्विक खाद्य तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव को लेकर संवेदनशील रहते हैं और आपूर्ति का बाधित होना भी हमें दिक्कत देता है। इस वर्ष जुलाई में हमने रिकॉर्ड मात्रा में खाद्य तेल खरीदा क्योंकि आकर्षक कीमतों के चलते रिफाइनरों ने पाम ऑयल और सोया ऑयल की खरीद बढ़ा दी। इस संबंध में नीति आयोग ने हाल ही में एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है जिसमें तिलहन आयात पर भारत की भारी निर्भरता का जिक्र किया गया है और भविष्य के पूर्वानुमान पेश किए गए हैं। उदाहरण के लिए 2022-23 में भारत ने 1.65 करोड़ टन खाद्य तेल आयात किया। घरेलू उत्पादन देश की कुल जरूरत के केवल 40-45 फीसदी की ही पूर्ति कर पा रहा है। वहीं देश के खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़कर 19.7 किलो प्रति वर्ष हो चुकी है। 1990 के दशक में तिलहन क्रांति (येलो रिवॉल्यूशन) की मदद से तिलहन के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता हासिल की गई थी वह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकी। इस संदर्भ में रिपोर्ट में फसल उत्पादन में विविधता लाने और मुख्य अनाजों के अलावा अन्य फसल उपजाने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। बहरहाल, बिजली और उर्वरक सब्सिडी सहित तमाम प्रोत्साहन धान और गेहूं की खेती के पक्ष में झुके हैं। इससे किसान दूसरी फसलों को नहीं अपनाना चाहते। पंजाब के किसानों को अब खरीफ के सीजन में कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के क्रम में 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। परंतु जैसा कि कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी तथा अन्य लोगों ने संकेत किया, केवल इतना करना पर्याप्त नहीं है। धान और तिलहन के बीच मुनाफे का अंतर इतना अधिक है उसकी भरपाई इस राशि से नहीं हो पाएगी। सुझावों के मुताबिक धान की खेती से दूरी बनाने के लिए कम से कम 35,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि देनी होगी। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तिलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए ताकि किसानों के लिए बाजार जोखिम कम किया जा सके। आयात का बोझ कम करने के लिए नीति निर्माता पाम की खेती बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देश में पाम ऑयल का उत्पादन 2010-11 के 79,000 टन से बढ़कर 2021-22 में 3.60 लाख टन हो गया। बहरहाल पाम के पौधरोपण के लिए वनों की कटाई को देखते हुए यह चिंता का विषय है। पूरे दक्षिण-पूर्वी एशिया में ऐसा देखा जा रहा है। हालांकि जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुपयोगी भूमि का इस्तेमाल एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। हमारी खानपान की आदतों और खाद्य खपत के आधार पर रिपोर्ट में प्रस्तुत अनुमानों के मुताबिक 2030 तक खाद्य तेल के मामले में मांग और आपूर्ति का अंतर 2.95 करोड़ टन होगा।

सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयन्ती

सर्वसुलभ इंसाफ की उम्मीद को पंख लगे

सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती के अवसर पर सभी ने शीघ्र न्याय की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति से तौबा करने का वक्त आ गया है? न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए। यही वजह है कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा, उसे देश की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए अलार्म बेल माना जा सकता है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि जब तक न्यायपालिका देश के आम लोगों को सहजता से इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता मुहैया नहीं कराती, तब तक उसका काम पूरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वीकारा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिये बड़ी चुनौती है।

ललित गर्ग

यह सुखद, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक अवसर ही है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 75 साल का गरिमामय सफर पूरा कर लिया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को यादगार बनाने के लिये बाकायदा डाक टिकट व सिक्के भी हाल ही में जारी किये गए और विभिन्न आयोजनों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के विषय पर गंभीर मंथन भी हुआ, ऐसे ही आयोजनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस बात पर बल दिया कि समय पर न्याय मिलने से ही न्याय का वास्तविक लक्ष्य पूरा होता है। 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है' वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।'

अदालतों से न्याय पाने की प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है और इसमें बेहिसाब वक्त लगता है। इन दोनों ही का नतीजा इसी रूप में सामने आता है कि इंसाफ की आस लेकर अदालत पहुंचा व्यक्ति फैसला आने तक टूट चुका होता है। इसीलिये राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि किसी गंभीर अपराध से जुड़े मामले का फैसला आने में 32 साल लग जाए तो लोगों को ऐसा लगना असाधारिक नहीं कि शायद अदालतें ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। राष्ट्रपति ने किसी खास मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा अजमेर में पॉक्सो अदालत द्वारा इसी 20 अगस्त को सुनाए गए फैसले की तरफ था। एक चर्चित सेक्स स्कैंडल से जुड़े इस मामले में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने में 32 साल लग गए। यह अपनी तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। बेहद गंभीर और वीभत्स अपराध के सैकड़ों ऐसे मामले हैं, जो अदालतों में बरसों से लंबित पड़े हैं।

लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश-निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हों? प्रश्न यह भी है उन्हें समय पर त्वरित न्याय कब मिल सकेगा? दुर्भाग्य से ये प्रश्न दशकों से अनुत्तरित है। इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के

खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके। निस्संदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। पूरे देश में अपराधियों को शीघ्र व सख्त दंड देने की मांग की जा रही है। यदि पुलिस व जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पहुंचें तो गंभीर मामलों में आरोप जल्दी सिद्ध हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मजबूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, गरीबों के अधिकार एवं सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ़ कमज़ोर समूहों का योग्य संरक्षक और करोड़ों नागरिकों के लिए आखरी उम्मीद वाला संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले 75 वर्षों में ज्यादातर समय भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा और क़ानून के शासन को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था के सामने अनेक जटिल स्थितियां भी हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बढ़ते केसों की संख्या, जवाबदेही, भ्रष्टाचार एवं विलम्बित न्याय आदि। न्याय को लेकर अदालतों तक आम नागरिकों की पहुंच एवं खर्च के मुद्दों और इसी तरह की दूसरी चीजों के मामले में सुधार के बारे में न्यायपालिका की अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हमारे कानूनों की भावना है-नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले है। निश्चित ही डी.वाई. चंद्रचूड़ न्याय-प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं तो उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दिये हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देती रही है। न्याय के इंतजार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80 हजार है। उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या 62 लाख के करीब है और निचली अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़। इसका अर्थ है कि लगभग पांच करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। देश में तीनों स्तरों पर लंबित मामले न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीके को पूरा करेंगे। तब आप यह समझ पाएंगे कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके विशेष कुशल होने और दूसरों तरह, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम ने किसी हमारे राशन में और जरूरत पूरी की तुलनाओं जैसा समाधानकारक उत्तर की समस्त करेंगे, बीमार पहलुओं संबंधों में भी, जहां हम समाधानकारक सही सहाय और कठिनाई से लाभ प्रदान करेंगे

मेष
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

वृष
किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

मिथुन
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

कर्क
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है। दोस्तों के साथ मुलाकात होगी।

सिंह
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

कन्या
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

तुला
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

वृश्चिक
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

धनु
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

मकर
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

कुंभ
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

मीन
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

शख्सियत

'सामाजिक सेवा और कुछ भी नहीं आपके मन के कर्तव्य और भावनाओं का एक जीता जागता वजूद है इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं सामाजिक सेवाओं से जुड़ने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है बस उसके मन में भावना यह हो कि वह सच में समाज की सेवा कर रहा है'

नमस्कार दोस्तों हमारी आज शख्सियत कॉलम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं श्री अशोक गुप्ता। इनका जन्म 28 जून 1952 को अलवर में रायबका वालों के मेठी परिवार में रामदयाल जी के घर हुआ । पिताजी की 1920से कंडलगंज में आढ़त की दुकान थी। पिताजी के परिवार में ये 4 भाई व 1बहन हैं। तीनों भाई व्यापार में रहे। इनके दो पुत्र व एक पुत्री हैं। बड़ा बेटा अभिषेक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटा बेटा अभिनव मेठी,बहु जयश्री मेठी दोनों दंत चिकित्सक हैं जो सेवा कार्यों में भी अग्रसर रहते हैं। इन्होंने नवीन माध्यमिक उच्चतर विद्यालय से 1969 में स्कूल के साइंस मैथ्स विषय से परीक्षा उत्तीर्ण की। अलवर कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद कुरुक्षेत्र के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज 1970 में प्रवेश लेकर 1975 में सिविल इंजीनियरिंग में तृतीय पोजिशन के साथ उत्तीर्ण की। जनवरी 1976 में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में प्रथम पोस्टिंग बीकानेर में हुई। वर्ष 1978 में मैरिट के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर पदोन्ती हुई। करीब 25 वर्ष की सफल सर्विस के बाद फरवरी 2004में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर

अशोक गुप्ता
(वरिष्ठ श्रेणी के इंजीनियर व प्रमुख समाजसेवी)

पदोन्नती हुई। वर्ष 79 से 83 एवम 89 से 95 तक जिला परिषद् अलवर में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत रहे। उस समय इन्होंने पक्के कार्यों के निर्माण पर जोर देते हुए अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे भवन रहित 2000 से अधिक विद्यालयों में, पंचायत भवनों, औषधालयों सामुदायिक भवनो आदि में कमरो का निर्माण करवाया। सिंचाई विभाग मे नगर भरतपुर, डीग , धौलपुर, जयपुर आदि स्थानों पर पदस्थापित रहे। वर्ष 2004 में भरतपुर में पदस्थापान के दौरान मैं अपना घर आश्रम के प्रेरणा स्त्रोत डॉ बी एम भाद्वाज जी के सम्पर्क में आये। उनकी समाज से वंचित लोगों की सेवाओं को देखते हुए ये भी तभी से अपना घर आश्रम की सेवाओं से जुड़ गए। वर्ष 2012 में सेवा निवृत्त होने पर अलवर के अपना घर आश्रम के खुलने पर इन्होंने आश्रम में शुरू से सचिव पद का दायित्व निभाते हुए 2021तक कार्य किया। अप्रैल 2021से आज तक अपना घर आश्रम के अध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे हैं। महिला आश्रम के अध्यक्ष पद का दायित्व भी अप्रैल 2021से अगस्त 2023 तक निभाया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था दी इन्टीटयूट ऑफ इंजीनियर्स के अलवर सेन्टर में 2015से 2017 तक सचिव पद पर, 2022 से आज तक अध्यक्ष पद का दायित्व सम्भाल रहे हैं । चन्द्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति में कार्य कारिणी सदस्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। वर्ष 2012 से आज तक गर्मियों में स्टेशन और बिजली घर चौराहे पर राहगीरों को जल सेवाओं में भागीदारी निभाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म लीन रामसुखदास जी महाराज जी के पदचिन्हों पर चलने वाले विलक्षण सन्त स्वामी विजयानंद जी गिरी से प्रभावित हैं और उनके जहां प्रवचन होते हैं वहां जाकर उनके प्रवचनो का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इस उम्र में भी एक अलग जज्बे के साथ सामाजिक सेवा करने वाले अशोक गुप्ता ने अपने मन की बात पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि मेरी लोगों से विनती है कि मनुष्य जीवन ईश्वर की विशेष कृपा से मिला है इसलिए इसे दूसरों की सेवाओं और अपने उद्धार के लिए भगवत भक्ति में लगाना चाहिए।अंत में मेरी इच्छा है कि मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दें कि मैं मरते दम तक असहाय, लाचारिस,दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहूं। सच में श्री अशोक गुप्ता एक सराहनीय प्रयास करते हुए एक शख्सियत के रूप में समाज में नजर आ रहे हैं । दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करती है।

जय हिंद

आज का इतिहास

4 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जय सिंह संधि पर 1665 की हस्ताक्षर हुए।
- स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजिल्स की स्थापना 1781 में की गयी।
- महात्मा गांधी ने 1888 में इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरु की।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने 1944 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया।
- 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की चपेट में 1967 को आया महाराष्ट्र का कोयना बांध, 200 से ज्यादा लोगों की मौत।
- उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह का देहावसान 1969 में हुआ ।
- 73 सालों के बाद समुद्र में 1985 को डूबे जहाज टाइटेनिक की तस्वीरें सामने आई थीं। टाइटेनिक दुर्घटना में इस जहाज पर सवार 1,500 लोग मारे गए थे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 को आयरलैंड के डबलिन में स्वीकार किया कि मोनिका लेविंस्की के साथ सम्बन्ध कायम करना बड़ी गलती थी, डरबन में 12वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सम्पन्न।
- लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 1998 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पी.एच.डी करने के दौरान इसे विकसित किया था।
- ईस्ट तिमोर में 1999 को सम्पन्न हुए जनमत संग्रह में 78.5 प्रतिशत जनता ने इंडोनेशिया से स्वतंत्रता के पक्ष में अपना मत प्रकट किया।
- श्रीलंका के उत्तरी जाफना के बाहरी सीमाओं पर 2000 में श्रीलंका सेना तथा मुक्ति चीते के बीच हुए संघर्ष में 316 लोग मारे गये।
- सिडनी में 2000 को 27वें ओलम्पिक खेलों का शुभारम्भ।

विशेष आलेख

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सामरिक सूचना के उजागर होने के खतरे

संजीव ठाकुर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका, रूस ,चीन, जापान और पश्चिमी देश जिस तरह गोपनीय तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे विकासशील देशों की रक्षा सूचना के उजागर होने के खतरे बढ़ गए हैं इसमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सामरिक सूचना के उजागर होने के खतरे बढ़ गए हैंइ्र जब तक इस विषा में पूरी तरह पारंगत नहीं हो जाते इस पर विशेष सावधानी रख का उपयोग किया जाना चाहिए अन्यथा इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। सूचनाओं विदेशी तत्वों के हाथों में जा सकती है इसके अलावा आतंकवादी संगठन इसका उपयोग कर भारी तबाही मचा सकते हैं। निसंदेह यह दौर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का दौर है पर इसका उपयोग अतिरिक्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिएइ्रअब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नफज़ पड़कर आपके मस्तिष्क की बात तुरंत पकड़कर उस पर अमल करने लगेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल्स रेट द्वारा आपके मन की हर बात जाने में सक्षम हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को वैज्ञानिकों ने मानव की सहायता के लिए और देश की बेहतरी के लिए अविष्कार किया है। अभी तक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इजरायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफी आगे पर अब खाड़ी के देशों विगत 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति केवल तेल के कुए पर न रह कर अन्य योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है और आश्चर्यजनक रूप से यूएई ,सऊदीअरबिया, कतर, मिस्र ,जॉर्डन,मोरक्को और अन्य देशों में यूरोप की तुलना में अब और ज्यादा खर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को अपने देश में बहुत मजबूत बना लिया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने फायदे हैं उससे ज्यादा विकासशील देशों के लिए यह नुकसान देह भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पल्स रीडिंग और मानसिक विचारधारा को केवल थ्रैब इंप्रेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिवाइस पढ़ कर उस पर अमल कर सकता है।इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका तथा यूरोपीय देश अब तक दुश्मन की अनेक सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त कर उसका सामरिक उपयोग करने में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रूस अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर मिसाइल दागने में यूक्रेन यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा है और अब तक यूक्रेन यूरोपीय तथा नाटो देश की मदद से इसी तकनीक के सहारे रूस के विरुद्ध अब तक टिका हुआ है वैसे तो यूक्रेन और रूस का युद्ध में काफी नुकसान हुआ है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं विकासशील देशों में इस टेक्नोलॉजी का विकास अभी काफी एडवांस नहीं है इन परिस्थितियों में उनके लिए उनके सामरिक महत्व की चीजें छुपाना दुश्मन देशों के सामने कठिन हो जाएगा और उनकी खुफिया जानकारी शक्तिशाली देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक सूत्र प्राप्त करने के बाद ही पूरी प्राप्त कर सकते हैं. खाड़ी के देश जिनमें सऊदी अरबिया, कतर ,मिस्र, जॉर्डन, यूएई अपने बजट का 34% बढ़ा हुआ हिस्सा एआई तकनीक पर लगातार कर रहे हैं। खाड़ी के देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी भविष्य की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे वे तेल की कमाई से हटकर अन्य साधनों से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकेंइ्र यूं एई पहला देश है जिसने 2017 ने इस तकनीक को अपनाया था इसके बाद खाड़ी के देशों में अब टेक्नोलॉजी को अपनाने में होड़ हो गई हैइ्र यह सभी देश एआई टेक्नोलॉजी पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैइ्र दूसरी तरफ यदि इसका इस्तेमाल अति विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया तो इसका दुरुपयोग जिन देशों के पास इन टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है वह पूरी जानकारी निकालने में सक्षम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यूरोपीय देश न सिर्फ सामरिक महत्व की चीजों में कर रहे हैं बल्कि मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान में भी पूरी तरह हो रहा है और इससे बहुत फायदे भी मिल रहे हैइ्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रजाति के लिए जितना फायदेमंद है दूसरी तरफ उतना ही नुकसान दे और इससे वैश्विक शांति को खतरा भी हो सकता हैइ्र राइट एक्टिविस्ट मानते हैं कि रोबोट की तरह इस तरह की विज्ञान पर आधारित चीजें माननीय प्रजाति को खत्म कर सकती है बल्कि उनकी चिंता डेटा सुरक्षा प्रपो गेंड सर्विलांस के विरुद्ध होने वाले नुकसान पर भी ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खाड़ी के देशों ने एआई के इस्तेमाल पर दिशा निर्देश तय कर उसे जारी किया है हालांकि इस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

यौन उत्पीड़न को हमें किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं करना चाहिए। अपराधी भले ही करीबी क्यों न हो? -एना नवारो

किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सात योजनाओं को स्वीकृति दी है, जो स्वागतयोग्य है। इनमें महत्वाकांक्षी डिजिटल कृषि मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेकिन देश के समग्र कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक डिजिटल सार्वजनिक मंच तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

कृषि में डिजिटल क्रांति

किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सात योजनाओं को स्वीकृति देना स्वागतयोग्य है और यह ग्रामीण व कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। इन योजनाओं में 2,817 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी डिजिटल कृषि मिशन इसलिए विशेष उल्लेखनीय है कि यह न केवल किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने में सहायक होगा, बल्कि कृषि के पारंपरिक तरीकों में आमूल-चूल बदलाव लाएगा। यह मिशन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों के लिए योजनाबद्ध कृषि मंत्रालय की गतिविधियों का एक हिस्सा भी है, जो अगले दो वर्षों यानी 2025-26 तक पूरे देश में शुरू किया जाएगा। इसकी शुरुआत का संकेत तभी मिल गया था, जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इससे जुड़ी पायलट परियोजनाओं की कामयाबी का जिक्र किया था। योजना के तीन बुनियादी स्तंभ हैं, जिनमें पहला एग्री स्टैक है, जिसमें किसानों की रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री इत्यादि शामिल हैं। दूसरा, एग्री डीएसएस यानी कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, जिसका हाल ही में अनावरण भी किया गया था, फसलों, मिट्टी, मौसम व जल संसाधनों आदि पर रिमोट सेंसिंग जानकारी को एकत्र करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाएगी। तीसरी बात यह कि मिशन के तहत 1.42 लाख करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि की मिट्टी की प्रोफाइल का विस्तृत मानचित्र तैयार करने की परिकल्पना की गई है। एक कृषि प्रधान देश के लिए इतनी व्यापक योजना का क्रियान्वयन निस्संदेह एक दुष्कर कार्य होगा। दरअसल, देश के कृषि क्षेत्र में किसानों और उनकी भूमि के संबंध में जो भी रिकॉर्ड हैं, वे सब विभिन्न राज्यों के कई विभागों में बिखरे हुए हैं। इस पूरी जानकारी को एक मंच पर लाना ही डिजिटल मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। योजना में किसानों के पहचान-पत्र बनाने की बात भी शामिल है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं, कर्ज इत्यादि का फायदा उठाने में सहूलियत हो। डिजिटल कृषि मिशन डाटा आधारित कृषि को प्रोत्साहन देगा, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए सही सलाह, मौसम की सटीक जानकारी, मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण और फसलों के स्वास्थ्य की डिजिटल निगरानी जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं सुलभ होंगी। दरअसल, डिजिटल कृषि मिशन, आधार, डिजिलॉकर, यूपीआई जैसी दूसरी ई-गवर्नेंस पहलों की भांति एक दूरदर्शी योजना है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की पहुंच व किसानों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के अलावा कृषि योग्य व बंजर भूमि और फसलों से जुड़े सभी आंकड़े व जानकारी को एक सूत्र में पिरोकर देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के लिए एक व्यापक डिजिटल सार्वजनिक मंच तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

लगातार लड़ाई की जरूरत है

मलयालम फिल्म उद्योग को लेकर आई जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट स्तब्ध करने वाली है। हॉलीवुड और बॉलीवुड, जैसे हाई प्रोफाइल फिल्म उद्योगों में भी महिलाओं का शोषण होता रहा है। इस मामले में बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन जब तक ठोस नियमन नहीं होता, तब तक लगातार लड़ने की जरूरत है।

अद्वैता काला
पत्रकार, फिल्म कथा लेखक एवं चर्चित उपन्यासकार

प्रतिशोध की कहानियों ने हमेशा फिल्म निर्माताओं और सिनेमा दर्शकों को आकर्षित किया है। लेकिन 17 फरवरी, 2017 में मलयालम अभिनेत्री के साथ जो हुआ, उससे न केवल मलयालम फिल्म उद्योग, बल्कि पूरा देश सदमे में है। हाल ही में उस घटना के संबंध में जब जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट उजागर हुई, तो एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया।

यह सब तब शुरू हुआ, जब अभिनेत्री शूटिंग के बाद घर लौट रही थी। जिस कार में वह यात्रा कर रही थी, उसे रोककर पांच आदमी उसमें सवार हो गए। अगले दो घंटों तक उन्होंने उसका यौन शोषण किया और इस भयावह घटना को रिकॉर्ड किया। उस हमले के बाद वह अभिनेत्री अपने एक सहकर्मी के घर पहुंची, जिसने उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। इस तरह यह सात साल पुरानी कहानी शुरू हुई, जो अब भी सुर्खियों में है और फिल्म जगत की चमक-दमक के पीछे की अनैतिकता को उजागर कर रही है, क्योंकि मलयालम सिनेमा की और भी महिलाओं ने साहस जुटाया और अपने स्तब्ध कर देने वाले कटु अनुभवों के साथ आगे आईं।

यह आंदोलन विकसित और प्रगतिशील माने जाने वाले मलयालम फिल्म उद्योग के बारे में बहुत कुछ बताता है। लेकिन यह मानना भोलापन होगा कि अन्य उद्योगों में ऐसा नहीं होता, जिसमें हॉलीवुड भी शामिल है, जिसे प्रगतिशील मूल्यों वाला फिल्मोद्योग माना जाता है।

हॉलीवुड में मीटू आंदोलन ने इस उद्योग के सबसे कायर और कामुक लोगों में से एक हार्वे वीनस्टीन के नाम को उजागर किया, जो अब अपने अपराधों के लिए जेल में है। फिर भी दशकों तक वह वैश्विक मनोरंजन उद्योग का चहेता था, उसने ऑस्कर पुरस्कार जीते और खूबसूरत अभिनेत्रियां उसके साथ थीं। यह सब तब हो रहा था, जबकि इस व्यवसाय के अंदरूनी लोग उसकी गतिविधियों और शोषण के बारे में जानते थे।

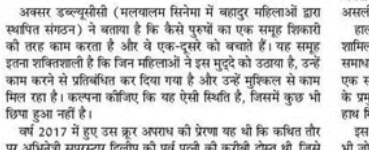

अक्सर डब्ल्यूसीसी (मलयालम सिनेमा में बहादुर महिलाओं द्वारा स्थापित संगठन) ने बताया है कि कैसे पुरुषों का एक समूह शिकारी की तरह काम करता है और वे एक-दूसरे को बचाते हैं। यह समूह इतना शक्तिशाली है कि जिन महिलाओं ने इस मुद्दे को उठाया है, उन्हें काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें मुश्किल से काम मिल रहा है। कल्पना कीजिए कि यह ऐसी स्थिति है, जिसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।

वर्ष 2017 में हुए उस क्रूर अपराध की प्रेरणा यह थी कि कथित तौर पर अभिनेत्री सुपरस्टार दिलीप की पूर्व पत्नी की करीबी दोस्त थी, जिसे उसने अपने विवाहेतर संबंध के बारे में बताया, जिसके कारण तलाक हो गया। आरोप है कि दिलीप को लगता था कि पूर्व पत्नी से तलाक में इस अभिनेत्री का हाथ है। इसलिए वह गुस्से से आगबबूला हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। यह एक सी ग्रेड फिल्म की पटकथा की तरह लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमला वास्तव में हुआ था और चौंकाने वाली यह घटना याद दिलाती है कि फिल्म उद्योग में पुरुष वर्ग न केवल बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि फिल्म उद्योग के अंधेरे हिस्से में भी हावी है।

हाल ही में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन पर एक युवा प्रशंसक, जिसने उसकी प्रेमिका को अश्लील संदेश भेजा था, की हत्या का आरोप लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह अब जेल में है और हाल ही में कुर्सी पर आराम से बैठकर सिगरेट पीते हुए उसकी तस्वीर सामने आई थी। यह आरोप लगाया गया है कि जिस पिटाई के कारण उस व्यक्ति की मौत हुई, वह दर्शन के आदेश पर उसके 'प्रशंसकों' द्वारा की गई थी। फिर से अधिकार की एक भ्रामक भावना और यह धारणा पसरी कि दुनिया और विशेष रूप से महिलाएं उनके इशारों पर नाचने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन इस तरह के खुलासे हमें कहां ले जाएंगे? बेशक ऐसी घटनाओं की अभी बाढ़ नहीं आई है और ऐसी घटनाएं कभी-कभार ही सामने आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह शोषण अन्य फिल्म उद्योगों में नहीं होता है, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल बॉलीवुड भी शामिल है। अब तक, यौन शोषण की रिपोर्ट के मामलों को 'गॉसिप' या 'विवादास्पद' महिलाओं द्वारा ध्यान आकर्षित करने का हथकंडा बताकर खारिज कर दिया गया है।

हालांकि, इसमें बदलाव आना तय है। मीटू के बाद पहली बार, जो भारत में असमय खत्म हो गया, ऐसा लगता है कि इन प्रथाओं पर लगाम लगाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जब यह बांध टूटेगा, जैसा कि मलयालम फिल्म उद्योग में हुआ है, तो जिन लोगों को हम आम जनता ने आदर्श के रूप में सम्मान दिया है, उनमें से कई लोगों की असली पहचान सामने आ जाएगी।

हालांकि यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसमें विवेकवान पुरुषों भी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर पुरुष समस्या का हिस्सा हैं, तो वे समाधान का भी हिस्सा हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक समाज के रूप में हम आज भी पुरुष प्रधान हैं, और फिल्म उद्योग के प्रमुख सदस्यों के रूप में शक्तिशाली पुरुषों को महिलाओं के साथ हाथ मिलाकर सिस्टम को साफ करने की जरूरत है।

इस एकजुटता की सार्वजनिक घोषणाओं के साथ-साथ इस बात पर भी जोर दिया जा सकता है कि वे जिस फिल्म सेट पर काम करते हों, वह उच्च दिशा-निर्देशों का पालन करता हो और महिलाओं के लिए कार्यस्थल सुरक्षित हो। अगर वीएफएक्स और वैनिटी वैन पर भारी बजट खर्च किया जा सकता है, तो महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुलभ शौचालय, आराम करने की जगह और सुरक्षित यात्रा के लिए बजट क्यों नहीं बनाया जा सकता?

मैं चाहे जितना भी यह मान लूं कि मैं एक सशक्त महिला हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी मैं रात के दो बजे अकेले हाईवे पर कार में नहीं जा सकती, लेकिन मेरे पुरुष साथी ऐसा कर सकते हैं। यही नहीं, मैं तो सुबह आठ बजे भी हाईवे पर अकेले गाड़ी नहीं चला सकती। मात्र दो महीने पहले जब मैंने ऐसा किया, तो हाईवे पर कुछ किलोमीटर तक पुरुषों से भरी एक कार ने मेरा पीछा किया। यह मेरी और मेरे जैसी अन्य कई महिलाओं की सच्चाई है, और जब तक यह स्थिति नहीं बदल जाती, महिलाओं की लड़ाई जारी रहेगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

चार्ल्स डार्विन

सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। लेकिन हम लाभ के लिए प्रकृति में मौजूद सभी प्राणियों के प्रति क्रूर हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा पाप है, इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा।

पशुओं से करें प्रेम, जीवन तनावमुक्त हो जाएगा

एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक दयालु किसान रहती थी। लिली को सभी प्राणियों से बहुत प्यार था, चाहे वे बड़े हों या छोटे। उसने अपना पूरा जीवन अपने जानवरों की देखभाल करने और उनके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आने के लिए समर्पित कर दिया। लिली जीवन का अर्थ समझ पाई थी। कई लोग न जानवरों से प्रेम करते हैं और न ही इन्सानों से। जटिल व निराशा भरी दुनिया में, हमारे पशु साथी हमें स्नेह और वफादारी से भर देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगता है, मनुष्य और पशु के बीच सुख-दुख महसूस करने की क्षमता में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। कोई भी जानवर, जो अच्छी तरह से सामाजिक प्रवृत्तियों से संपन्न है, जिसमें माता-पिता और संतान के स्नेह भी शामिल हैं, अनिवार्य रूप से एक नैतिक भावना या विवेक प्राप्त करेगा।

आपने देखा होगा कि हमारे आसपास के कई जानवर, जो कई बार आपके दरवाजे पर कुछ खाने के लिए आ जाते होंगे, उनको पता होता है कि उन्हें कहां प्रेम मिलेगा। जब कोई व्यक्ति अपने कुत्ते से बात करता है या उसे देखता है, तो हम इन हरकतों का अंतिम निशान उसकी दुम के हल्के से हिलने में देखते हैं, शरीर की कोई और हरकत नहीं होती और कान भी नीचे नहीं होते। कुत्ते अपने मालिकों से दुलार पाने और थपथपाए जाने की इच्छा से भी अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। कुत्ते के खुश और उदास व निराश होने की स्थिति में उसकी चाल-ढाल और हाव-भाव में अंतर स्पष्ट होता है। उदास या निराश होने पर उसके सिर, कान, शरीर, पूंछ और तालू लटक जाते हैं और आंखें सुस्त हो जाती हैं। इसके अलावा जब कुत्ते स्नेह महसूस करते हैं, तो वे सभी आवाजों को अनसुना करने के लिए अपने कान झुका लेते हैं, ताकि उनका पूरा ध्यान अपने मालिक के दुलार पर केंद्रित हो सके। कुत्तों के पास अपना स्नेह दिखाने का एक और शानदार तरीका है, वह है-अपने मालिकों के हाथ या चेहरे चाटना। कुत्ते अपने स्नेह की अभिव्यक्ति में होंठों को थोड़ा-सा घुमाते हैं, और अपनी हरकतों के बीच मुस्कराते और सूंघते हैं, जो एक तरह से हंसी जैसी लगती है। वहीं मानव जाति के कुछ भाव, जैसे कि अत्यधिक भय के प्रभाव में बालों का खड़ा हो जाना, या उग्र क्रोध के कारण दांतों का खुल जाना, शायद ही समझ में आ सकते हैं, सिवाय इस विश्वास के कि मनुष्य कभी बहुत निम्न और पशु-जैसी स्थिति में रहा होगा। इन्सानों और जानवरों में शर्मीना, जिसमें मुख पर लाली छा जाती है, एक अनोखा रूप होता है, जो सभी अभिव्यक्तियों में सबसे अजीब और सबसे मानवीय है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। लेकिन हम अपने लाभ के लिए प्रकृति में मौजूद सभी प्राणियों के प्रति क्रूर हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा पाप है, इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा।

सभी के प्रति रखें करुणा

सूत्र

हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी प्रजातियों के साथ दया, प्रेम और करुणा से पेश आएं। यह समझ से परे है कि ये जानवर मानवीय क्रूरता से पीड़ित हैं। अहिंसा हमें सर्वोच्च नैतिकता की ओर ले जाती है, जो सभी विकास का लक्ष्य है। जब तक हम अन्य सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं करते, तब तक हम जंगली ही रहेंगे

दूसरा पहलू

सूखे से जूझ रहे नामीबिया ने 83 हाथियों समेत 700 से ज्यादा जानवरों को मारने की योजना बनाई है।

हाथियों को मारकर लोगों की भूख मिटाएगा नामीबिया

दक्षिणी अफ्रीकी देश नामीबिया सैकड़ों प्रमुख जानवरों को मारने की योजना बना रहा है, ताकि अपने 14 लाख नागरिकों (देश की करीब आधी आबादी) की भूख मिटा सके, जो सदी के भयंकर सूखे के कारण भूख से जूझ रहे हैं। नामीबिया के पर्यावरण, वन और पर्यटन मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकों की भूख मिटाने के लिए 83 हाथियों समेत 723 जंगली जानवरों को मारने की योजना जरूरी है और हमारे संविधान के अनुरूप है, जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नागरिकों के लाभ के लिए करने की अनुमति देता है।

यह कोई नई रणनीति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अफ्रीका ऑफिस के निदेशक रोज म्वेबाजा ने कहा कि स्वस्थ जंगली जानवर लोगों के लिए भोजन का अच्छा स्रोत हो सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा सूखे की चपेट में है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जून में कहा था कि इस क्षेत्र की तीन करोड़ से ज्यादा आबादी इससे प्रभावित है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी के प्रवक्ता बेंजामिन सुआरतो ने कहा कि सूखा दक्षिणी अफ्रीका में आम बात है, लेकिन यह आपदा विशेष रूप से विनाशकारी और व्यापक रही है। नामीबिया में विश्व वन्यजीव फंड के निदेशक जूलियन जीडलर ने कहा कि पूरे क्षेत्र में लोगों और जानवरों के लिए बिल्कुल भी भोजन नहीं है।

सुआरतो ने कहा कि इस क्षेत्र में अल नीनो के चलते पिछले वर्ष रिकॉर्ड-तोड़ सूखा पड़ा। औसत से आधे से भी कम बारिश हुई। सूखे की वजह से फसलें सूख रही हैं और पशुधन मर रहे हैं तथा इसलिए नामीबिया भोजन के लिए कृषि को छोड़कर जंगली जानवरों पर निर्भर होता जा रहा है। नामीबिया में हाथियों के अलावा 300 जेब्रा, 30 दरियाई घोड़ा, 50 इंपाला, 60 भैंस, 100 ब्लू वाइल्डबीस्ट और 100 इंलैंड (एक तरह का हिरण) को मारने की योजना है। इन जानवरों को सिर्फ मांस के लिए ही नहीं मारा जा रहा, बल्कि सूखे की वजह से भोजन और पानी की तलाश में भटकते इन्सान और जानवरों के बीच संभावित मुठभेड़ को टालने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। हालांकि हाथी शाकाहारी होते हैं, लेकिन भूख से व्याकुल होकर वे इन्सानों पर हमला कर सकते हैं। पिछले वर्ष हाथियों ने जिम्बाबे में 50 लोगों को मार दिया था। आम तौर पर जानवर सूखे में पलायन कर जाते हैं, लेकिन देशव्यापी सूखे की वजह से पलायन के लिए जगहें सीमित रह गई हैं। स्थिति बेहद भयानक है और नामीबिया में 84 फीसदी खाद्य संसाधन खत्म हो चुके हैं।

©The New York Times 2024

एमीलिया वीरेनबर्ग

सूखे के कारण करीब चौदह लाख लोग भोजन के लिए जूझ रहे हैं। नामीबिया का कहना है, 'भोजन के लिए, जानवरों को मारना संविधान के अनुरूप है।'

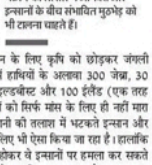

स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगली जानवरों को मारकर ये केवल लोगों की भूख ही नहीं मिटना चाहते, बल्कि भोजन की तलाश में जानवरों और इन्सानों के बीच संघर्षित मुठभेड़ को भी टालना चाहते हैं।

आंकड़े

एआई और भारत

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग दुनिया भर में बढ़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार, एआई टूल चैटजीपीटी का उपयोग भारत में सबसे ज्यादा होता है।

आंकड़े चैटजीपीटी के उपयोग के। स्रोत : BCG

अणिमांडव्य ऋषि ने कौशिक को शाप दिया कि सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी, पर उसकी पत्नी शांडिली ने अपने तप के प्रभाव से दस दिन तक सूरज नहीं उगने दिया।

भक्त शांडिली

अंतर्यात्रा
संकलित

प्राचीन काल में कौशिक नामक व्यक्ति प्रतिष्ठानपुर में रहता था। वह अत्यंत क्रोधी और कामी था। उसे कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी शांडिली भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। एक बार कौशिक एक वेश्या पर मोहित हो गया। कौशिक ने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि वह उसे उस वेश्या के पास ले जाए। शांडिली ने उसे काफी समझाया, लेकिन उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी, तो वह उसको अपने कंधों पर बैठाकर ले गई। रास्ते में अणिमांडव्य ऋषि तप कर रहे थे, गलती से कौशिक का पैर ऋषि को लग गया। इससे उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने कौशिक को शाप दिया कि सूर्योदय होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।

शांडिली ने कहा, 'मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए सूर्योदय नहीं होने दूंगी।' करीब दस दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ, तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूइया ही कुछ मार्ग निकाल सकती हैं। देवताओं के अनुरोध पर सती अनुसूइया ने शांडिली को समझाया और कहा, 'आप सूर्योदय होने दीजिए, मैं अपने तप के बल से आपके पति को पुनर्जीवित कर दूंगी।' इसके बाद शांडिली ने अपना प्रण छोड़ा। सूर्योदय होते ही कौशिक की मृत्यु हो गई, लेकिन अनुसूइया के तप के प्रभाव से कौशिक एकदम स्वस्थ होकर पुनर्जीवित हो गया। देवता शांडिली और अनुसूइया को आशीर्वाद देकर देवलोक को लौट गए।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 24 सितंबर, 1958

अमेरिकी सैनिकों को हटाने का आश्वासन

अमेरिकी सैनिकों को हटाने का आश्वासन
अरब देशों से संघर्ष सुधारेंगे

जनरल शेहाब ने शैमून से लेबनान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद जनरल शेहाब ने कहा-मैं देश की सुरक्षा का पक्का प्रबंध करेगा। साथ ही उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को हटाने का आश्वासन दिया।

पौधे लगाने की रस्म अदायगी काफी नहीं

हर वर्ष बड़े स्तर पर पौधे लगाए जाते हैं, पर उन पौधों को वनाग्नि से बचाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे समय और पैसे, दोनों की बर्बादी होती है।

सुरेश भाई

मुद्दा

जून की भीषण गर्मी के बाद बारिश आने पर वृक्ष प्रेमी गत वर्षों की भांति पौधे रोपने लगे। लेकिन इस बार भी उनमें यह दिलचस्पी नहीं रही कि उनका रोया हुआ पौधा आने वाले ग्रीष्मकाल से नहीं? यह सावधानी इसलिए कि इस बार पर्वतीय इलाकों के वनों में लगी आग से लाखों पेड़ जल गए हैं। इसके अलावा, वन्य जीव, जड़ी बूटियां, घास, छोटे-छोटे पौधे, पक्षी आदि के विनाश का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है।

आग से प्रभावित वनों की जैव-विविधता को बचाने के लिए लोगों ने कई पत्र अपनी राज्य सरकारों को सौंपे हैं, लेकिन बारिश आते ही सारे प्रयास ठंडे बस्ते में चले गए। अतः वन और पर्यावरण के प्रति इस घोर लापरवाही के बाद पेड़ उतने ही लगाने चाहिए, जितना कि इन्सान स्वयं देखभाल करके बचा सकता है। जंगल के बीच में पेड़ लगाकर भगवान भरोसे छोड़ना समय और पैसा, दोनों का नुकसान है। और यह हर वर्ष नर्सरी में उगाए गए पौधों के प्रति भी अन्याय है, लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी और देखरेख में पौधरोपण कर रहे हैं, उनके द्वारा रोपे गए पौधे आग और सूखे, दोनों से बच जाते हैं।

आंकड़ों के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 73,000 प्रजातियों के 30.40 खरब पेड़ दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है कि प्रतिवर्ष 15 अरब पेड़ विकास के नाम पर काटे जाते हैं और यह भी बताया जाता है कि इतने ही पौधों का रोपण भी किया जाता है। इसके आधार पर पता चलता है कि प्रति व्यक्ति 400 से अधिक पेड़ धरती पर हैं। यदि यह सच होता, तो वे भीषण तापमान को रोकने में मददगार हो सकते थे। दूसरी ओर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 24.62 प्रतिशत क्षेत्र में ही वन हैं, जबकि स्वस्थ पर्यावरण मानक के अनुसार, 33.3 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़-पौधे होने चाहिए थे। धरती पर कार्बन को नियंत्रित करने में पेड़ पौधों के अलावा घास की भी अहम भूमिका है।

भारत के भूगोल में विविधता के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्रों में बहुत अंतर दिखाई देता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वन क्षेत्र में बेहतर सुधार हुआ है और इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहां प्रति व्यक्ति 28 पेड़ हैं। अरुणाचल प्रदेश में 80 प्रतिशत वन क्षेत्र है, उत्तराखंड में 71 प्रतिशत और राजस्थान में 10 प्रतिशत से भी कम वन क्षेत्र है। इसलिए भारत की वन नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक-तिहाई क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाना पड़ेगा।

एक व्यक्ति को जीवन काल में 7-8 पेड़ों से प्रतिवर्ष 740 किग्रा ऑक्सीजन मिलती है। हर व्यक्ति एक वर्ष में सिर्फ पांच पेड़ लगाए, उनमें से 75 प्रतिशत भी बचा सके, तो धरती पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ध्यान रहे, पौधा तभी पनपता है, जब उसे लगाते समय गड्ढे में कोई कीट न हो। यदि हो, तो दवाई के छिड़काव के साथ खाद और मिट्टी मिलाकर पौधे लगाने चाहिए। धूप से बचाव के लिए समय-समय पर सिंचाई जरूरी है। रोपण के समय गड्ढे के चारों ओर 50-100 सेंटीमीटर पौधरोपण की तरह महत्व देने की जरूरत है।

रुक सकती है। 18-24 महीने तक निराई और खाद का प्रयोग आवश्यक है। पेड़ आमतौर पर गीली जमीन पसंद करते हैं। यदि इसका ध्यान नहीं होगा, तो रोपे गए पौधे जल्दी सूख जाएंगे।

अनुमान है कि 2050 तक 25 खरब पेड़ ही बचे रहेंगे। फिर तो वैश्विक तापमान वृद्धि को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों के साथ हर स्तर पर पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने के लिए उचित देखभाल के अनुसार ही पौधरोपण करवाएं। राज्यों को बिना सोचे-समझे जंगल को रातों-रात काटने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी पड़ेगी। उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में जहां हर वर्ष करोड़ों पेड़ों का रोपण किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 50 वर्षों से पाले हुए जंगल को काटने पर विचार हो रहा है। उत्तराखंड में हर रोज जंगल बचाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं, फिर भी यहां आए दिन हरे पेड़ काटने की शिकायतें मिलती हैं। यही स्थिति जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि स्थानों की है। जहां विकास के नाम पर हर रोज लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है। यदि हम रोप पौधरोपण करें और हमारे सामने ही 50-60 साल पुराना जंगल काट दिया जाए, तो समझना चाहिए कि हम आज जो पेड़ लगा रहे हैं, पहले तो उसे आग से बचाना मुश्किल होगा और यदि बच गया, तो लगभग 50 वर्ष तक उसे जंगल के रूप में खड़ा होने के लिए इंतजार भी करना होगा। अतः जरूरी हो गया है कि पुराने समय से जो पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसके अलावा जो बीज धरती के अंदर से जमकर पौधे का रूप धारण कर रहे हैं, उन्हें भी राज व समाज को मिलकर पौधरोपण की तरह महत्व देने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान 1936

सुरक्षा पर सियासत

सारे राजनीतिक भेद-मतभेद जैसे अचानक ही खत्म हो गए। मंगलवार को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपराजिता विधेयक पेश किया गया, तो पक्ष-विपक्ष सब एक साथ खड़े दिखाई दिए। विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया गया। ममता बनर्जी ने विपक्ष के विधायकों से कहा कि वे राज्यपाल से इस विधेयक को स्वीकृति देने का अनुरोध करें, ताकि इसे आगे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सके। विपक्ष के नेता भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने तो राज्यपाल से इसकी अपील भी कर दी। पिछले कुछ दिनों में कोलकाता की सड़कों ने एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद जिस तरह की राजनीति और गुंडागर्दी देखी है, उसके बाद इस तरह की आम सहमति एक उम्मीद बंधा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विधेयक भले ही सर्वसम्मति से पास हुआ हो, पर जिस तरह की राजनीति वहां दिखी, वह किसी भी तरह से आश्वस्त करने वाली नहीं थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो दूसरे राज्यों में हुए बलात्कारों की पूरी फेहरिस्त ही पेश कर दी। वह इतने पर ही नहीं रुकीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस तर्क के साथ इस्तीफे की मांग कर डाली कि वे महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हैं। याद रहे, भाजपा नेता कोलकाता अस्पताल बलात्कार और हत्या के मामले में कई दिनों से ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सो, मुख्यमंत्री ने सोचा कि इसका राजनीतिक जवाब थोक भाव में इस्तीफे की मांग कर ही दिया जा सकता है।

अपराजिता विधेयक भले ही सर्वसम्मति से पास हुआ हो, पर जिस तरह की राजनीति वहां दिखी, वह किसी भी तरह से आश्वस्त करने वाली नहीं थी।

अब आते हैं अपराजिता विधेयक पर। निश्चित तौर पर इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। यह विधेयक इसे स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर किसी का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है या फिर बलात्कारी उसे पूरी तरह अक्षम बना देता है, तो इसके दोषी को मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। ठीक यहीं पर हमें थोड़ा रुककर 2012 के निर्भया कांड को याद कर लेना चाहिए, जिसके बाद बलात्कार से संबंधित कानूनों में बदलाव के लिए जस्टिस जेएस वर्मा आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग ने बहुत बड़े विमर्श के बाद बहुत ही कम समय में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र ने जो कानून बनाया, उसमें दोषी को अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड का प्रावधान था। मगर क्या हुआ? अगर हम निर्भया कांड के दोषियों को छोड़ दें, तो बाद में किसी भी बलात्कारी को कभी मृत्युदंड नहीं दिया गया। इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को बलात्कार के लिए आजीवन कारावास होता है, तो उसे इस सजा के दौरान किसी भी तरह की पेरोल या फरलो नहीं दी जाए। हाल-फिलहाल के बहुत सारे संदर्भ बताते हैं कि कानून में इस तरह के प्रावधान कितने जरूरी हैं।

कानूनों में खामियां हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है बलात्कार पर होने वाली राजनीति। राजनीति में बलात्कार को अक्सर राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो कोलकाता के कांड पर हल्ला मचा रहे हैं, वे बदलापुर की घटनाओं पर चुप्पी लगा जाते हैं और जो बदलापुर पर चिल्ला रहे हैं, वे कोलकाता की वारदात पर कुछ नहीं बोलते। बलात्कार की हर वारदात के बाद जनता का गुस्सा राजनीति के इन आरोपों-प्रत्यारोपों के आगे दम तोड़ देता है। बलात्कार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर कोई आम सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं होती?

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

04 सितंबर, 1949

हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान

जबकि कल तक हमारा ही अंग रहे पाकिस्तान का रुख हमारे प्रति द्वेषपूर्ण और तासुबभरा मालूम पड़ता है, यह हर्षदायक है कि हमारे दूसरे पड़ोसी मुस्लिम देश अफगानिस्तान का रुख ऐसा नहीं है। हमारे विदेश विभाग के उपमंत्री डा. केसकर अफगान स्वातंत्र्य समारोह के सिलसिले में अफगानिस्तान गये थे और हाल ही में लौटकर आये हैं। उन्होंने वहां के अपने जो संस्मरण सुनाये वे उत्साहवर्द्धक हैं और इस बात को सिद्ध करते हैं कि मुस्लिम आबादी होने से ही कोई देश गैर-मुस्लिम देश के प्रति बैर-भाव नहीं रख सकता। मतलब यह कि पाकिस्तान जो हमारे प्रति शत्रु का-सा रुख रख रहा है उसका कारण यही नहीं हो सकता कि हमारा देश हिन्दुबहुल है और पाकिस्तान मुस्लिमबहुल बल्कि इसकी तह में कोई और ही बात है।

डा. केसकर अफगान सरकार के निमंत्रण पर स्वातंत्र्य-समारोह में शामिल होने गये थे। वहां उनका स्वागत ही नहीं हुआ, उनको तरह तरह की जानकारी प्राप्त करने का अवसर दिया गया। सब कुछ देख-सुनकर डा. केसकर ने बताया है कि अफगानिस्तान में भी हिन्दू व सिख हैं और उनकी संख्या बीस हजार से अधिक है परन्तु पाकिस्तान की तरह उस्त वे नहीं हैं बल्कि उतनी ही आजादी का उपयोग करते हैं जितनी कि वहां के बहुसंख्यक निवासी मुसलमानों को है। मंदिर व गुरुद्वारे भी उनके हैं, जहां वे निर्बाध पूजा-पाठ करते हैं। जहां तक हिन्दुओं और अफगानिस्तान के निवासी मुसलमानों (पठानों) के सम्बन्ध की बात है, डा. केसकर के अनुसार, वे शांति और मित्रता से यानी मिले-जुले रहते हैं। सेना में कुछ समय के लिए अनिवार्य भर्ती का वहां नियम है जो मुसलमानों पर ही लागू नहीं होता बल्कि हिन्दुओं व सिखों पर भी समान रूप से लागू होता है, जिसका मतलब है कि फौजी तालीम में भी हिन्दुओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इससे भी आल्हादकारक यह रहस्योद्घाटन है कि पाकिस्तानी कष्टों से तंग आकर प्राणरक्षा के लिए सीमाप्रवासी (भारतीय और अब पाकिस्तानी) सीमाप्रान्त से जब हिन्दू व सिख परिवार भाग कर अफगान सीमा में पहुंचे तो अफगान अधिकारियों ने शरण आये उन पीड़ितों का इसलिए निरादर नहीं किया कि वे स्वधर्मी और स्वदेशी नहीं है बल्कि उन्हें रक्षा दी और तन ढकने के लिए कपड़े और पेट भरने को खाना भी दिया।

आरोपी से मत छीनिए उसके अधिकार

अश्विनी कुमार | अधिवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वैधानिक प्रतिबंधों से ऊपर है और आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रखकर बिना मुकदमे के सजा नहीं दी जानी चाहिए।

यह देखते हुए कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को लेकर देश भर में एक खास तरह का खौफ बना हुआ है, गंभीर आपराधिक मामलों में भी आरोपियों को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला स्वागतयोग्य माना जाना चाहिए। इस फैसले ने विचाराधीन कैदियों में यह भरोसा पैदा किया है कि उनकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और निजता का अब अनुचित हनन नहीं हो सकेगा। मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 9 अगस्त को कहा, संविधानवाद और कानून के शासन का पैरोकार हमें होना चाहिए, जिसकी स्वाभाविक शर्त स्वतंत्रता है। उसने आगे कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद, जिसमें निष्पक्ष व त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में निहित है।

सिसोदिया मामले में सांविधानिक स्थिति की व्याख्या करने के बाद अदालत ने कविता बनाम ईडी (27 अगस्त, 2024) के मामले में भी यही बात दोहराई कि अनुच्छेद 21 के तहत मिला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार वैधानिक प्रतिबंधों से ऊपर है और आरोपी को बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रखकर उसे बिना मुकदमे के सजा नहीं दी जानी चाहिए। प्रेम प्रकाश बनाम भारत संघ (28 अगस्त, 2024) मामले में भी न्यायालय ने यही कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सदैव नियम है और इससे वंचित किया जाना अपवाद। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद में किसी व्यक्ति को असीमित समय के लिए सलाखों के पीछे रखना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन करना होगा। पूर्व के इन फैसलों के अनुरूप ही 2 सितंबर, 2024 को विजय नायर बनाम ईडी केस में दो सदस्यीय पीठ ने लंबे समय तक जेल में रहने और जल्द ट्रायल होने संबंधी आरोपी के अधिकार के आधार पर विजय नायर को जमानत दी है।

बहरहाल, उल्लेखनीय यह भी है कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 45 की व्याख्या करते हुए अदालत ने प्रेम प्रकाश को राहत देते समय 'विश्वास करने के उचित आधार' की बकालत की। उसने कहा कि अदालत को 'जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों के आधार पर' यह देखने की जरूरत है कि 'क्या आरोपी के खिलाफ वास्तव में कोई मामला बनता है'? पीएमएलए के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी के बयान के संबंध में अदालत ने दोहराया कि हिरासत में लिया गया 'शख्स ऐसा नहीं होता, जिसे स्वतंत्र दिमाग से काम करने वाला माना जा सके' और आरोपी के खिलाफ ऐसे बयान को स्वीकार्य बनाना बेहद असुरक्षित होगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई निष्पक्षता और न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ होगी। अदालत के इस तरह के रुख से सरकार को भी सहमत होना चाहिए और कानून की समीक्षा करते हुए ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि बिना जमानत यदि आरोपी को हिरासत में रखा जाता है, तो उसकी एक उचित अधिकतम मियाद हो।

जाहिर है, अदालत ने संविधान की प्रधानता और अनुच्छेद 21 के महत्व को स्थापित किया है। नारकोटिक ड्रग्स ऐंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेज ऐक्ट, 1985 (एनडीपीएस ऐक्ट) के तहत दर्ज फ्रैंक विट्स बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य तीन के मामले में 8 जुलाई, 2023 को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब तक वाजिब कारण न हों, संविधान करता है, उसे हासिल किया जा सके। यह यह युग है, जिसमें सांविधानिक मर्यादा का अभाव दिखता है। ऐसे में, संविधान का उल्लंघन करने वालों को आईना दिखाने के साथ-साथ अदालत को यह भी आश्वस्त करना होगा कि महज आरोप लगा देने मात्र से किसी के मान के साथ खिलवाड़ न हो सकेगा। उम्मीद है, न्यायालय का यह घोषित स्वतंत्रतावादी दर्शन राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवाधिकारों की रक्षा समग्र रूप से लोगों और उनके द्वारा स्थापित संस्थानों का ही सामूहिक दायित्व है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

स्मार्ट औद्योगिक शहर बिना हमारा काम नहीं चलेगा

चंद्रजीत बनर्जी | महानिदेशक, सीआईआई

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाने का भारत का हालिया नीतिगत फैसला बहुत खास है। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को बदलने और खूब रोजगार पैदा करने की तैयारी है। यह नीति भारत की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) में देश की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगी।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने 2023-24 में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 14 प्रतिशत का नाममात्र योगदान दिया, फिर भी इसमें 9.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र भी समान दर से बढ़ा, जिसकी जीवीए में नौ प्रतिशत हिस्सेदारी है। साल 2024-25 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11.11 ट्रिलियन रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) के बड़े आवंटन के साथ-साथ स्मार्ट सिटी मिशन, औद्योगिक गलियारा विकास, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और एक जिला एक उत्पाद योजना जैसी सरकारी पहल शामिल हैं। अब 12 औद्योगिक शहर बनाने की घोषणा सरकार के इसी इरादे की एक कड़ी है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत साल 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इन 12 शहर परियोजनाओं में से चार निर्माणाधीन हैं, जबकि चार आवंटन के लिए तैयार हैं। ये 12 शहर 10 राज्यों व छह प्रमुख औद्योगिक गलियारों का विस्तार करेंगे।

12 नए शहरों में हरित निर्यात को न केवल बढ़ावा देना है, बल्कि हरित मैन्युफैक्चरिंग की स्थायी व्यवस्था करने की योजना है।

यह शहर निर्माण कार्यक्रम पीएम गति शक्ति के लक्ष्यों के अनुरूप ही है। इस कार्यक्रम में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे में पांच, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे में दो और विजाग-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-नागपुर, चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में एक-एक शहर परियोजना शामिल है। 28,600 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा नए शहर बनेंगे, तो आसपास के इलाकों को भी आर्थिक फायदा होगा।

देश के विकास के लिए राज्यों की निर्यात-क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत उत्पाद निर्माण और निर्यात के लिए बड़े प्रयास कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, डिजाइन विनिर्माण, खाद्य और पेय पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और परिधान, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, मशीनरी व उपकरण और निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों में राज्यों की निर्यात-क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन नए शहरों में बड़े निवेशकों के साथ ही छोटे निवेशकों को भी पूरी मदद करने की योजना है।

शहर निर्माण की यह पहल 1.5 ट्रिलियन रुपये की समग्र निवेश क्षमता पैदा करने की संभावना रखती है। ध्यान दें कि कुछ प्रस्तावित शहर उन राज्यों में स्थित हैं, जो पहले से ही निर्यात के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र और तेलंगाना। अच्छी बात है कि नीति में यह भी ध्यान रखा गया है कि बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कम निर्यात हिस्सेदारी वाले राज्यों को भी शामिल किया जाए। खास बात यह भी है कि यह शहर निर्माण कार्यक्रम भारत के जलवायु लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जल को फिर उपयोग लायक बनाना और कूड़ा-कचरा के सही निस्तारण की भी चिंता की गई है। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों और वॉक-टू-वर्क जैसी अवधारणाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसमें अक्षय ऊर्जा का भी पूरा इंतजाम रखने की योजना है। साल 2030 तक क्षमता और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। हरित निर्यात को न केवल बढ़ावा देना है, बल्कि हरित मैन्युफैक्चरिंग की स्थायी व्यवस्था करने की योजना है। यदि हमने हरित उत्पादन की चिंता की, तो विश्व स्तर पर हमारे भागीदारों की भी संख्या बढ़ेगी।

जरूरी है कि नए शहरों में उच्च तकनीकी में सक्षम श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए पुख्ता बुनियादी ढांचा दिया जाए। स्मार्ट डिजिटल औद्योगिकीकरण का लाभ उठाया जाए। एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के साथ, भारत की औद्योगिक शहर परियोजनाएं निर्यात और आर्थिक विकास के लिए क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

हमें शोक से बचना होगा

यह देह तो पल-पल बदलती रहती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा इस चक्र का अनुभव किसे नहीं है? आधुनिक वैज्ञानिकों का तो कहना है कि सात साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। हमारे पूर्वज मानते थे कि बारह वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है और इसलिए वे प्रायश्चित, तपश्चर्या, अध्ययन आदि की भी मियाद बारह-बारह वर्ष की रखते थे। बहुत वर्ष की जुदाई के बाद जब कोई बेटा अपनी मां से मिला, तो मां उसे पहचान न सकी, ऐसे किस्से हम सुनते हैं। क्या यही प्रतिक्षण मरणशील देह ही तेरा रूप है? रात-दिन जहां मल-मूत्र की नालियां बहती हैं और तुझ जैसा जबर्दस्त धोनेवाला मिल जाने पर भी जिसका अस्वच्छता का व्रत छूटता ही नहीं, क्या वही तू है? वह अस्वच्छ, तू उसे साफ करनेवाला; वह रोगी, तू उसे दवा-पानी देनेवाला; वह साड़े तीन हाथ की जगह घेरे हुए, तू त्रिभुवन-विहारी; वह नित्य परिवर्तनशील, तू उसके परिवर्तन देखने वाला; वह मरने वाली और तू उसके मरण का व्यवस्थापक; तेरा और उसका भेद इतना स्पष्ट होते हुए भी तू इतना संकुचित क्योंकर बनता है? वह क्यों कहता है कि इस देह से जो संबंध रखते हैं, वे ही मेरे हैं? और इस देह की मृत्यु के लिए इतना शोक भी क्यों करता है? भगवान पूछते हैं कि 'अरे, देह का नाश क्या शोक करने जैसी बात है?'

देह तो कपड़े की तरह है। पुराने फट जाते हैं, इसी से तो नए धारण किए जा सकते हैं। यदि कोई एक शरीर आत्मा से सदा के लिए चिपका रहता, तो आत्मा की बुरी गति होती। सारा विकास रुक जाता, आनंद हवा हो जाता और ज्ञानप्रभा मंद पड़ जाती। अतः देह का नाश शोचनीय नहीं, हां, यदि आत्मा का नाश होता, तो अलबत्ता वह एक शोचनीय बात होती। मगर वह तो अविनाशी है, वह तो मानो एक अखंड बहता हुआ झरना है। उसे पर अनेक देह आते और जाते हैं, इसलिए देह के नाते-रिश्तों के चक्कर में पड़कर शोक करना सर्वथा अनुचित है। वह सारा ब्रह्मांड मानो एक सुंदर बुनी हुई चादर है। कोई छोटा बच्चा जैसे हाथ में कैंची लेकर चादर के टुकड़े-टुकड़े कर देता है, वैसे ही इस देह

आधुनिक वैज्ञानिकों का तो कहना है कि सात साल में शरीर बिल्कुल बदल जाता है और पुराने खून की एक बूंद भी शेष नहीं रहती। हमारे पूर्वज मानते थे कि बारह वर्ष में पुराना शरीर मर जाता है।

के जितनी कैंची लेकर उस विश्वात्मा के टुकड़े करना कितना लज्जाकर और कितनी हिंसा है!

सचमुच, यह बड़े दुख की बात है कि जिस भारत-भूमि में ब्रह्मविद्या ने जन्म पाया, उसी में छोटे-बड़े गुटों, फिरकों और जातियों की चारों ओर भरमार दिखाई देती है और मरने का तो इतना भय हमारे मन में घर कर गया है कि वैसा शायद ही कहीं दूसरी जगह हो! इसमें कोई शक नहीं कि दीर्घकालीन परतंत्रता का यह परिणाम है, परंतु यह बात भूल जाने से भी नहीं चलेगा कि वह भय भी इस परतंत्रता का एक कारण है।

विनोबा भावे, उनके गीता प्रवचन से

हेमा कमिटी रिपोर्ट से बेपरदा होता स्याह सच

वर्ष 2012 में निर्भया केस (दिल्ली) से लेकर 2024 में कोलकाता डॉक्टर बलात्कार मामले तक पिछले 12 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस और भाजपा, दोनों की सरकार बनी, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर शायद ही किसी ने ठोस कदम उठाया। अगर गंभीर प्रयास किए गए होते, तो हेमा कमिटी इतनी स्याह सच को बेपरदा नहीं करती। उसकी रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति बेहतर बताने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उल्लेखनीय है कि हेमा कमिटी का गठन 2017 में किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट अगले दो साल में जमा भी कर दी। मगर रिपोर्ट से बड़े-बड़े नामों के बेनकाब होने के डर से केरल सरकार ने उसे जारी नहीं किया। मगर अब महिला संगठनों के बढ़ते दबाव के कारण रिपोर्ट के कुछ हिस्से को छोड़कर शेष सबको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में तहलका मच गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, मलयाली फिल्मों में लड़कियों को तभी काम मिल पाता है, जब वह अपने शरीर का सौदा करने की रजामंदी देती हैं। कितनी घिनौनी बात है यह। वैसे भारत को महिलाओं के लिए सुरक्षित देश बताने वालों को यह भी जान लेना चाहिए कि महिला सुरक्षा को लेकर नीचाई सबसे बुरा देश भारत ही है। ऐसे में, लैंगिक समानता के दावे कागजी ही लगते हैं।

एन एस कृष्णवाहा, टिप्पणीकार

परदे के पीछे का खेल

हेमा कमिटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे कितना घना अंधेरा है। यह अंधेरा महिला कलाकारों और अन्य महिला सहकर्मियों के लिए कितना स्याह होता है, इसकी कल्पना करके ही सिहरन हो उठती है। रिपोर्ट की मानें, तो फिल्म इंडस्ट्री में 'कास्टिंग काउच' बड़े पैमाने पर जारी है। इसमें स्थापित पुरुष कलाकार, निर्देशक, निर्माता अक्सर देर रात महिला कलाकारों के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें विभिन्न तरीके से परेशान करते हैं, उनका लाभ उठाना चाहते हैं। आलम यह है कि सेट पर, विशेषकर आउटडोर शूटिंग के समय महिला कलाकारों के लिए कपड़े बदलने और टॉयलेट तक की ठीक व्यवस्था नहीं होती। इस कारण उन्हें लगातार मानसिक तनाव में रहना पड़ता है। महिला कलाकार आमतौर पर यह सब सहकर भी इसलिए चुप रहती हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक माफिया की तरह काम करती है। अगर आपने मुंह खोला, तो आपको कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। जाहिर है, कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के दावे अब तक हकीकत नहीं बन सके हैं। हमें इसे नकारना होगा। सच बनाना ही होगा।

मनीष आजाद, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

कार्यस्थल पर भेदभाव

कामकाजी औरतों के पास कई कानूनी हक

यह सही है कि हेमा कमिटी की रिपोर्ट मलयालम फिल्म उद्योग के स्याह सच को बेपरदा करती है, लेकिन सिर्फ इसी रिपोर्ट के आधार पर यह दावा सही नहीं माना जा सकता कि भारत में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ जमकर भेदभाव किया जाता है। सच यही है कि पहले की तुलना में महिलाओं के हित में कई काम किए गए हैं, जिसका फायदा उनको कार्यस्थलों पर मिला है। यही कारण है कि दफ्तरों या कार्यस्थलों पर महिला-कर्मियों की संख्या अनवरत बढ़ रही है। महानगरों में तो देर रात तक महिलाएं घरों से बाहर कार्यस्थल पर रहती हैं और सुरक्षित महसूस करती हैं।

महिलाओं को सबसे बड़ी ताकत भारतीय संविधान से मिली है। संविधान सभी भारतीयों को विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा लैंगिक आधार पर विभेद न करने (अनुच्छेद 15(1)) और राज्य द्वारा महिलाओं के पक्ष में विशेष उपबंध कर सकने (अनुच्छेद 15(3)) की गारंटी देता है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 51 (अ) के तहत महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार को निषिद्ध किया गया है। इनके अलावा कुछ विधायी ताकत भी उनके पास है, जैसे, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012। अब कार्यस्थलों पर ऐसा माहौल बनाया जाने लगा है कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके तहत अलग से शौचालय, स्तनपान कक्ष और सुरक्षा के अन्य उपाय किए गए हैं। गत में अगर कार्यस्थलों से महिला-कर्मी घर जाना चाहती हैं, तो कंपनी को उनके जाने की न सिर्फ व्यवस्था करनी पड़ती है, बल्कि साथ में सुरक्षा गार्ड भी भेजने पड़ते हैं।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के हित में शिकायत समितियों का गठन भी किया जाने लगा है, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिलाकर्मी करती हैं। यह प्रावधान भी कानूनी उपायों के तहत किया गया है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई समझौता न हो। इसके अलावा, कर्मचारियों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं और महिला सहकर्मियों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, इसका व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ठीक है कि हेमा कमिटी ने कुछ पुरुष कलाकारों का कुरूप चेहरा उजागर किया है, लेकिन यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता का निर्माण करने और सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश देश भर में की जा रही है। अतः हेमा कमिटी की रिपोर्ट को बहुत तूल देने की जरूरत नहीं दिखती।

महिमा खत्स, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा
पटना • बुधवार • 4 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दुख और वेदना के अथाह सागर वाले इस संसार में प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है।
-डॉ. रामकुमार वर्मा

चिंता का समाधान

बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर हर कोई चिंतित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने पलक्कड़ में तीन दिवसीय सम्मेलन समन्वय बैठक में यह कहा। उन्होंने बताया कि विभिन्न संगठनों द्वारा बांग्लादेश की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दी। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और बयानों के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि कि वह बांग्लादेश सरकार के साथ मिल कर काम करे। तमिलनाडु में मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण गतिविधियां चलाए जाने का आरोप लगाते हुए इसे गंभीरता से लेने को कहा गया है जबकि ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार

इसके बावत हलफनामा दे चुकी है। हलफनामे के अनुसार कई वर्षों से राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई घटना नहीं हुई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आने के बाद से बांग्लादेश में कई मंदिरों, हिन्दुओं के मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों खासकर हिन्दुओं की सुरक्षा का मसला राजनीति और सत्ता में बदलाव के साथ ही संवेदनशील हो जाता है। अवामी लीग की भारी हार के बाद 2001 में भी हिन्दू समुदाय पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए थे। कुछ संगठनों का तो यहां तक दावा है कि शेख हसीना के पलायन के बाद चार दर्जन जिलों में ढाई सौ से ज्यादा घटनाएं हुईं। हिन्दू, बौद्ध और ईसाई एकता संगठन दो सौ से ज्यादा हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं का दावा कर रहे हैं। वे अल्पसंख्यक आयोग बनाने और इन घटनाओं की जांच की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की आबादी में अल्पसंख्यकों का कुल आठ प्रतिशत है। विश्लेषकों का कहना है कि हिन्दुओं पर होने वाले हमले राजनीतिक से ज्यादा सांप्रदायिक ज्यादा हैं। हालांकि इस बात पर कोई संदेह नहीं कि हिन्दुओं के साथ होने वाली इन घटनाओं का फायदा अवामी लीग के साथ-साथ भारत भी परोक्ष तौर पर लेता है। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने राजनैतिक संबंधों को बिगाड़ने को कतई राजी नहीं नजर आ रही। हालांकि वहां की अंतरिम सरकार और सेना पर दबाव बना कर फौरी राहत की बात हो सकती है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी वहां हस्तक्षेप करने के लिए राजी करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

करना होगा विश्वास अर्जित

प्राकृतिक सौंदर्य से भरा-पूरा उत्तर-पूर्व का राज्य मणिपुर पिछले 16 महीनों से जातीय हिंसा से जूझ रहा है। यहां केंद्र और राज्य सरकार शांति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले रविवार को राज्य के मैतेई बहुल इंफाल पश्चिमी जिले में कुकी उग्रवादियों के हमले में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। इस हमले के सर्वाधिक चिंताजनक पहलू की ओर संकेत करते हुए पुलिस ने कहा है कि उग्रवादियों ने गांव पर हमला करने के लिए उच्च तकनीक वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके बम से हमला किया। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि हमले में ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ है। पड़ोसी देश म्यांमार में पहले से ही गृहयुद्ध और सैन्य संघर्ष के हालात हैं। इसका सीधा

प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। पिछले काफी समय से यह चर्चा है कि म्यांमार में अमेरिका और पश्चिमी देश ईसाई बहुल क्षेत्र में एक पृथक 'कुकी लैंड' बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। कुकी विद्रोहियों को हथियार और आर्थिक संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं। वस्तुतः पश्चिमी देशों की भारत से अपेक्षा थी कि वह म्यांमार की सैन्य सत्ता के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर संतुलित नीति अपनाई। इस क्षेत्र में कुकी लैंड की स्थापना पूर्वोत्तर भारत के लिए समस्या का कारण भी बन सकती है। मणिपुर में कुकी समुदाय अपने लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहा है। जिसे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अलग प्रशासन की मांग को अनुमति नहीं दी जाएगी। कुकी उग्रवादियों के हमले इसके प्रतिक्रियास्वरूप हो सकते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री सिंह ने वादा किया था कि वह राज्य में छह महीने के भीतर पूर्ण शांति लाएंगे। लेकिन राज्य में जारी हिंसा से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जातीय तनाव बना हुआ है और सरकार को पूर्ण शांति बहाली की दिशा में अपने रुख में बदलाव करना होगा। राज्य में 40 हजार केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं जिन्होंने हिंसा रोकने के लिए एक लंबा वफर जोन बनाया है। इसकी वजह से पहाड़ों में रहने वाले कुकी न तो घाटी में जा सकते हैं और न घाटी में रहने वाले मैतेई पहाड़ों में जा सकते हैं। सरकार की तरफ से यह भी कोशिश होनी चाहिए कि दोनों संघर्षरत जातीय समूहों का विश्वास अर्जित करने के उपाय तलाशे। चुनौती बड़ी है जिसका दृढ़ता से सामना करना होगा।

पैरालंपिक/योगेश कुमार गोयल

अद्भुत है इनका संघर्ष

पेरिस ओलंपिक में भारत भले ही इस बार एक भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में एसएच1 स्टॉईन में अवनि लेखरा द्वारा गोल्ड जीतने के बाद पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीतकर बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नितेश ने पेरिस पैरालिंपिक में इंग्लैंड के डेनियल बेथेल को हराकर पुरुष एकल एसएल3 बैडमिंटन स्पर्धा में सोना जीता।

एसएल3 श्रेणी की स्पर्धा निचले अंग की गंभीर विकलांगता वाले उन खिलाड़ियों के लिए वर्गीकृत है, जिनके शरीर के एक तरफ, दोनों पैरों में या अंग की अनुपस्थिति के कारण मध्यम गतिशीलता की चुनौतियां होती हैं। ये एथलीट आधी चौड़ाई वाले कोर्ट पर खड़े होकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहां उनकी हरकत सीमित हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके पास शॉट लगाने की पूरी क्षमता होती है। नितेश के तीखे रिवर्स हिट, नाजुक ड्रॉप शॉट और शानदार नेट प्ले ने बेथेल को पूरे मैच में थकाये रखा। पैरालंपिक खेलों में नितेश का यह पहला स्वर्ण पदक है। हालांकि पैरालंपिक जैसी दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता में नितेश का स्वर्ण पदक जीतने तक का सफर शुरू से ही चुनौतियों से भरा रहा है। एक नौसेना अधिकारी के बेटे नितेश का कभी अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए सुरक्षा बल में एक अधिकारी के रूप में शामिल होने का ही सपना था, लेकिन 2009 में विशाखापत्तनम में हुई एक रेल दुर्घटना ने उनके तमाम सपनों को चकनाचूर कर दिया। उस रेल दुर्घटना में नितेश ने अपना बायां पैर हमेशा के लिए खो दिया था लेकिन जिंदगी को झकझोर देने वाले उस हृदयविदारक हादसे ने भी नितेश के हौसलों को नहीं टूटने दिया। वहरहाल, नितेश और अवनि जैसे पैरालंपिक में पदक जीत रहे तमाम पैरा खिलाड़ी देश के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी विकट शारीरिक बाधाओं के बावजूद जिंदगी से हार मानने के बजाय बुलंद हौसलों के चलते अपने भीतर कुछ ऐसा विशेष कर दिखाने का सामर्थ्य पैदा किया, जिसके चलते पूरी दुनिया में भारत को गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर मिला।

ठीक नहीं है सब कुछ

सत्य है कि समय के साथ संस्कृतियां बदलती हैं, और इनके बदलाव में अहम भूमिका परंपराओं की होती है। दुनिया भर में यही होता है, भारत कोई अजूबा नहीं है। यहां की धार्मिक विविधता इसे सबसे अलग जरूर बनाती है। कई शहरों में मंदिर हैं, तो उसके निकट ही मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर भी हैं। सभी अपने-अपने धर्मों के हिसाब से जीते हैं, लेकिन बीते एक दशक से देश की तस्वीर में कुछ बदलाव आए हैं, जो बहुआयामी हैं। जाहिर तौर पर ये बदलाव बेशक, राजनीति के तहत किए जा रहे हैं, लेकिन इनका असर समाज पर पड़ रहा है।

ताजा उदाहरण असम सरकार का फैसला है कि विधानसभा में शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए दो घंटे का विराम खत्म कर दिया जाएगा। देखने में यह फैसला बहुत छोटा है। इसका असर इतना भर होगा कि विधानसभा के मुस्लिम सदस्यों को नमाज पढ़ने से रोक दिया जाएगा। लेकिन इस राजनीतिक फैसले का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से पड़ेगा। मुमकिन है कि आज जो फैसला विधानसभा के संदर्भ में लिया जा रहा है, उसी तरह का फैसला अन्य विभागों में भी लिया जाएगा और मुस्लिम कर्मियों से कहा जाएगा कि उन्हें नमाज पढ़ने की छूट नहीं दी जाएगी। जाहिर तौर पर असम में सत्तासीन भाजपा सरकार के इस फैसले पर आपत्तियों को सामने आना ही था। दिलचस्प यह कि ये आपत्तियां केंद्र सरकार के दो घटक दल जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) की तरफ से आई हैं। दोनों दलों द्वारा जारी बयान में फैसले की निंदा की गई है और कहा गया है कि यह देश हित में नहीं है। किसी भी धर्म के धर्मावलंबियों को उनके धर्मगत व्यवहारों से नहीं रोका जाना चाहिए। दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने असम में अपनी सरकार के फैसले के समर्थन में कहा है कि विधानसभा और लोक सभा नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं, लेकिन यह बात कहते हुए जोशी भूल गए कि जब संसद के नये भवन का उद्घाटन हुआ तब किस तरह एक धार्मिक प्रतीक को लोक सभा कक्ष में पूरे वैदिक रीति-रिवाज के साथ स्थापित किया गया था। यहां तक कि इसके लिए खास धर्म के गुरुओं को बुलाया गया और यह सब पूरी दुनिया ने देखा। वैसे मसला केवल एक फैसले भर का नहीं है, जिसके कारण केंद्र में सत्तासीन सरकार का भविष्य खतरे में है।

अभी तक कुल पांच फैसले ऐसे रहे हैं, जिन्हें वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को विवश होना पड़ा है। इनमें वक्फ बोर्ड से संबंधित विधेयक भी है। समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड-यूसीसी) को लेकर भी केंद्र सरकार वीच मझधार में अटकी है। गृह मंत्री अमित शाह बार-बार दावा करते हैं कि यूसीसी

को पूरे देश में लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ, उन राज्यों में जहां वा तो उनके दल की अपनी सरकार है या उनका दल वहां की सरकार में साझेदार है, समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार के गले में उपासना स्थल अधिनियम-1991 की फांस भी अटकी पड़ी है।

दरअसल, मंदिर-मस्जिद की राजनीति को साधने के लिए केंद्र में सत्तासीन भाजपा के लिए यह अहम है कि वह इस अधिनियम में संशोधन करे। यह उसके मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे में शामिल है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की काग्रेस सरकार ने यह खास कानून बनाया था, जिसके मुताबिक 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। दरअसल, भाजपा की नजर में यही वह कानून है जो उसे देश भर के उन मस्जिदों को ध्वस्त करने से रोक रहा है, जहां उसे लगता है कि वह मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। जाहिर तौर पर यह राम मंदिर की राजनीति की अगली कड़ी है, जिसके उदाहरण काशी और मथुरा में खड़े किए गए नये विवाद हैं।

अब भाजपा की कोशिश है कि वह किसी तरह इस कानून में बदलाव करे लेकिन लोक सभा चुनाव में बहुमत से 32 सीटें दूर रह जाने के कारण भाजपा अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसकी वजह यह है कि उसे जदयू, तेदेपा के अलावा भी कुछ दलों का समर्थन लेना पड़ रहा है, जिनके एजेंडे में मंदिर-मस्जिद विवाद नहीं है। इसलिए देखा यह जा रहा है कि हिन्दू धर्म के नाम पर राजनीति को जारी रखने के लिए भाजपा अब केंद्र की बजाय उन राज्यों में धर्म आधारित राजनीति कर रही है, जहां उसके अपने बूते सरकार है। असम और उत्तराखंड ऐसे दो राज्य हैं, जहां भाजपा अपने एजेंडा को लागू करने की कोशिश में जुटी है। वह जानती है कि सोशल मीडिया के जमाने में फैसला बेशक, गुवाहाटी में लिया जाए, उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं को यह भी पता है कि यदि उन्हें देश में सरकार चलानी है तो हिन्दू धर्म के राजनीतिक एजेंडे के मामले में समझौते करने ही होंगे और अभी तो उसके सामने जातिगत जनगणना का मसला भी है जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। एनडीए के घटक दल भी बीच इसे लेकर एकमत नहीं हैं।

भाजपा जातिगत जनगणना की विरोधी है तो उसकी सरकार का एक बड़ा घटक जदयू बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का श्रेय ले रहा है। बिहार में उसे अपनी राजनीति को मजबूत बनाने के लिए इस मुद्दे का सहारा लेना पड़ रहा है। वजह यह भी है कि बिहार सरकार के एससी, एसटी और ओबीसी के लिए राज्य में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसद किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगले वर्ष वहां चुनाव हैं, और जदयू के पास अपनी साख बचाने का कोई और रास्ता नहीं है।

कुल मिलाकर देश की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। हिन्दू धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा मनमानी करने में असफल हो रही है। इससे संदेश यह भी जा रहा है कि मौजूदा सरकार अब मजबूत सरकार नहीं रह गई है। जाहिर तौर पर इसका दूसरा पक्ष यह है कि विपक्ष अब मजबूत हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि दो वैसाखियों के सहारे देश में चल रही यह सरकार हिन्दू धर्म से जुड़े अपने एजेंडों को लागू कर पाती है, या उसके घटक दल उससे नाता कब तोड़ते हैं। हालांकि भाजपा के नेता बेशक, कह रहे हैं कि वह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

(लेखक के निजी विचार हैं)

राजग गठबंधन

नवल किशोर कुमार

देश की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। हिन्दू धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा मनमानी करने में असफल हो रही है। इससे संदेश यह भी जा रहा है कि मौजूदा सरकार अब मजबूत सरकार नहीं रह गई है। जाहिर तौर पर इसका दूसरा पक्ष यह है कि विपक्ष अब मजबूत हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि दो वैसाखियों के सहारे देश में चल रही

यह सरकार हिन्दू धर्म से जुड़े अपने एजेंडों को लागू कर पाती है, या उसके घटक दल उससे नाता कब तोड़ते हैं

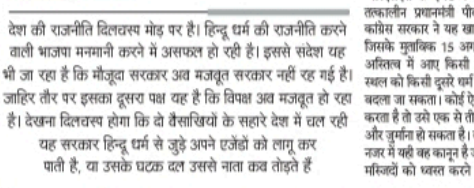

महिला डॉक्टरों में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता

- देश में अधिकतर महिला डॉक्टर रात्रि पाली की ड्यूटी के दौरान इस कदर 'असुरक्षित' महसूस करती हैं कि आत्मरक्षा के लिए हथियार (पिस्टल) रखना चाहती हैं
- कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना की पृष्ठभूमि में रात्रि पाली के दौरान महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा कराए गए अध्ययन से यह बात निकल कर सामने आई है
- अध्ययन में 22 से अधिक राज्यों की महिला डॉक्टर शामिल हुईं जिनमें 85 फीसद 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की थीं, जबकि 61 फीसद प्रशिक्षु या स्नातकोत्तर प्रशिक्षु थीं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

लगता है बीजेपी में प्रतिभा का अकाल पड़ गया है। पढ़े-लिखे लोगों की कमी हो गई है। तभी तो टीवी चैनलों में सिर्फकांग्रेस और दूसरे दलों से आए लोग बीजेपी के प्रवक्ता बन बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं और जो लोग सालों बीजेपी के लिए लड़ते मरते रहे वो टीवी चैनलों से गायब हैं। वाकई में बीजेपी देश को विपक्ष मुक्त करते करते, विपक्षमय हो गई।

आशुतोष, पत्रकार@ashutosh83B

तो हर फुहार के साथ दिल्ली डूबेगी ही!

उथली होती यमुना | पंकज चतुर्वेदी

इस बार राजधानी दिल्ली पर कुल आठ बार ठीकठाक बादल बरसे और बमुश्किल एक घंटे की बरसात में ही दिल्ली ठिठक गई। कोई 65 लोग बरसात में जलभराव या भरे पानी में बिजली का करेंट आने से मर चुके हैं। आकाश से राहत की बूंदें गिरीं और क्या मिंटो रोड तो क्या नवनिर्मित प्रगति मैदान की सुरंग, हर जगह पानी शहर की रफ्तार थाम देता है।

जिस शहर के बीचोंबीच से 22 किमी. तक यमुना बहती है, वह शहर प्यास बुझाने को उसी यमुना का पानी 104 किमी. दूर करनाल से मूनक नहर के जरिए लेता है। जिन जल-तिजोरियों को बरसात की हर बूंद सहेजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उन्हें 'रियल एस्टेट' मान लिया गया और कुदरत की नियामत बरसते ही बेधनी विशालकाय शहर की पूरी सड़कें, कॉलोनियां पानी से लबालब हो जाती हैं। काश! केवल यमुना को अविरल बहने दिया होता और उससे जुड़े तालाबों और नहरों को जीवन दे दिया जाता तो दिल्ली से दुगुने बड़े शहरों को पानी देने और बारिश के चरम पर भी हर बूंद को समेट लेने की क्षमता इनमें है।

दिल्ली में जलभराव का कारण यमुना का गाद (सिल्ट) और कचरे के कारण इतना उथला हो जाना है कि महज एक लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो इसमें बाढ़ आ जाती है। नदी की जल ग्रहण क्षमता को कम करने में बड़ी मात्रा में जमा गाद, रेत, सीवरेज, पूजा-पात्र सामग्री, मलबा और तमाम तरह के कचरे का योगदान है। 1994 से अब तक यमुना एक्शन प्लान के तीन चरण आ चुके हैं, हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं पर यमुना में गिरने वाले दिल्ली के 21 नालों की गाद भी अभी तक नहीं रोकी जा सकी है। जब नाले का पानी नदी की तरफ लपकता है और उथली नदी में पहले से ही नाले के मुंह तक पानी भरा होता है तो नदी के प्रवाह से उपजे प्रतिगामी बल से नाले पलट कर सड़कों को दरिया बना देते हैं। कभी यमुना का बहाव और हाथी डुब्बा गहराई आज के मयूर विहार, गांधी नगर, ओखला, अक्षरधाम तक हुआ करती थी। एक तरफ ढेरों वैध-अवैध कॉलोनियों और सरकारी भवनों के कारण नदी की चौड़ाई कम हुई तो दूसरी तरफ गहराई में गाद भर गई। इस तरह जीवनदायी बरसात के जल को समेटने वाली जल धार को कूड़ा होने की धार बना दिया गया।

जब नदी-नहर पानी की कमी पूरी कर नहीं पाते तो जमीन में छेद कर पानी उलिच जाता है, यह जाने बगैर कि

इस तरह भूजल स्तर से बेपरवाही का असर यमुना के जल स्तर पर ही पड़ रहा है। बात आबादी बसाने की हो या उनके लिए सुचारु परिवहन के लिए पुल या मेट्रो बनाने की, हर बार यमुना की धारा के बीच ही खंभे गाड़े जा रहे हैं। वजीराबाद और ओखला के बीच यमुना पर 22 पुल बन चुके हैं, और चार निर्माणाधीन हैं, और इन सभी ने यमुना के नैसर्गिक प्रवाह, गहराई और चौड़ाई को नुकसान पहुंचाया है। रही-बची कसर अवैध आवासीय निर्माणों ने पूरी कर दी जो देखते-देखते यमुना का कछार अर्थात जहां तक नदी अपने पूरे यौवन में लहरा सके, को ही हड़प गए। कछार में अतिक्रमण ने नदी के फैलाव को रोक दिया और इससे जल-ग्रहण क्षमता कम हो गई। तभी इसमें पानी आते ही कुछ ही दिनों में वह जाता है। सरकारी बस्तों में दर्ज है कि यमुना के दिल्ली प्रवेश कश्मीरी दरवाज से ओखला बैराज तक के 22 किमी. में 9700 हेक्टेयर की कछार भूमि पर पक्के निर्माण हो चुके हैं।

इसमें से 3638 हैक्टेयर को दिल्ली विकास प्राधिकरण खुद नियमित अर्थात वैध बना चुका है। यहां पूरी तरह सरकारी अतिक्रमण हुआ-100 हेक्टेयर में अक्षरधाम मंदिर, खेल गांव का 63.5 हेक्टेयर, यमुना बैंक मेट्रो डिपो 40 हैक्टेयर और शास्त्री पार्क मेट्रो डिपो 70 हेक्टेयर। आईटी पार्क, दिल्ली सचिवालय, मजनू का टीला और अबु फजल एनक्लेव जैसे बड़े वैध-अवैध अतिक्रमण हर साल बढ़ रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शोध के मुताबिक, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 600 से अधिक आर्द्रभूमि और जल निकाय थे, लेकिन उनमें से 60 से अधिक अब सूखे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, 'यमुना बाढ़ क्षेत्र में यमुना से जुड़ी कई जल-तिजोरियों का संपर्क तटबंधों के कारण नदी से टूट गया।'

समझना होगा कि अरावली से चल कर नजफगढ़ झील में मिलने वाली साहबी नदी का इस झील को यमुना से जोड़ने वाली नैसर्गिक नहर का नाला बनना हो या सराय कालेखां के पास बारा पुला या खिड़की गांव का सात पुला या लोधी गार्डन की नहरें, असल में ये सभी यमुना में क्षमता से अधिक पानी आने पर तो उसे जोहड़-तालाब में सहेजने का जरिया थीं। शहर को चमकाने के नाम पर इन सभी सदियों पुरानी संरचनाओं को तबाह किया गया, सो न अब बरसात का पानी तालाब में जाता है, और न ही बरसात के दिनों में सड़कों पर जल जमाव रुक पाता है। जब दिल्ली बसी ही इसलिए थी कि यहां यमुना बहती थी, सो जान लें कि यदि दिल्ली को जलभराव से जूझना है तो यमुना आंकरल बहे, उसकी गहराई और पाट बचे रहें, यही अनिवार्य है। वरना तैयार रहिए अपनी संपदा यमुना को चोट पहुंचाने के चलते सावन-भादों में हर फुहार के साथ दिल्ली डूबेगी ही!

बेकारी | श्रीराम शर्मा आचार्य

कहावत है-'खाली दिमाग शैतान की दुकान।' यह कहावत उन सबके लिए ही जो परिश्रम से जी चुराते हैं। परिश्रम के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा सा रहता है। अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि परिश्रम से जी चुराने से ही नाना प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। परिश्रम चाहे व्यायाम का ही क्यों न हो किंतु करना अवश्य चाहिए। बेकारी की समस्या इसीलिए

खतरनाक नहीं मानी जाती कि उन दिनों आदमी कमाता नहीं वरन मुख्यतया इसलिए उसे भयंकर मानते हैं कि बेकार आदमी को उत्पात ही सूझेंगे। बुराई का आज चारों ओर बाहुल्य है। उसका प्रसार एवं आकर्षण भी प्रबल है। बेकार आदमी सहज ही उस ओर आकर्षित होते हैं। कार्यव्यस्त व्यक्ति फुरसत न मिलने के कारण बुराइयों से बचा रहता है पर बेकार आदमी के लिए तो सर्वनाश का द्वार खुला पड़ा है। बेकारी का कारण सदा काम का अभाव नहीं है। बहुधा आलस्य भी होता है। नौकरी के लिए दर-दर ठोकरें खाते फिरने वालों में से अधिकांश वे होते हैं, जो ऊंची आय, आरामतलबी, बिना मेहनत की नौकरी चाहते हैं, श्रम में जिनका जी दुखता है, मेहनत-मजदूरी से जिन्हें अपनी शान घटती मालूम होती है। उनके लिए बाबूगीरी की नौकरियां मिलना मुश्किल हो सकती हैं पर परिश्रम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। ज्यादा पैसे का नहीं, बड़ा न सही, परंतु हर जगह काम मिल सकता है, और बहुत न सही, पर थोड़ा-सा तो वह कमा ही सकता है। थोड़ी भी कमाई न हो तो समय की बेकारी तो किसी काम में लगे रहने से बच ही जाती है। खुराफात में मन दौड़ाने का अवसर नहीं मिलता, यह भी क्या कुछ कम लाभ है? कहावत है, 'कुछ न कुछ बिना कुछ, कुछ न हो तो पाजामा उधेड़ कर सिया कर।' बेकारी का वक्त बेकार बातों में गंवाने की अपेक्षा अच्छा है कि पाजामा उधेड़ने और सीने की कला का अभ्यास होता रहे और उस कार्य में हाथ सध जाए। देश में उद्योग-धंधे बढ़ रहे हैं। उनके लिए कुशल कारीगरों की भारी कमी रहती है। उन्हें आजीविका भी अच्छी मिलती है, और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बाबूगीरी की अपेक्षा लोग मेहनतकश बनने को तैयार हों, तो उनकी शान-शेखी में ही थोड़ी कमी हो सकती है, पर लाभ उन्हें भी होगा और सारे समाज को भी।

रीडर्स मेल

दक्षिणपंथ का बोलबाला

यूरोप में राष्ट्रवादी एवं चूर दक्षिणपंथ का पुनः उदय होना शुरू हो गया है। द्वितीय युद्ध की पीड़ा को एवं नाजी, जर्मनी एवं मुसोलिनी का इटली के दर्द व प्रताड़ना को लोग भूल रहे हैं। तभी तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, हॉलैंड, पोलैंड, स्वीडन एवं कुछ हद तक ग्रेट ब्रिटेन में उग्र राष्ट्रवाद के प्रति समर्थन बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर पिछले रविवार को जर्मनी के दो पूर्वी राज्यों में चुनाव परिणाम ने पूरे विश्व को चिंतित कर दिया है। थुरिंजिया में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की जीत और सैक्सोनी में दूसरे स्थान पर आने से बर्लिन में आत्ममंथन का एक नया दौर शुरू हो गया, जबकि राष्ट्रीय चुनाव से एक वर्ष पहले जर्मनी का झुकाव दक्षिणपंथ के तरफ होना यूरोपीय संघ के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जर्मनी के चांसलर, ओलाफ स्कोल्ज ने मुख्यधारा की पार्टियों से आग्रह किया है कि वे दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को समर्थन न दें, जिससे रविवार के क्षेत्रीय चुनाव में पूर्वी राज्य थुरिंगिया में बड़ी जीत हासिल की है। मुझे लगता है इनका इस मांग को तमाम पार्टियों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए हर कीमत पर एएफडी पार्टी को सत्ता के पहुंच से दूर रखना ही जर्मनी के लिए श्रेयस्कर होगा, वरना जर्मनी में वापस 1930 के दस्क का दौर वापस आ जाएगा।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

हाकिंग का हौसला

दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक हॉकिंग भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका हौसला हमेशा के लिए प्रेरणादायी रहेंगे। उनके शरीर के 92 फीसद हिस्से काम नहीं करते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। रिलेटिविटी, ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी की खोज करने में उन्होंने बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जुनून भरे काम से दुनिया के करोड़ों युवाओं को विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को विज्ञान समझाने के लिए 15 किताबें भी लिखी। हॉकिंग समय को बर्बाद करने से बचते थे, उन्होंने जब नेचुरल साइंस पर पीएचडी शोध पत्र को पूरा किया तो उसे सार्वजनिक होने के बाद महज कुछ ही दिनों में 20 लाख से अधिक लोगों ने देखा। सन 1966 में इसे जारी करते ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का प्रकाशन अनुभाग क्रैश हो गया था। उन्होंने अपना रिसर्च समाप्त करते हुए कहा था कि घड़ी को वापस पीछे घुमाना नामुमकिन है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

न्यायिक सुधार जरूरी

देश में न्यायिक सुधार की सख्त जरूरत है। देश का आम आदमी आज कोर्ट का नाम सुनकर ही घबराता है क्योंकि उसे मालूम है कि न जाने कितने साल बीत जाएंगे और पता नहीं इंसाफ मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देश की राष्ट्रपति दोनों ने ही इस बात को स्वीकार किया है कि देश की न्याय प्रणाली में सुधार हो और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर ही भारतीय न्यायिक सेवा का भी गठन हो। भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से बहुत फायदे हैं, जैसे की नई प्रतिभा आएगी, समाज के वंचित वर्गों को प्रस्तुति मिलेगी, न्यायाधीश और जनसंख्या का जो उचित अनुपात है वह हासिल होगा। केंद्र सरकार और कोर्ट को राज्य सरकारों के साथ गहन विमर्श करना चाहिए ताकि देश की आम जनता को न्याय त्वरित और सुलभ मिले। यही समय की मांग है।

बाल गोविंद, नोएडा
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, गौता-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-खाजपुर, पानापुर, पटना से मुद्रित तथा पाटलीपुत्र टाल, सहारा इण्डिया बिहार, मोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी ।

कल्पमेधा

शिक्षा का ध्येय मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि करना ही नहीं, अपितु उसका उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क को विकसित करना है, भरना नहीं।

- डाडेट

जाति की जड़ें

जातिगत जनगणना के औचित्य पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सकारात्मक रुख से माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर सकती है। हालांकि विपक्षी दलों को इतने भर से संतोष नहीं है। वे चाहते हैं कि संघ और भाजपा इस पर अपना रुख स्पष्ट करें, केवल 'उपदेशात्मक' बात न करें। दरअसल, इस विषय पर फिर से चर्चा इसलिए छिड़ गई है कि केरल के पलक्कड़ में संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय स्वयंसेवक बैठक के अंतिम दिन उसके अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रेस कांफ्रेन्स कर कहा कि जातिगत जनगणना का उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल पिछड़े रहे समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। अभी तक संघ और भाजपा इस मसले पर कुछ भी कहने से बचते आ रहे थे। जातिगत जनगणना का मुद्दा असल में, पिछले कुछ समय से कांग्रेस काफी जोर-शोर से उठा रही है। कर्नाटक चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में उसने इस पर जोर दिया। राहुल गांधी अपने हर भाषण में यह मुद्दा उठाते देखे जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि भाजपा और आरएसएस को लगने लगा है कि इस विषय में लंबे समय तक चुप्पी साधे रहना नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए वे अब जातिगत जनगणना को उचित बताने लगे हैं।

आरक्षण का मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में काफी संवेदनशील हो चुका है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर दल इसका इस्तेमाल अपना जनाधार बढ़ाने, आरक्षण से वंचित जातियों को अपने पाले में खींचने के मकसद से ही करते रहे हैं। मगर संवैधानिक बाध्यताओं के चलते राज्य सरकारें पचास फीसद की सीमा पार नहीं कर पातीं। कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने भी आरक्षण का दायरा बढ़ा कर उसमें कुछ और जातियों को शामिल किया था। मगर तमाम प्रयोगों के बावजूद आरक्षण को लेकर बहुत सारे समुदायों और जातियों में असंतोष बना हुआ है। ऐसे में सिद्धांत रूप में यह उपाय निकाला गया कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जिस जाति की जितनी संख्या हो, उसी आधार पर आरक्षण तय किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन हो। सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले दिनों व्यवस्था दी कि मलाईदार तबके को आरक्षण की व्यवस्था से बाहर रखा जाना चाहिए और जातियों के भीतर उपजातियों का भी वर्गीकरण होना चाहिए। मगर इस व्यवस्था के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन कर दिया था।

कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण के प्रावधान का सैद्धांतिक रूप से विरोध नहीं कर सकता। अब जिस तरह कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना दिया है, उसमें हर पार्टी को अपना जनाधार संभालने की चिंता पैदा हो गई है। इसलिए यह कहना कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आदर्श वाक्य जैसा हो सकता है। मगर वास्तव में सभी दल इसके जरिए अपना राजनीतिक हित साधने के प्रयास कर रहे हैं। यह तो सही है कि वंचित समुदायों और जातियों को उनकी संख्या के आधार पर वरीयता देकर ही उनके कल्याण की उम्मीद बन सकती है। पर हमारे देश में जिस तरह की जातिगत जटिलताएं हैं, उन्हें सुलझाना आसान काम नहीं है। अगर संघ और भाजपा सचमुच इसके पक्ष में हैं, तो उन्हें जातिगत जनगणना से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। इसमें दूसरे दलों से भी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा होगी।

नाम के स्कूल

नियमित स्कूली शिक्षा व्यवस्था के समांतर चलने वाले कोचिंग केंद्रों में पढ़ाई आज एक ऐसा दुश्चक्र बन गया है कि इसमें कई बार नियम-कायदों का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता। इनमें दाखिला लेकर स्कूली कक्षाओं से आजादी की सुविधा मुहैया कराने वाले स्कूलों की वजह से भी आज समस्या खड़ी हो रही है। इसमें स्कूली शिक्षा व्यवस्था के नियम-कायदे ताक पर रखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन्हें 'डमी स्कूल' कहा जाता है, जहां विद्यार्थी अपना नामांकन तो करा लेते हैं, मगर वहां कक्षाओं में शामिल होने या हाजिरी लगाने की जरूरत उन्हें नहीं होती। इसमें अनियार्य उपस्थिति से लेकर अन्य शिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्रों की व्यवस्था डमी स्कूल की ओर से करा दी जाती है। इसी समस्या पर काबू पाने के मकसद से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मंगलवार को राजस्थान और दिल्ली के सत्ताईस 'डमी स्कूलों' का औचक निरीक्षण किया। बोर्ड ने इस मसले पर कहा कि सभी संबद्ध स्कूलों से इसके दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है और इस निरीक्षण के बाद जिन स्कूलों को नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने या जानबूझ कर अनदेखी करने के मामले पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी शिकायतें पहले भी आई हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से निकाल कर 'डमी स्कूलों' में दाखिला दिलवा देते हैं। दरअसल, अच्छे स्कूलों में छात्रों के लिए अस्सी फीसद हाजिरी का नियम लागू होता है, मगर कोचिंग में पढ़ाई करने वाले छात्र स्कूल नहीं जाना चाहते। वहीं 'डमी स्कूल' में दाखिला लेने के बाद उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वे सिर्फ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हैं। इस तरह बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश में अभिभावक अपने बच्चों को शुरुआती दौर में ही जाने-अनजाने भ्रष्टाचार में शामिल कर देते हैं। इस समस्या पर काबू पाने के लिए कोचिंग कक्षाओं और स्कूल के समय को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, मगर यह समस्या बनी रही। स्कूली पाठ्यक्रम की अनदेखी करके सिर्फ किसी खास प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर कोचिंग की पढ़ाई के दूरगामी नतीजों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है।

जहरीली हवा में सांस लेता बचपन

'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की रपट में बताया गया था कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 4.76 लाख बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें से अकेले भारत में 1.16 लाख नवजात बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से हुई थी।

योगेश कुमार गोयल

वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में प्रति वर्ष लाखों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। हाल ही में आई यूनिसेफ और अमेरिका के गैर-सरकारी संगठन 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' (एचईआइ) की साझा रपट के अनुसार पूरी दुनिया में 2021 में वायु प्रदूषण के कारण कुल 81 लाख लोगों की मौत हो गई। इनमें पांच वर्ष से भी कम आयु के 7.09 लाख बच्चे थे। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में हर घंटे 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। भारत में 2021 में वायु प्रदूषण से 169400 बच्चों की मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में हो रही बच्चों की मौत के ये आंकड़े व्यथित और परेशान करने वाले हैं।

रपट के मुताबिक दूषित हवा ने गंदे पानी तथा गंदगी से होने वाली मौतों को भी पीछे छोड़ दिया है और गरीब देशों के बच्चों पर वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ रहा है। रपट के अनुसार अफ्रीकी देशों में तो उच्च आय वाले देशों की तुलना में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत सौ गुना तक अधिक है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में बच्चों की मौतों का यह आंकड़ा तब है, जब वर्ष 2000 के बाद से दूषित हवा से बच्चों की मौत करीब 53 फीसद तक घटी है, जिसका प्रमुख कारण घर के भीतर हवा की गुणवत्ता में सुधार होना है। घर के अंदर हवा को स्वच्छ रखने में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है, मगर दुनिया भर में अब भी करीब 230 करोड़ लोगों के पास खाना बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा नहीं है।

'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की रपट में बताया गया था कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 4.76 लाख बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें से अकेले भारत में 1.16 लाख नवजात बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2018 में प्रकाशित 'एयर पाल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ' नामक रपट में कहा गया था कि 2016 में दुनिया भर में पांच वर्ष से कम आयु के छह लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई थी और उनमें से एक लाख से अधिक बच्चे भारत के थे। वायु प्रदूषण के कारण नवजात शिशुओं की सर्वाधिक मौतें अफ्रीका तथा एशिया में होती हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में करीब 90 फीसद बच्चे, जिनकी कुल संख्या 1.8 अरब से भी ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। यूनीसेफ की एक रपट के मुताबिक विश्वभर में करीब दो अरब बच्चे खतरनाक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से 62 करोड़ बच्चे दक्षिण एशियाई देशों में हैं।

भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत के कारणों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि कुपोषण के बाद इस आयु वर्ग के बच्चों की मौतों की बड़ी वजह वायु प्रदूषण है। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव होने से गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी वायु प्रदूषण का

घातक असर पड़ता है। इससे समय से पूर्व प्रसव या फिर कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं और ये दोनों शिशु मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। समय से पहले जन्मे बच्चों का शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे बच्चों के अस्थमा तथा अन्य बीमारियों का शिकार होने का काफी खतरा रहता है। 'द लांसेट प्लानेटरी हेल्थ जर्नल' में अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण से वातावरण में फैलने वाले कण और रसायन अजन्मे बच्चों के दिमाग, फेफड़े और अन्य विकासशील अंगों तक पहुंच रहे हैं, जो संभावित रूप से उनके स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं।

> अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे अगर बच भी जाते हैं, तो उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, जन्म के समय कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। गर्भ में भी बच्चे वायु प्रदूषण के प्रभाव से अछूते नहीं हैं, उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनमें दमा और हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं और वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों बच्चों की मौत हो जाती है।

यूनिसेफ द्वारा जून 2018 में प्रकाशित एक रपट में बताया जा चुका है कि भारत में लगभग सभी स्थानों पर वायु प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक है, जिससे बच्चे फेफड़ों से संबंधित बीमारियों और अल्प विकसित मस्तिष्क का शिकार हो रहे हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से करीब 15 फीसद वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली सांस संबंधी बीमारियों के कारण होती है। 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' के पूर्व अध्यक्ष डैन शीनबाम के मुताबिक नवजात का स्वास्थ्य किसी भी समाज के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण होता है और इन नए साक्ष्यों से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में नवजातों को होने वाले अधिक खतरे का पता चलता है।

अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे अगर बच भी जाते हैं, तो उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, जन्म के समय कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। गर्भ में भी बच्चे वायु प्रदूषण के प्रभाव से अछूते नहीं हैं, उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनमें दमा और हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं और वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष लाखों बच्चों की मौत हो जाती है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि घरों के भीतर का प्रदूषण भी बच्चों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कुछ रपटों के मुताबिक नवजात शिशुओं की मौतों में से दो तिहाई का कारण घरों के अंदर का प्रदूषण है। विश्व स्तर पर वाहनों से उत्सर्जित गैसों और 'पार्टिकुलेट मैटर' के उत्सर्जन पर तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन घरों के अंदर के प्रदूषण के स्रोतों पर अक्सर कोई चर्चा नहीं होती। 'यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो बोल्डर' के वैज्ञानिकों के मुताबिक खाना पकाने, साफ-सफाई तथा घर के अन्य सामान्य कामकाज के दौरान 'पार्टिकुलेट मैटर' और 'वोलाटाइल आर्गेनिक कंपाउंड्स' (वीओसी) उत्पन्न होते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं। 'पार्टिकुलेट मैटर' खाना पकाने और साफ-सफाई के दौरान उत्पन्न होते हैं, जबकि शैम्पू, परफ्यूम, रसोई और सफाई वाले घोल वीओसी के प्रमुख स्रोत हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रकार के तत्त्व विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा कैंसरकारक भी होते हैं। घरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों का सबसे बड़ा कारण आजकल अधिकांश घरों में विभिन्न घरेलू कार्यों में तरह-तरह के रसायनों का बढ़ता उपयोग माना जा रहा है। ऐसे ही रसायनयुक्त पदार्थों के बढ़ते चलन से घरों के अंदर फार्मल्डीहाइड, बेंजीन, अल्फोहल, कीटोन जैसे कैंसरजनक हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिनका बच्चों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ता है। बहरहाल, वायु प्रदूषण के बच्चों पर पड़ते दुष्प्रभावों और हर वर्ष वायु प्रदूषण के कारण हो रही लाखों बच्चों की मौतों को लेकर पूरी दुनिया को अब संजीदगी से इस पर विचार मंथन करने और ऐसे उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जिससे मासूम बचपन प्रदूषण का इस कदर शिकार न बने।

जल है तो कल है

मुकेश पोपली

यह तो तय है कि हमारे जीवन में पानी की आवश्यकता जन्म से लेकर मृत्यु तक बनी रहती है। पानी की उपलब्धता के लिए बह रही नदियां, लहराते सागर, झर-झर बहते झरने, गहरे नाले सभी प्रकृति की देन हैं। दूसरी ओर, नहरें, कुएं और बावड़ियां मानव निर्मित हैं। एक समय था जब हमारे देश में कुएं और बावड़ियां पर्याप्त मात्रा में थे और इनमें बरसाती पानी जमा होता था। इसी तरह उन इलाकों में जहां बारिश और पानी की कमी होती थी, घरों में कुंड बनाए जाते थे। घर की छत पर जमा हो रहे बारिश के पानी को इस कुंड तक ले जाने के लिए नालियां बनाई जाती थीं और इस पानी को पीने के काम में लिया जाता था। यहां यह भी बिंदु महत्त्व रखता है कि यह पानी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता था।

आज घरों में बरसात के पानी का संचय करने वाले कुंड नाममात्र के हैं। अब कुएं नहीं हैं, बावड़ियां नहीं हैं। जो हैं, उनमें कोई जमा है। वह पानी पीने के लायक तो नहीं है और उसका उपयोग नहाने-धोने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। जानवर भी उस पानी के नजदीक नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह सड़ांध मार रहा है। दरअसल, पानी की प्रकृति निर्मल होती है और चंचलता भी उसमें कूट-कूट कर भरी होती है। आज प्रकृति निर्मित नदियों को हमने कचरा घर मान लिया है। नदियों के किनारों पर बसे शहरों के कल-कारखानों ने अपने उत्पादों से निकलने वाले तमाम कचरे को हमेशा पानी में बहाया है और लाख सख्ती के बावजूद नदियां आज भी प्रदूषित हो रही हैं। अब न तो नदियों में निर्मलता है और न ही मन को मोहने वाली चंचलता। अब पानी गाहे-बगाहे अपना रौद्र रूप दिखाता है। इस कारण से नदियों के किनारे बसे शहरों में रहने वालों की प्रकृति भी दिनोंदिन कठोर होती जा रही है। देश में पानी को लेकर झगड़े आम बात हो गई है। यहां तक कहा जाने लगा है कि आने वाले वक्त में अगर विश्व युद्ध हुआ तो उसका मुख्य कारण पानी होगा। पानी के मामले में जिस तरह के अभाव की स्थिति, छीना-झपटी, पानी के लगातार कारोबार बनते जाने की हालत बनती जा रही है, भूजल सूखने की खबरें आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि पानी के मसले पर टकराव एक स्वाभाविक स्थिति होगी।

पानी तो सबको चाहिए और वह मिल भी रहा है, लेकिन उसकी शुद्धता और उसमें पोषक तत्त्व की मौजूदगी की परवाह किसी को नहीं है। हम प्रकृति की निर्मम हत्या करके स्वयं को बलिष्ठ समझने लगे हैं। नदियों के रास्ते में बने घने जंगलों को हमने उजाड़ना शुरू कर दिया है। विकास के बहाने से हमने नदियों का पानी स्वयं से ही दूर कर लिया है। हमारी निर्दयता देखकर नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं। नदियों में जब भी तेज बहाव होता है, तब पानी गांव, खेतों और घरों में घुस जाता है। शहरों की सड़कों में पानी की निकासी के पर्याप्त प्रबंध न होने से पानी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। बाद में जब बाढ़ का पानी उतरता है तो पीछे रह जाते हैं छोटे-बड़े पत्थर, गटमैला, काला और गहरा गाद, सूखे-गीले कांटों का जमावड़ा और साथ ही ठहरे हुए पानी से जन्म लेने वाली बीमारियां।

हमने पानी को केवल उपभोग की वस्तु मानना प्रारंभ कर दिया है। यह जानते हुए भी कि पानी हमारे जीवन का आधार है, हम उसकी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक जमाना था जब पानी की संस्कृति हमारे दिलों और घरों में मौजूद थी। हमारी प्राचीन सभ्यता की ओर मुड़ कर देखें तो हम पाते हैं कि हमारी संस्कृति को पानी ने ही पाला-पोसा है। पहाड़ों से शुरू होने वाला कलकल पानी पतली और अलग-अलग धाराओं के रूप में जंगलों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से निकलते हुए नदियों के रूप में बहता हुआ जल सागर में समाता देखकर हमें सुकून मिलता था। यह पानी ही बताता है कि निरंतर चलते रहना ही जीवन है।

दुनिया मेरे आगे

> समुद्र का विशाल रूप हमें सीख देता है कि हमारा जीवन दुख-सुख, आशा-निराशा, उतार-चढ़ाव का अद्भुत संगम है। बहते पानी को रोकने के लिए किए जाने वाले षड्यंत्रों की ही तरह ढेर सारे लोग हमारे जीवन की सुचारु गति में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ईर्ष्या करते हैं। हमारा अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास करते हैं।

समुद्र का विशाल रूप हमें सीख देता है कि हमारा जीवन दुख-सुख, आशा-निराशा, उतार-चढ़ाव का अद्भुत संगम है। बहते पानी को रोकने के लिए किए जाने वाले षड्यंत्रों की ही तरह ढेर सारे लोग हमारे जीवन की सुचारु गति में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ईर्ष्या करते हैं। हमारा अस्तित्व समाप्त करने का प्रयास करते हैं। हमें पनपने देना नहीं चाहते। साथ ही इसके विपरीत कुछ लोग जो संख्या में भले ही कम हों, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग करते हैं। वे हर पल हमारा साथ निभाते हैं। दुआएं देते हैं। हौसला प्रदान करते हैं। हमारी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें पता है कि समुद्र सभी नदियों, नालों को उनसे उनका उद्गम स्थल, रंग-रूप, उनकी कमियां पूछे बगैर अपने भीतर समेट लेता है। पानी के साथ बहकर आ रही प्रत्येक वस्तु को भी वह अपने तल में पनाह दे देता है। यही समुद्र हमें भी ज्ञान प्रदान करते हुए सीख देता है। वह चाहता है कि हम भी मिलने वाले स्नेह, हर्ष और घृणा को अपने हृदय में बसा कर रख लें तो बेहतर है। अन्यथा जो हमने बाहर छोड़ दिया, वह कीचड़ बनकर हमेशा हमें सालता रहेगा। जिस तरह से पानी का कोई रंग नहीं होता, ठीक उसी तरह हमें भी हमेशा सादा रहना आना चाहिए।

मतदान की कसौटी

चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, जिन्हें निष्पक्ष तरीके से कराना बहुत जरूरी है। अगर चुनावों में निष्पक्षता नहीं होगी तो लोकतंत्र को सीधे तौर पर नुकसान होगा। मगर चुनावी मौसम के आते ही अलग-अलग दल के लोग चुनाव जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं। निष्पक्षता या ईमानदारी से इनका कोई वास्ता नहीं होता है, जबकि राजनीति में नैतिक मूल्य होने बहुत जरूरी हैं, पर चुनावी दंगल में इसका उलटा होता है। कुछ क्षेत्रों में चुनावी प्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के बहुमूल्य वोटों को चंद पैसों और शराब से खरीद लेने के आरोप लगते हैं। अगर कभी ऐसा होता है तो इसका भुगतान मतदाताओं को ही करना पड़ता है। मतदाताओं को कुछ सवालों पर सोचना जरूरी है, जिससे तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग मतदान करने से पहले पूरी समझदारी और सब बातों का अवलोकन करके निर्णय करते हैं? क्या मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर वोट करते हैं? अपने क्षेत्र और राज्य की हालत बदलने के विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं, चिंताओं को समझे और उनके हितों का ध्यान रखे।

- सौरभ कांत, दिल्ली

उपेक्षित किसान

अवरोध की सीमा' (संपादकीय, 24 अगस्त) पढ़ा। इसमें उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को संयुक्त समिति गठित करने और चर्चा से शंभू सीमा को खोलने पर सहमति बनाने को कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी केंद्र और राज्य कोई सार्थक हल नहीं निकाल सके। शंभू सीमा पर अवरोध जारी होने से आम लोग तथा लंबित मांगों से किसान परेशान हैं। टालमटोल करने के बजाय किसानों की मांगों पर केंद्र को सम्मानजनक हल खोजना होगा, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि पहले जैसी स्थिति निर्मित नहीं हो जाए, क्योंकि किसान भी पुराने वादे को पूरा करने की मांग पर अड़े हैं। अब केंद्र सरकार ने किसानों की मांग पर विचार करते हुए सात फैसले लिए हैं, लेकिन देखना होगा कि ये जमीन पर कितने उतरते हैं।

- बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

विचित्र प्रवृत्ति

'जानलेवा शौक' (संपादकीय, 27 अगस्त) पढ़ा। मोबाइल जब आया होगा तो शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी कि संचार का यह साधन एक दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए नुकसानदायक, यहां तक कि जानलेवा भी साबित होने लगेगा। मोबाइल से सेल्फी लेना एक आदत-सी हो गई है, फिर हम यह भी नहीं देखते कि कहां खड़े युवाओं में तो इसका जुनून होता चला जा रहा है। जोखिम भरी जगहों में सेल्फी खिंचवाते हुए मौत के मुंह चले जाना अब पूरी दुनिया में दुर्घटनाओं का एक नया चलन बन चुका है। कहीं चलती ट्रेन के सामने खड़े होकर, तो कहीं पहाड़ों पर, तो कहीं नदियों में, झरनों के बिल्कुल पास जाकर लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं और कई बार जान पर बन आती है। मोबाइल फोन बातचीत करने का साधन रहे तो इससे अच्छा कुछ नहीं। हमें इसके दुरुपयोग से बचना होगा। सेल्फी लेने का शौक बड़े नुकसान का वाहक बन रहा है।

- साजिद अली, बंधन नगर, इंदौर

विकृत मानस

देश में बढ़ती अमानवीय घटनाएं डर का माहौल पैदा कर रही हैं जो आने वाले समय के लिए घातक साबित होंगी। हाल ही में वयस्क से लेकर कम उम्र की बच्चियों तक से बलात्कार की कई खबरें आईं। हालांकि इस तरह की घटनाएं अक्सर ही होती रहती हैं, मगर किसी घटना के तूल पकड़ लेने के बाद समाज और सरकार के लिए यह चिंता का विषय बनती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति एक सभ्य मानव समाज के लिए बेहद अफसोस की बात है। ऐसे लोग किस दिशा की ओर जा रहे हैं। मासूमों के साथ हैवानियत या आपराधिक हरकत करने वाले लोग हमारे बीच के होते हैं। समझना मुश्किल है कि ऐसी विकृति से ग्रस्त लोगों की मानसिकता कैसे बनती है। लोगों को अपने आसपास के ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों को कानून के हवाले कराने में पुलिस के मददगार की भूमिका निभानी चाहिए।

- पलक त्रिवेदी, गिरिजा बाग, उन्नाव

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

दिखने लगे महंगाई घटने के आसार

देश में बारिश कुल मिलाकर अच्छी है और अच्छी उपज के भी संकेत मिलने लगे हैं। इस बार एक भरपूर खरीफ फसल महंगाई की मार को कम कर सकती है। हालांकि, निर्यात-आयात के संतुलन को भी सुधारना होगा, ताकि उपभोक्ताओं के साथ किसान भी फायदे में रहें। पेश है, जरूरी उपज की पड़ताल करती सायंतन बेरा की रिपोर्ट...

किसानों को उपज के वाजिब दाम मिले

किसानों को फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। दो साल पहले बासमती (बिना कूटा हुआ धान) 3,800 रुपये से 4,200 रुपये प्रति क्विंटल बिका था। पांच महीने पहले, (थोक) कीमतें लगभग 3,200 रुपये प्रति क्विंटल थीं। अभी फसल कटने में डेढ़ महीने से ज्यादा का समय बचा है, पर कीमतें पहले ही गिरकर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के करीब आ गई है। उपज ज्यादा हो, तो किसानों को लाभ होना चाहिए।

कृषि विकास की लौटनी चाहिए रफ्तार

30 अगस्त को जारी भारत के नवीनतम जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल-जून तिमाही में कृषि क्षेत्र में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले की अवधि में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि से कम है। इस वर्ष अच्छी खरीफ फसल से कृषि विकास दर के पुनर्जीवित होने की उम्मीद है। इस बार कृषि विकास दर अगर ठीक रही, तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

चावल के बारे में ज्यादा सोचना होगा

2022 और 2023 में, असमान बारिश और कम फसल के बाद चावल पर कई प्रतिबंध लगाए गए और आज तक जारी है। सरकार ने प्रीमियम बासमती चावल पर 950 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया, सफेद और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और उबले चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया। यह सोचना होगा कि दुनिया को भारत से चावल चाहिए, पर हम कितना दे सकते हैं?

आनंद प्रकाश नाम के यह शख्स पिछले दिनों से छत पर खेती में हाथ आजमा रहे है। वह गाजियाबाद में रहते हैं, पेशे से ड्राइवर हैं, किसान नहीं। उनके लिए छत पर खेती का सीधा सा मतलब है, अपनी छत पर सब्जियां और पत्तेदार सब्जियां उगाना।

आनंद प्रकाश चिंतित रहते हैं। चुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है, अकेले अरहर दाल की कीमतें दो वर्षों में 60 प्रतिशत बढ़ गई है। प्रकाश कहते हैं कि उन्हें अपना भोजन खुद उगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वह बताते हैं, 'हमें अपने आहार में दालों और सब्जियों जैसी पौष्टिक चीजों की मात्रा कम करनी पड़ी है। हम कभी भी केला नहीं खरीदते है और कभी-कभार मिलने वाले केले के अलावा कोई फल खरीद भी नहीं सकते। मैं भाग्यशाली हूं कि किसी ने मुझे एक गाय उपहार में दी, कम से कम घर में दूध तो है। भोजन पर खर्च करने और निजी शिक्षा (दो बच्चों की) के लिए भुगतान करने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता है।'

लाखों भारतीयों ने हाल के वर्षों में खुद को संकट में पाया है और भोजन जुटाने के लिए तरह-तरह से बचत करना उनकी मजबूरी है।

पिछले महीने जारी एक शोध पत्र में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 2020 (जून 2020 से जून 2024) के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 6.3 प्रतिशत थी, जबकि 2016 और 2020 के बीच यह केवल 2.9 प्रतिशत थी। इसमें कहा गया है कि प्रतिकूल जलवायु के बाद आपूर्ति को झटका लगा है। केंद्रीय बैंक ने चेतावनी दी है कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति स्थानिक समस्या बन गई है।

जहां उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, वहीं किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि फसल की ऊंची कीमतें, चाहे वह दालों, सब्जियों या अनाज की हों, अक्सर जलवायु संबंधी कमी की वजह से होती हैं। वास्तव में, अनाज पर निर्यात प्रतिबंध और तिलहन के शुल्क मुक्त आयात जैसी व्यापार नीतियों ने कृषि आय पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

कुशल प्रबंधक और एक कंपनी के कार्यकारी आनंद चंद्रा कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, असमान बारिश के कारण खरीफ (ग्रीष्मकालीन फसल) का उत्पादन ही सबसे अधिक जोखिम भरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सितंबर में बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसमें लंबी अवधि या 50 साल के औसत से 109 प्रतिशत से अधिक बारिश की उम्मीद है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर-पश्चिम व उत्तरी राज्यों में ज्यादा बारिश की उम्मीद है। आईएमडी ने 31 अगस्त को कहा कि ला नीना स्थितियां - भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का सामान्य से अधिक ठंडा तापमान, जो भारत में ज्यादा बारिश लाता है - सितंबर के अंत तक बनने या विकसित होने की संभावना है।

अक्तूबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान सितंबर के अंत में जारी किया जाएगा, जब खरीफ की कटाई शुरू होगी। फिलहाल, पूर्वानुमान अनिश्चित है। जून में बारिश में 11 प्रतिशत की कमी के बाद, मानसून जुलाई में 9 प्रतिशत और अगस्त में 16 प्रतिशत अधिक बारिश लेकर आया। थोड़े ही समय में हुई तेज बारिश से कई शहरों के हिस्से डूब गए, कई राज्यों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ और कुछ में भीषण बाढ़ आ गई।

हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि बारिश ने कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित कर दिया है, अब तक खरीफ फसलों को व्यापक नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 23 अगस्त तक, 10. 65 करोड़ हेक्टेयर में खरीफ की बुआई पूरी हो चुकी थी, जो पिछले पांच वर्षों के औसत 10.95 लाख हेक्टेयर के करीब है।

जून-अक्तूबर खरीफ सीजन के दौरान, किसान अनाज, दालें, तिलहन, साथ ही गन्ना और कपास जैसी फसलें उगाते हैं। इस वर्ष, चावल और दालों की बुआई 2023 के स्तर को पार कर गई है और तिलहन व गन्ने की बुआई लगभग बराबर है। गेहूं को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी चीजों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

मध्य प्रदेश के विदिशा के 32 वर्षीय किसान अमित रघुवंशी, लगभग 100 एकड़ पारिवारिक भूमि का प्रबंधन करते हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि इस साल बारिश भरपूर हुई है, पर फसल की कीमतों में गिरावट की संभावना उनके मुनाफे को कम कर देगी। तीन साल पहले तक, क्षेत्र के अधिकांश अन्य किसानों की तरह, रघुवंशी भी सोयाबीन उगाते थे, जो एक व्यावसायिक फसल है, पर नियमित रूप से भारी बारिश से सोया की फसल प्रभावित हुई, इसलिए क्षेत्र के किसानों ने चावल की प्रीमियम किस्मों की ओर रुख किया। चावल उगाना एक तर्कसंगत विकल्प प्रतीत होता है, क्योंकि सुनिश्चित सरकारी खरीद एक न्यूनतम मूल्य स्थापित करती है। भरपूर फसल वाले वर्ष में भी कीमतें आमतौर पर तय मूल्य से नीचे नहीं गिरती हैं। चावल समय-समय पर होने वाली भारी बारिश को सहन कर सकता है और अधिक उपज दे सकता है। इसकी तुलना में, सोयाबीन एक कम उपज देने वाली फसल है और इसकी कीमतें लंबे समय से सुस्त बनी हुई हैं, जिसका मुख्य कारण सस्ते आयातित तेलों की आमद है। वर्तमान में, थोक सोयाबीन की कीमतें एक दशक पहले देखे गए स्तर के करीब हैं।

किसान और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। किसान समूह अक्सर शिकायत करते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों से उनकी संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसका एक उदाहरण तिलहन है, पिछले दो वर्षों में वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कम कीमतों ने भारतीय उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब कई महीनों से, खाद्य तेलों में मुद्रास्फीति नकारात्मक रही है।

तिलहन के अलावा, भारत में दालों का आयात बढ़ रहा है। 2022 और 2023 में कम उत्पादन के कारण, भारत का दाल आयात बिल 2023-24 में सात साल के उच्चतम 3.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसलिए, इस साल का खरीफ उत्पादन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से दालों की मुद्रास्फीति लगातार दोहरे अंक में बनी हुई है। जुलाई में दालों की कीमतें पिछले साल की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक थीं। इस बार दाल की कीमतें नरम होने की संभावना है, क्योंकि घरेलू उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है।

केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में तब तक कमी करने की संभावना नहीं है, जब तक कि खाद्य पदार्थों की कीमतें काफी कम न हो जाएं। फिलहाल, सारी उम्मीदें भरपूर खरीफ फसल पर टिकी हैं।

mint

अभी कीमतें कुछ बेलगाम

बार-बार मौसम के खराब होने या फसल के प्रतिकूल होने की वजह से भी खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊपर-नीचे होती रहती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का भी यही कहना है।

(खाद्य मुद्रास्फीति प्रतिशत में)

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

जरूरी सामान ने किया परेशान

पिछले कुछ महीनों से दालों और सब्जियों की ज्यादा कीमत से बहुत लोगों को परेशानी हुई है। अनेक लोगों ने अपनी खपत या खर्च में कटौती की है।

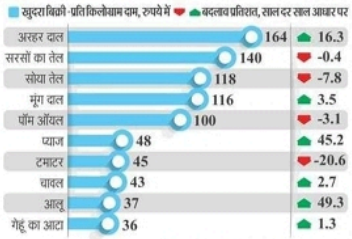

(31 अगस्त तक के आंकड़े। स्रोत - उपभोक्ता मामले विभाग

बेहतर दिन आने वाले हैं?

खेतों में इस बार बड़े पैमाने पर फसल उगाई गई है, अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई घटने की संभावना है।

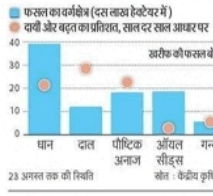

23 अगस्त तक की स्थिति
स्रोत : केंद्रीय कृषि मंत्रालय

राहत का संदेशा लाते बादल

देश के अनेक इलाकों में पर्याप्त से ज्यादा बारिश हुई है, इससे पैदावार बढ़ने की संभावना है।

बारिश का पचास साल का औसत ठीक रहा है और इस साल भी स्थिति ठीक है। (आंकड़े प्रतिशत में)

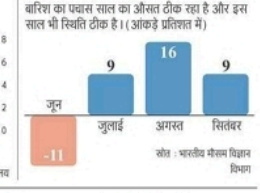

स्रोत : भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

60% बढ़ी अरहर दाल की कीमत दो वर्ष में | **28%** घटी विश्व में वनस्पति तेल की कीमत | **13%** से ज्यादा बढ़ी चावल की कीमत

> भारत के वैश्विक बाजारों से हटने से पैदा हुई कमी को अन्य चावल उत्पादक देशों ने भर दिया है, जिससे एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अब समय आ गया है कि सरकार इन प्रतिबंधों में ढील दे। इससे किसानों को फायदा होगा। बाजार में पर्याप्त स्टॉक या भंडार है और अगर प्रतिबंध नहीं हटाए गए, तो कीमतों में और गिरावट आएगी।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। लाभ के मौके मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

वृष : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। संयत रहें। बातचीत में संतुलित रहें। सेहत के प्रति सचेत रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। कठिनाई आ सकती है।

मिथुन : आत्म संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। वाणी के प्रभाव से कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से लाभ में वृद्धि होगी।

कर्क : मन अशांत रहेगा। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं।

सिंह : मन में शांति व प्रसन्नता का भाव रहेगा। आत्म विश्वास भी भरपूर रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पिता की सेहत का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कन्या : मन अशांत रहेगा। संयत रहें। धैर्य बनाए रखें। धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। आय में कमी व खर्च अधिक की स्थिति हो सकती है। आत्मविश्वास मिल सकता है।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में बदलाव की संभावना। पिता से धन प्राप्ति होगी।

वृश्चिक : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय के साधन बन सकते हैं। बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

धनु : मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। कारोबार में भी कठिनाई आ सकती है।

मकर : मन परेशान रहेगा। आत्म संयत रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय रहेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्च में वृद्धि होगी।

कुंभ : आत्म संयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। कारोबार के प्रति सचेत रहें। लाभ में कमी भी आ सकती है।

मीन : किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा पर जाने का योग। खर्चों में वृद्धि होगी।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

वर्ग पहेली : 7715

बाएं से दाएं
1. विनय सहित; विनीत भाव से (4)
3. विमान चालक; विमान संबंधी; (4)
7. घोर संकट आना; सहसा विपत्ति आना (4,2,3)
9. अस्थायी बाजार; कसबाती बाजार; साप्ताहिक बाजार; स्थानीय बाजार; दुकान (2)
10. नतीजा; लाभ; पेड़-पौधों से प्राप्त खाद्य (2)
12. गुट; समूह (2)
15. भूखा मारना; भोजन न पा सकने देना; ललचाना; लाचार कर देना; बहुत कष्ट देना (2,2,1,4)
16. कड़ापन; कर्कशता; सख्ती; निर्दयता (4)
17. कपड़ा बुनने वाला; बुनाई कर्मी (4)

ऊपर से नीचे
2. उन्नति का समय; प्रसार काल; वर्सत काल (5)
4. किसी के सत्कार्यों, सद्गुणों आदि की स्तुति करते हुए दिया जाने वाला पत्र; अभिनंदनपत्र (4)
5. कल्पना करने वाला; रचनाशील (5)
6. अखंडित; दृढ़; न टूटने वाला; मजबूत (3)
8. बहती हुई धार के नीचे शरीर को स्वच्छ करना; स्नान करना (3)
10. जो फल दे; फल देने वाला; फलदायी; (5)
11. क्षमता; बल; शक्ति; सामर्थ्य (3)
12. दम साधने वाला; श्वास की गति रोकने वाला (2,3)
13. जो गदा धारण करे; गदापाणि; नारायण (4)
14. चतुर्भुजाकार; चार भुजाओं वाला (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 7714

सुडोकू : 7698

* मध्यम

2						6		3
					1	8		
1	8		6		5			
	3	4		2		9		
			3		6			
		1		5		2	3	
			1		2		6	7
		2	8					
4		7						8

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7697

6	8	7	5	2	3	9	1	4
2	4	1	7	6	9	3	5	8
9	3	5	4	8	1	2	7	6
5	7	6	3	1	8	4	9	2
3	2	4	6	9	7	1	8	5
1	9	8	2	5	4	6	3	7
8	6	3	9	7	2	5	4	1
7	5	9	1	4	6	8	2	3
4	1	2	8	3	5	7	6	9

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

04 सितंबर, बुधवार, शक संवत्: 13 भाद्रपद (सौर) 1946, पंजाब पंचांग: 20 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2081, इस्लाम: 29 सफर सन् 1446, विक्रमी संवत्: भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा प्रातः 09.47 बजे तक पश्चात द्वितीया तिथि, साध्य योग रात्रि 8.03 बजे तक, बव करण, चन्द्रमा सिंह राशि में प्रातः 09.56 बजे तक उपरांत कन्या राशि सूर्य दक्षिणायन। सूर्य उत्तर गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक राहुकालम्। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पारंभ। चंद्रदर्शन।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

मैंने एक होटल बनवाया है। पर, मेरे कर्मचारी मुझ पर हावी रहते हैं। कृपया कोई उपाय बताएं।
मुकेश चोपड़ा, दिल्ली

- होटल के नक्शे के अनुसार होटल दक्षिण मुखी है, जिसमें आपने अपना ऑफिस ईशान कोण में बनाया है जो कि मालिक होने के नाते आपके लिए गलत है। संभव हो तो अपना ऑफिस दक्षिण दिशा में बना लें।
- ऑफिस की दक्षिणी दीवार पर ऊंची बिल्डिंगों का चित्र लगाएं। उत्तर पश्चिम में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्रीकृष्ण का चित्र लगाएं। ऑफिस की पूर्व दिशा में एक खिड़की में पारदर्शी शीशा हो। खिड़की पर सफेद रंग की क्रिस्टल बॉल लटकाएं।